चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 05 अक्टूबर-11 अक्टूबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव

राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

भारतीय राजनीति में बिहार का चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है. लेकिन इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से कुछ अलग है. यह हाल के दिनों हुए या होने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा पेचीदा और महत्वपूर्ण है. पेचीदा इसलिए, क्योंकि हर पार्टी आंतरिक कलह और अंतर्विरोध से जूझ रही है. हर पार्टी में स्थानीय नेताओं के रूठने-मनाने की प्रक्रिया के मतदान तक जारी रहने की उम्मीद है. जातीय समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण का असर इस बार कैसा और कितना होगा यह किसी को पता नहीं है. जनता किस मुद्दे को प्राथमिकता देगी यह कहना भी मुश्किल है. दल-बदलू उम्मीदवारों की भीड़ लगी है. जनता जाति, धर्म, विचारधारा, उम्मीदवार या मुद्दे पर वोट देगी फिलहाल इसका आंकलन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समर्पित वोटरों को छोड़कर आम मतदाता शांत है. वर्तमान में बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि बड़े-बड़े विश्लेषक भी उलझन में हैं. यह उलझन इसलिए भी है क्योंकि बिहार का यह चुनाव भारत की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इसके नतीजे से राष्ट्रीय राजनीतिक की दिशा और दशा तय होगी. इस चुनाव के नतीजे का असर मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा होगा और वह उसकी योजनाओं और नीतियों में दिखाई देगा. इस चुनाव में उत्तर भारत में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों की साख दांव पर है. यह चुनाव सेकुलर और गैर-सेकुलर पार्टियों के बीच वाटर-लू की लड़ाई है. इसलिए, बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल सभी दल काफी तैयारी और ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में हैं. सभी पार्टियों ने अपनी सारी ताकत और साधन इस चुनाव में झोंक दिये हैं, क्योंकि हर पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है. यह समझना भी जरूरी है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए बिहार चुनाव के क्या मायने हैं? इसके नतीजों का अलग-अलग पार्टियों पर क्या असर होगा?

मनीष कुमार

भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरह से तूफान से पहले की शांति है. कई वरिष्ठ नेता और मंत्री हाशिए पर हैं. पार्टी के फैसलों में उनकी हिस्सेदारी न के बराबर हो गई है. मोदी और अमित शाह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे में रोष है. इन नेताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पार्टी पर कब्जा हो गया है. पार्टी में संवादहीनता का माहौल है. पिछले कुछ महीनों में कई नेताओं ने पार्टी के आंतरिक-क्रियाकलापों पर नकारात्मक टिप्पणी भी की लेकिन उन्हें पार्टी के अंदर ही दबा दिया गया. बिहार चुनाव के नतीजों का सीधा असर भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पर होगा. इसके दो कारण हैं. पहला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अमित शाह ने बिहार चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. चुनाव से जुड़े सारे फैसले अमित शाह और उनके सहयोगी ले रहे हैं. अमित शाह को इस बात का आभास है कि बिहार में चुनाव हारने के साथ ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगेंगे. कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों और पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाने लगेंगे. नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिलने लगेगी. अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं. आंतरिक कलह कहीं सार्वजनिक न हो जाए, इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई. नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने का फैसला उनकी लोकप्रियता के साथ-साथ पार्टी में चल रहे घमासान को दबाने की भी मजबूरी है. भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह की हालत ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बिहार चुनाव में जीत दर्ज करना अवश्यंभावी हो गया है. यदि भाजपा बिहार चुनाव जीत जाती है तो पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध के स्वर कुछ समय के लिए दब जायेंगे. विरोधी खेमे को उत्तर प्रदेश चुनाव तक इंतजार करना होगा. यदि भाजपा हार जाती है तो हार का ठीकरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिर पर फूटेगा. ऐसे में विरोधी खेमा खुलकर सामने आ जाएगा और पार्टी संगठन के साथ-साथ मंत्रिमंडल में बदलाव की मुहिम तेज़ हो जाएगी.

बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है. लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद, उनके पास अपने मनमुताबिक फैसलों को संसद में पास कराने लायक संख्या बल राज्यसभा में नहीं है. भाजपा को यदि राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ानी है तो उसके लिए बिहार जैसे बड़े राज्यों के चुनाव जीतना जरूरी है. वर्तमान में मोदी सरकार विपक्ष

बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है. लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद, उनके पास अपने मनमुताबिक फैसलों को संसद में पास कराने लायक संख्या बल राज्यसभा में नहीं है. भाजपा को यदि राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ानी है तो उसके लिए बिहार जैसे बड़े राज्यों के चुनाव जीतना जरूरी है. वर्तमान में मोदी सरकार विपक्ष की सहायता के बगैर कोई भी क़ानून संसद में पास नहीं करवा सकती है. भूमि-अधिग्रहण क़ानून इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा.

की सहायता के बगैर कोई भी क़ानून संसद में पास नहीं करवा सकती है. भूमि-अधिग्रहण क़ानून इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा. बिहार चुनाव के नतीजे मोदी सरकार के फैसले लेने की शक्ति पर भी असर डालेंगे. जिस तरह के नव-उदारवादी नीतियों को मोदी सरकार लागू करना चाहती है, उसके लिए कई कड़े फैसले लेने की जरूरत है. जन-समर्थन के आभाव में कोई भी सरकार ऐसे फैसले नहीं ले सकती. यही वजह है कि बाजार और निवेशक भी बिहार चुनाव की ओर देख रहे हैं. भाजपा की जीत से बाजार और निवेशकों का नरेंद्र मोदी सरकार पर विश्वास बढ़ेगा, वहीं बिहार में हार का मतलब नव-उदारवादी नीतियों पर लगाम लगना होगा. लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बिहार विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि दोनों बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. इस चुनाव से भाजपा में यह फैसला भी होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का पार्टी में वर्चस्व रहेगा या नहीं.

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह बिहार चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी जीवन-मरण का सवाल है. पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े और मुख्यमंत्री बने. जदयू और बीजेपी गठबंधन की जीत ऐतिहासिक थी. लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने भाजपा से रिश्ता तोड़कर अपने राजनीतिक जीवन का सबसे अहम और साहसिक फैसला लिया. 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के पास यह सिद्ध करने का आखिरी मौक़ा है कि उनका भाजपा से अलग होने का फैसला सही था. राजनीतिक स्तर पर भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार ने स्वयं की राजनीति और पार्टी के भविष्य को दांव पर लगा दिया था. लोकसभा चुनाव में जनता का फैसला नीतीश के पक्ष में नहीं था. जदयू के अंदर कई लोगों को यह लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला सही नहीं था. लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ और भाजपा के एग्रेसिव कैंपेन की वजह से नीतीश कुमार को मनमाफिक परिणाम नहीं मिले. इस वजह से नीतीश कुमार को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है. लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की कवायद है. बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला होना है. इस चुनाव में नीतीश कुमार के शासनकाल के क्रियाकलापों, उनके सुशासन मॉडल और उपलब्धियों पर जनता अपना फैसला सुनाएगी. इसलिए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जातीय चाशनी में सराबोर बिहार का चुनावी संग्राम | P-3

चुनौती सबके लिए है सत्ता बचाने की, सत्ता पाने की | P-4

सबके निशाने पर माय विकास के सपने पर जाति का सच भारी | P-5

बिहार विधानसभा चुनाव

राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है

पृष्ठ 1 का शेष

नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव जीतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पहले भाजपा के खिलाफ देशव्यापी गठबंधन यानी जनता परिवार बनाने की कोशिश की. अपने अहम को दरकिनार कर उन्होंने अपने धुरविरोधी लालू यादव से हाथ मिलाया, ताकि भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सके. नीतीश कुमार के लिए खुशी की बात यह है कि अब तक जितने भी चुनावी सर्वे हुए हैं, उनमें वह मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं. मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार की जनता की पहली पसंद हैं. भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर इस चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार में तब्दील कर दिया है. यह नीतीश कुमार के लिए चुनौती के साथ-साथ एक अवसर भी है. अगर नीतीश कुमार भाजपा को हराकर फिर से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो वह नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले देश के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे. 2019 के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा विरोधी खेमे के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर उभर सकते हैं. यदि वह विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ेगा. जदयू के कई नेता भाजपा से अलग होने के फैसले से सहमत नहीं थे लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके भरोसे की वजह से वे शांत रहे और उनका साथ दिया. बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये सारे नेता खुलकर सामने आ जाएंगे. कहने का मतलब यह कि नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है. बिहार चुनाव जीतने के साथ ही वह राष्ट्रीय राजनीति की प्रथम पंक्ति के अहम नेता बन जाएंगे, लेकिन हारने के बाद उनका कद एक ऐसे असरहीन क्षेत्रीय नेता का हो जायेगा, जिसकी आवाज केंद्र सरकार के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव के लिए संजीवनी का काम कर सकता है. 15 साल तक बिहार में एकछत्र राज करने वाले लालू यादव पिछले कई चुनावों से लगातार कमजोर होते जा रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में तो वह इतनी भी सीटें नहीं जीत सके, जिससे कि वह नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी पेश कर पाते. पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल मात्र 24 सीट जीत सका था. यहां यह समझना जरूरी है कि लालू यादव भले ही चुनाव में सीटें जीतने में पीछे जरूर थे, लेकिन जहां तक वोट का सवाल है तो लालू यादव का आधार वोट जो बैंक है, वह अभी तक लालू यादव के साथ है. कई सीटों पर हार का अंतर बहुत ही कम था. लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा. बिहार की आम जनता को लगता है कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए बहुत हद तक लालू यादव

जिम्मेदार हैं. लालू यादव और नीतीश कुमार के एक साथ होने का सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव को होगा. नीतीश कुमार के कुशल प्रशासन की वजह से लालू यादव के कुशासन का मुद्दा पीछे छूट गया है. दूसरी बात यह कि जिन विधानसभा सीटों पर हार का अंतर कम था. उन सीटों पर नीतीश कुमार के समर्थकों की मदद से वह जीतने में कामयाब हो सकते हैं. लालू यादव फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं इसलिए जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक यह कहा जा सकता है कि वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं हैं. लालू यादव के लिए बिहार चुनाव अस्तित्व का सवाल नहीं है. लालू यादव पिछले एक दशक से राजनीतिक तौर पर कमजोर जरूर हुए हैं लेकिन बिहार में उनकी पार्टी और समर्थन बरकरार है. महा-गठबंधन की जीत का मतलब लालू यादव के हाथ में सत्ता की चाभी होना और हार का मतलब, पिछले दस साल के नतीजों का दोहराव होना. जब तक लालू यादव राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं तब तक उनकी पार्टी बिहार की राजनीति के केंद्र में बनी रहेगी. चुनाव में जीत या हार का असर लालू यादव पर सबसे कम पड़ने वाला है.

कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी. बिहार में कई दशकों तक कांग्रेस का एकछत्र राज रहा. आज कांग्रेस की हालत यह है कि उसके पास प्रदेश में 243 में से सिर्फ 4 विधायक हैं, जबकि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में तूफानी प्रचार किया था. बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व ख़तरे में है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिली है. महा-गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली हैं जो कि आश्चर्यजनक है. यदि सही ढंग से उम्मीदवारों का चयन और चुनाव प्रबंधन हो तो कांग्रेस पार्टी इन चालीस सीटों की बदौलत बिहार में अपनी जड़ें जमा सकती है. कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि पार्टी के पास कोई सुदृढ़ वोट बैंक नहीं है. राहुल गांधी ने बिहार के हर जिले में संगठन तो तैयार किया लेकिन युवा नेताओं को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए. बिहार में संगठन की स्थिति ढुलमुल है. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस चुनाव के माध्यम से क्या कांग्रेस पार्टी खुद को बिहार की राजनीति में फिर से प्रासंगिक बनाने में कामयाब होगी या नहीं. बिहार में हार राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका साबित होगी. इसके बाद मोदी को चुनौती देने वाले नेताओं की लिस्ट में वह और भी पीछे चले जाएंगे.

वैचारिक तौर पर बिहार चुनाव में एक ऐतिहासिक घटना हुई है लेकिन इस घटना पर मीडिया की नजरें नहीं गईं हैं. पहली बार देश की सारी महत्वपूर्ण वामपंथी पार्टियों ने एक गठजोड़ बनाया है. बिहार चुनाव में देश के सभी (छह) वामदल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. वैचारिक रूप से ये वामदल आपस में एक-दूसरे के प्रतियोगी रहे हैं. बिहार में वामपंथी आंदोलन का एक इतिहास रहा है. बिहार के कई इलाकों में वामपंथी पार्टियों के समर्थक हैं. बिहार में सीपीआई (माले) इस गंठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है. वह विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती आई है और सीटें भी जीतती रही है. सवाल है, बिहार में वामपंथियों के एकजुट होने के क्या कारण हैं? वैचारिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था अब नव-उदारवादी नीतियों के तहत दुनिया भर में स्थापित की जा रही है. भारत में नव-उदारवादी नीतियां लागू हों उसके पीछे भी वैश्विक पूंजीवादी शक्तियों का हाथ है. नव-उदारवादी व्यवस्था गरीब किसान और मजदूरों के हितों के खिलाफ है. सरकार से लेकर मीडिया और गैर-सरकारी संस्था हर तरफ नव-उदारवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाली ताकतों को प्राथमिकता मिल रही है. नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष अगल-थलग रहकर नहीं किया जा सकता है. नव-उदारवाद से लड़ने का मतलब सर्वशक्तिमान वैश्विक ताकतों से लड़ना है. इससे लड़ना किसी एक पार्टी के वश की बात नहीं है. यही वजह है कि देश के वामपंथी पार्टियों को वाम-एकता की जरूरत पड़ी है. राजनीतिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में वाममोर्चा की हार के बाद से भारतीय राजनीति से वामपंथ हाशिये पर चला गया है. धीरे-धीरे यह अप्रासंगिक होता जा रहा है. अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने की मजबूरी ने वामपंथी पार्टियों को एकजुट कर दिया है. बिहार में पहली बार यह प्रयोग हो रहा है. इसलिए यह जरूरी है कि वाममोर्चा का प्रदर्शन बेहतर हो. इस प्रयोग की सफलता के लिए वोट के साथ-साथ वाममोर्चा को 5 से 10 सीटें जीतनी होंगी. वाममोर्चा अगर ऐसा कर पाता है तो उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, अन्यथा भारतीय राजनीति की मुख्यधारा से अलग-थलग हो रहा वामपंथ और भी हाशिये पर चला जाएगा.

बिहार में एक और मोर्चा अपनी किस्मत आज़मा रहा है. इस मोर्चे में कुल छह पार्टियां हैं. इसमें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, शरद यादव की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, पी ए सांगमा की नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी, नागमणि की समरस समाज पार्टी और देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता पार्टी शामिल है. यह गठबंधन दरअसल नाराज नेताओं का गठबंधन है. समाजवादी पार्टी कुछ दिन पहले तक जनता परिवार में शामिल थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार से मनमुटाव हुआ और मुलायम सिंह ने अलग होने का फैसला ले लिया. समाजवादी पार्टी भले ही उत्तर प्रदेश में एक बहुमत वाली सरकार चला रही है, लेकिन बिहार में उनके पास न तो समर्थन है और न ही संगठन. वहीं, पप्पू यादव मधेपुरा और इसके आसपास के इलाकों में लोकप्रिय हैं, वह कुछ दिन पहले तक लालू यादव की पार्टी में थे. वह खुद को लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, लेकिन जबसे लालू यादव ने अपने बेटों को राजनीति में आगे किया, पप्पू यादव नाराज हो गए. शरद पवार की एनसीपी सीमांचल की एक लोकसभा की पार्टी है, जहां से तारिक अनवर चुनकर आते हैं. देवेंद्र प्रसाद यादव चार बार सासंद रह चुके हैं लेकिन, इस बार विधायक का टिकट नहीं मिलने पर वह जदयू से बाहर हो गए और मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ गए. कहने का मतलब, इन पार्टियों का बिहार में राज्यव्यापी जनाधार नहीं है लेकिन ये पार्टियां कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं. समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बने इस मोर्चे की चुनौती केवल इतनी है कि वह इस चुनाव के नतीजों को किन-किन इलाकों में कितना प्रभावित कर सकता है.

बिहार में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम चुनाव मैदान में है. उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाके की 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है. ओवैसी हैदराबाद से आते हैं और उनकी राजनीति मुसलमानों के विकास के इर्द-गिर्द घूमती है. वह भारत के मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं. अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे. वहां उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा. वह दो सीट जीतने में कामयाब भी हुए. ओवैसी यह जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बनने के लिए उन्हें उत्तर भारत के मुसलमानों का समर्थन मिलना जरूरी है. यही वजह है कि वह बिहार के चुनावी मैदान में कूदे हैं. वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे. यह खबर भी आ रही है कि मायावती के साथ गठबंधन करने की पहल हो चुकी है. लेकिन बिहार में वह अकेले ही लड़ रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी के सामने वैसी ही चुनौती है जैसी नीतीश कुमार की. असदुद्दीन ओवैसी जिस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की वजह से बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं उसका एकमात्र रास्ता सीटें जीतने से ही शुरू होता है. असदुद्दीन ओवैसी के लिए हर हाल में वोट के साथ-साथ 2 से 4 सीटें जीतना जरूरी है. यदि वह इसमें सफल होते हैं तो नतीजे आते ही देश की राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी. यदि वह सीटें नहीं जीत सके, तो उत्तर भारत में उनकी हैसियत एक वोट-कटवा पार्टी की हो जाएगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा.

इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार चुनाव का राष्ट्रीय महत्व है. इस चुनाव का नतीजा भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा. देश की सभी बड़ी पार्टियां के लिए यह चुनाव निर्णायक साबित होने वाला है. चुनाव के नतीजों का असर हर राजनीतिक दलों की आंतरिक-कार्यप्रणाली और सगंठन पर पड़ने वाला है. साथ ही इस चुनाव के नतीजों का सीधा असर संसद और केंद्र सरकार की नीतियों पर पड़ेगा. इसके अलावा इस चुनाव के नतीजों के बाद ही यह पता चलेगा कि देश की राजनीति बीजेपी और एंटी-बीजेपी खेमे में बंटेंगी या नहीं. इस चुनाव का असर भविष्य की गठबंधन राजनीति पर भी होगा. भारतीय राजनीति का यह अजीबोगरीब पहलू है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य की जनता, भारत की राजनीति के भविष्य को तय करने वाली है. यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि देश के सबसे गरीब, पिछड़े, बेरोज़गार, अशिक्षित और वंचित भारत का भविष्य तय करने वाले हैं. यही वजह है कि बिहार का विधानसभा चुनाव हर चुनाव की जननी है. ■

manishbph244@gmail.com

कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी. बिहार में कई दशकों तक कांग्रेस का एकछत्र राज रहा. आज कांग्रेस की हालत यह है कि उसके पास प्रदेश में 243 में से सिर्फ 4 विधायक हैं, जबकि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में तूफानी प्रचार किया था. बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व ख़तरे में है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिली है. महा-गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली हैं, जो कि आश्चर्यजनक है. यदि सही ढंग से उम्मीदवारों का चयन और चुनाव प्रबंधन हो तो कांग्रेस पार्टी बिहार में इन चालीस सीटों की बदौलत बिहार में अपनी जड़ें जमा सकती है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 31
दिल्ली, 05 अक्टूबर-11 अक्टूबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बिहार चुनाव विशेष

राज्य में वामपंथ का एक बड़ा आधार था. सोवियत संघ के ज़माने में बेगुसराय के क्षेत्र को पूरब का मास्को और चंपारण को लेनिनग्राद कहा जाता था.यदि पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो यह साफ़ हो जाएगा कि राज्य में वामपंथ का बड़ा आधार था, लेकिन चुनाव में किसी भी वामपंथी दल को कोई सीट नहीं मिली थी. यहां तक की 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए चल रही सहानुभूति लहर में भी वामपंथी पार्टियों को 13 सीटें मिली थीं. लेकिन साल 2000 के आते–आते राज्य में वामदलों का प्रदर्शन बद से बदतर होता चला गया.

बिहार विधानसभा चुनाव

वाम दलों के अस्तित्व की लड़ाई

शफीक आलम

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह है कि छह वाम दल गठबंधन करके पहली बार किसी चुनाव में एक साथ उतरे हैं. इस गठबंधन में भाकपा, माकपा, भाकपा (माले), फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया शामिल हैं. यह गठबंधन राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना रहा है. हालांकि, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य यह मानते हैं कि उनका लक्ष्य भाजपा को हराना है, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि लोग नीतीश और लालू से भी नाराज़ हैं. इसलिए जो लोग एनडीए या महा–गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते, वे वाम–गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देंगे. गौरतलब है कि इस चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महा–गठबंधन है जिसमें राजद, जद(यू) और कांग्रेस शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन. जिसमें भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) आदि पार्टियां शामिल हैं. यह माना जा रहा है की मुख्य मुक़ाबला इन्हीं दो गटबंधनों के बीच है. तीसरा मोर्चा, वाममोर्चा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को खेल बिगाड़ू के रूप में देखा जा रहा है. लेकिन जहां तक वाम मोर्चे का सवाल है तो दीपांकर भट्टाचार्य इस आशंका को सिरे से ख़ारिज करते हैं. वह कहते हैं कि वामदलों के महा–गठबंधन में शामिल नहीं होने का फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा. उनका मानना है कि नीतीश कुमार और भाजपा पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहे हैं और वामपंथी पार्टियां आम जनता के मुद्दों पर राज्य में संघर्ष करती रही हैं. यदि अब वे तथाकथित महा–गठबंधन में केवल भाजपा को रोकने के लिए शामिल हो जायें तो, इससे भाजपा को और अधिक मजबूती मिलेगी.

बहरहाल, यह तो समय ही बतायेगा कि चुनाव में वाममोर्चा किसे नुकसान पहुंचाता है और किसे फायदा. लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिहार के कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां इन दलों का एक आधार मौजूद है. इन्हीं जगहों पर वह महा–गठबंधन और एनडीए को न केवल नुक़सान पहुंचाने की स्थिति में है बल्कि चुनाव जीतने की स्थिति में भी है. बावजूद इसके राज्य के अधिकांश क्षत्रों में वामपंथी पार्टियां काफी कमजोर हैं और फ़िलहाल किसी गठबंधन को फायदा या नुक़सान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है. यदि बिहार विधान सभा चुनावों में वामपंथी पार्टियों के प्रदर्शन को देखा जाया तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि उनके एक साथ आने से किसी की तरह के उलटफेर की उम्मीद, केवल दिल बहलाने का ख्याल ही साबित होगी. पिछले चुनाव में केवल भाकपा एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी. अन्य वामदलों का खाता भी नहीं खुल पाया था.

लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है. राज्य में वामपंथ का एक बड़ा आधार था. सोवियत संघ के ज़माने में बेगुसराय के क्षेत्र को पूरब का मास्को और चंपारण को लेनिनग्राद कहा जाता था.यदि पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो यह साफ़ हो जाएगा कि राज्य में वामपंथ का बड़ा आधार था, लेकिन चुनाव में किसी भी वामपंथी दल को कोई सीट नहीं मिली थी. यहां तक की 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए चल रही सहानुभूति लहर में भी वामपंथी पार्टियों को 13 सीटें मिली थीं. लेकिन साल 2000 के आते–आते राज्य में वामदलों का प्रदर्शन बद से बदतर होता चला गया. अब ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है. वाम दलों के आधार में गिरावट पूरे देश में दर्ज की जा रही है. पश्चिम बंगाल जो कि उनका गढ़ था, वहां से ये ख़बरें आ रही हैं कि वाम दलों के कार्यकर्ता अब भाजपा का दामन थमने लगे हैं. लोकसभा चुनाव में वाम दलों को मिली करारी हार ने उन्हें एक साथ आने और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया. ध्यान रहे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद माकपा के महासचिव प्रकाश करात ने कहा था कि वाम दलों को केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए. वहीं दूसरी तरफ माकपा–भाकपा के जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन ने उन्हें राज्य में तात्कालिक फायदा तो जरूर पहुंचाया लेकिन दोनों दलों के बीच की वैचारिक दूरी ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया.

राजनीतिक समीक्षक वाम दलों के खस्ताहाल के लिए विपरीत वैचारिक दृष्टिकोण वाली पार्टियों के साथ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किए गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं. हालांकि बिहार चुनाव में महा–गठबंधन के साथ नहीं जाने पर पर यह सवाल भी उठा कि जब पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय के चुनावों में वाम दल कांग्रेस के साथ एक समन्वय बना सकते हैं तो बिहार में कांग्रेस, जद(यू) और राजद वाले महा–गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हो सकते? इस सवाल के जवाब में माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने कहा कि बिहार में तथाकथित महा–गठबंधन के साथ जाने और कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है.

बहरहाल, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि वाम दलों ने महा–गठबंधन का नुकसान पहुंचाया या एनडीए को फायदा. लेकिन सबसे महतवपूर्ण सवाल यह है कि क्या वामपंथी पार्टियों का यह गठबंधन बिहार के ध्रुवीकृत मुक़ाबले में अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करने में सफल हो पायेगा? हालांकि बिहार की मौजूदा राजनीतक परिस्थिति में ऐसी उम्मीद करना किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बराबर है. यदि वामदलों को राज्य में और देश में अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसे किसी भी तरह के अवसरवाद से प्रेरित राजनीति से परहेज़ करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

चुनाव में हासिल कुल सीटें

वर्ष	भाकपा	माकपा	भाकपा (माले)
1952	0	--	--
1962	12	--	--
1967	24	4	--
1979	25	3	--
1972	35	0	--
1977	21	4	--
1980	23	6	--
1985	12	1	--
1990	23	6	--
1995	26	6	6
2000	5	2	6
2005 फ़रवरी	3	2	7
2005 अक्टूबर	3	1	7
2010	1	0	0

जातीय चाशनी में सराबोर बिहार का चुनावी संग्राम

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

जैसी आशंका थी, ठीक वैसा ही हुआ. विकास के लाख दावों के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव जातीय चाशनी में सराबोर हो गया. दोनों बड़े गठबंधनों ने अपने बेस वोट को ध्यान में रखते हुए टिकटों का बंटवारा किया. इसका साइड इफैक्ट यह हुआ कि बहुत से अच्छे उम्मीदवार टिकट पाने से वंचित रह गए. इसी वजह से टिकट वितरण के साथ ही पार्टी कार्यलयों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया. बहुत जगहों पर प्रत्याशी बदलने के लिए तोड़फोड़ भी हुई. लेकिन पार्टी आलाकमान ने यह साफ कर दिया कि टिकटों का वितरण सामाजिक समीकरण को देखते हुए किया गया है और इसमें फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है. टिकट वितरण से यह साफ हो गया है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने माय, दलित और महादलित को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है. यादव बिरादरी से 64, दलित–महादलित से 36 और 33 अल्पसंख्यकों को महा–गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने अपने बेस वोट अगड़ी जातियों में से राजपूतों को 35, भूमिहारों को 29, ब्राम्हणों को 18 और वैश्यों को 18 सीटों से उम्मीदवार बनाया है. यादवों के वोटों का बंटवारा हो इसके लिए एनडीए ने 25 यादव उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है. देखा जाये तो इन्हीं दो गठबंधनों ने 89 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इन दोनों गठबंधनों में इसके अलावा 47 राजपूतों, 42 भूमिहारों, 42 मुस्लिमों और 45 अतिपिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया है. जदयू के हवाले से लव–कुश को ताकत दी गई है तो कांग्रेस ने सवर्णों को खुश करने का जिम्मा उठाया है. महा–गठबंधन ने माई समीकरण से 97 लोगों को टिकट दिया है तो एनडीए गठबंधन ने 34 को. गौरतलब है कि खबर लिखे जाने तक अभी राजग के 20 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है इसलिए इन आकड़ों में इज़ाफा भी हो सकता है. देखा जाए तो दोनों गठबंधनों ने किसी तरह का नया प्रयोग करने का साहस नहीं दिखाया और जहां उनकी ताकत थी उन्होंने वहीं अपना सारा होमवर्क किया. अब अगली कहानी कुशल चुनाव प्रबंधन की लिखी जानी है. इस मामले में जो बेहतर साबित होगा, चुनावी बाज़ी उसके हाथ लगने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी. एक बात यहां भी गौर करने वाली है कि छह दलों के तीसरे मोर्चे ने जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया है उससे एनडीए को कम और महा–गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है. तीसरे मोर्चे ने महा–गठबंधन के सामाजिक और जातीय समीकरण को कमजोर करने के लिए चुन–चुनकर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस जातीय ताने–बाने को दोनों गठबंधनों ने सजाया–संवारा है उसका कितना फायदा चुनावी महासमर में उन्हें मिल पायेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

2010 का जातीय समीकरण

- पिछले चुनाव (2010) में कुर्मी जाति के 18 लोग जीते. जदयू के 14, भाजपा के 2 तथा लोजपा और कांग्रेस के 1-1
- कोयरी जाति के 19 विधायक बने. इनमें 12 जदयू के टिकट पर जीते. 5 भाजपा और 2 राजद के टिकट पर.
- यादव जाति के 39 लोग विधानसभा पहुंचे. इनमें 19 जदयू, 8 भाजपा, 10 राजद, 1 भाकपा तथा 1 निर्दलीय जीते.
- वैश्य जाति के 12 विधायक. 10 भाजपा से, 1 जदयू तथा 1 निर्दलीय.
- अति पिछड़ी जमात से 17 जीते(10 जदयू 7 भाजपा से)
- 10 ब्राम्हण भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीते. जदयू से 4 तथा 2 लोग निर्दलीय लड़कर विधानसभा पहुंचे.
- 26 भूमिहार विधायक बने. 13 जदयू के और इतने ही भाजपा के.
- विधायक बनने वाले राजपूतों की संख्या 34 रही. भाजपा के 15, जदयू के 14, राजद के 3, झामुमो के तथा एक निर्दलीय राजपूत उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे.
- कायस्थ विधायकों की संख्या 3 रही. 2 भाजपा से और 1 निर्दलीय जीते.
- 9 मुस्लिम विधायक बने. जदयू के 7, भाजपा के 1, राजद के 6, लोजपा के 2 तथा कांग्रेस के 3.
- अ.जा. के 38 विधायक. जदयू के 19, भाजपा के 18 और राजद के एक
- अ.ज.जा. के 2 विधायकों में 1-1 जदयू भाजपा के रहे.

इस चुनाव को जदयू और भाजपा मिलकर लड़ा था. बाकी सभी दल उसके विरोधी थे. इस बार दोनों पालों का नया रंग बहुत कुछ नया दिखा सकता है. ■

किस जाति को कितने टिकट मिले

जाति	महा–गठबंधन	राजग
ब्राह्मण	9	18
भूमिहार	13	29
राजपूत	12	35
कायस्थ	04	03
यादव	64	25
कुर्मी	16	04
कुशवाहा	22	19
वैश्य	06	18
दलित/महादलित	36	32
अति पिछड़ा	25	20
अल्पसंख्यक	33	09
महिलाएं	25	19

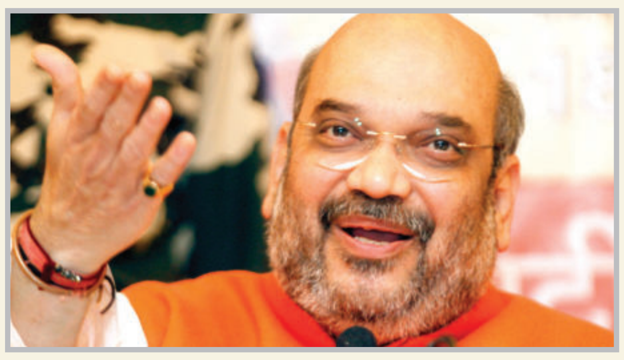

चुनाव अपने आप में उत्तेजक होते ही हैं, पर इस बार उत्तेजना पिछले चुनावों की तुलना में कुछ अधिक ही है. बिहार विधानसभा का यह चुनाव साम, दाम, दंड और भेद का उत्तम नमूना है. सत्ता के दोनों दावेदार(एनडीए और महागठबंधन) बागी उम्मीदवारों से त्रस्त हैं. यह सत्य है कि एनडीए के घटक दलों में बेटिकट लोगों की संख्या महा–गठबंधन के दलों की तुलना में काफी कम है. लोजपा और रालोसपा के कोई विधायक थे ही नहीं, हम के सभी विधायकों को जगह मिल ही गई है लेकिन, भाजपा ने अपने एक दर्जन से अधिक विधायकों को इस बार टिकट से वंचित कर दिया.

चुनौती सबके लिए है

सत्ता बचाने की सत्ता पाने की

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महा–गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है. गत विधानसभा चुनाव और उसके बाद के उप–चुनावों में इन 49 सीटों में से 37 पर महा–गठबंधन के दल काबिज हुए. इनमें से 31 सीटों पर तो सत्तारुढ़ जद(यू) काबिज है जबकि चार सीटों पर राजद और दो सीटों पर कांग्रेस. हालांकि, पिछले संसदीय चुनाव में हालत बदल गई और इस हिस्से के समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, नवादा आदि संसदीय सीटों पर एनडीए क़ाबिज हुआ था, जबकि भागलपुर और बांका में राजद. इस लिहाज से देखें तो दोनों राजनीतिक ध्रुवों के लिए विधानसभा चुनाव का यह चरण अग्निपरीक्षा जैसा है.

सरोज सिंह

बिहार की चुनावी रणभूमि सज गई है. राजनेताओं के नाते–रिश्तेदारों और बागियों की भारमार के साथ राज्य विधानसभा के पहले चरण के चुनावी योद्धा अपने लाव–लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके हैं. राज्य विधानसभा की 243 सीटों के लिए पांच चरण में मतदान होना है. बारह अक्टूबर को पहले चरण में दस जिलों की कुल 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. चार दर्जन से अधिक ये निर्वाचन क्षेत्र मिथिला की धरती समस्तीपुर से लेकर मगध की धरती तक फैले हुए हैं. महाकवि विद्यापति की कर्मभूमि कल्याणपुर से लेकर बिहार के सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र रजौली के मतदाता पहले चरण में मतदान करेंगे. इस दोनों ध्रुवों के बीच अंगभूमि, भागलपुर–मुंगेर प्रमंडलों में भी इसी दिन वोट डाले जाने हैं. हालांकि ये विधानसभा वोटरों की अभूतपूर्व और तीखी राजनीतिक गोलबंदी के बीच हो रहे हैं. लेकिन अपने राजनीतिक चरित्र में इसमें दो गठबंधनों के बीच सीधा मुक़ाबला है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) व राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल(यू) एवं कांग्रेस के महा–गठबंधन के घटक दलों ने आम तौर पर पूरे राज्य में सीधी टक्कर का ही माहौल बनाया है. पर, वास्तविकता यह भी है कि समाजवादी धर्मनिर्पेक्ष मोर्चा के नाम से स्वघोषित तीसरे मोर्चे और वामपंथी मोर्चा(जिसमें छह वाम दल शामिल हैं) के कई उम्मीदवारों ने अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस मुक़ाबले को त्रिकोणीय या बहु–कोणीय बना दिया है.

प्रथम चरण के मतदान में कई नेताओं की साख दांव पर हैं– कुछ स्वयं चुनाव मैदान में हैं, तो कुछ के नाते–रिश्तेदार. हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के नेता शकुनी चौधरी (तारापुर), भाकपा (मा) के बड़े नेता रामदेव वर्मा (विभूतिपुर), बिहार सरकार के ताकतवर मंत्री विजय कुमार चौधरी (सरायरंजन), कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेवालाल चौधरी (तारापुर) आदि बड़े नाम पहले चरण में ही मतदाताओं के आर्शीवाद की उम्मीद कर रहे हैं. इनके अलावा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा के पुराने व पसंसदीदा क्षेत्र उजियारपुर में भी पहले चरण में ही मतदान होना है, और यहां एनडीए की तरफ से लोक समता दल के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं. कुछ नामचीन बाहुबलियों की किस्मत का फैसला भी इसी तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा. इनमें प्र लाद यादव (राजद, सूर्यगढ़ा), प्रदीप कुमार (जदयू– वारसलीगंज), राजवल्लभ प्रसाद (राजद, नवादा), कौशल यादव (जदयू–हिसुआ), रामलखन सिंह (भाजपा– तेघड़ा) नरेन्द्र कुमार सिंह (जदयू– मटिहानी) आदि प्रमुख हैं. बाहुबलियों की पत्नी व अन्य रिश्तेदार भी कई विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं. राजनेताओं की अगली पीढ़ी तो सामने आ ही रही हैं, अन्य नाते–रिश्तेदारों को भी राजनीतिक खेल में उतरने का मौका दिया जा रहा है. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने अपने भतीजे और सांसद रामचन्द्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज (कल्याणपुर) को राजनीति के मैदान में उतार रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के नेता नामचीन बाहुबली सूरजभान ने अपने रिश्तेदार रमेश राय (विभूतिपुर) को मौका दिया है. भाजपा के नैतिकतावादी मुखर नेता–सांसद अश्विनी कुमार चौबे अपने पुत्र अर्जित शाश्वत के लिए भागलपुर से उम्मीदवारी हासिल करने में कामयाब रहे. इसी तरह हम के नेता शकुनी चौधरी इस चुनाव के जरिए अपने दूसरे पुत्र राजेश कुमार उर्फ रोहित (खगड़िया) को लॉन्च कर रहे हैं. तारापुर की जद(यू) विधायक नीता चौधरी की जगह इस बार उनके पति और कृषि वैज्ञानिक मेवालाल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है. कटोरिया (सु) के विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम की बहु निक्की हेम्ब्रम इस बार अपने ससुर की इच्छा का पालन कर रही हैं, और कटोरिया से क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी हैं. इस चुनाव के जरिए राजनीति में इन सभी की लॉन्चिंग हो रही है. नए राज–घरानों का विस्तार हो रहा है. लेकिन इनके अलावा और भी उम्मीदवार हैं जो अपने खानदान के राजनीतिक रूतबे और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी या तीसरी बार चुनाव मैदान में डटे हैं.

बिहार में होने वाले चुनाव हिंसा और रक्तपात के लिए राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होते रहे हैं. यह अब इतिहास की बात हो गई है. इस तथ्य पर गौर करने के बावजूद, यहां बाहुबलियों के गैंगवार और नक्सली हिंसा की आशंका सदैव बनी रहती है, खासकर चुनावों के समय. प्रथम चरण में जिन निर्वाचन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से तकरीबन चालीस प्रतिशत कमोवेश नक्सल प्रभावित हैं, इन क्षेत्रों में सदैव हिंसक घटनाएं होती रही हैं. ये वे इलाके हैं जहां नक्सली हमले में एसपी मारे गए, पुलिस दल का अपहरण कर लिया गया और निर्माण कार्यों में लगे लोगों के अपहरण की घटनायें हमेशा होती रहती हैं. चकाई, जमुई, झाझा, रजौली, हिसुआ, नवादा, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, कटोरिया, बेलहर, बांका, सिकन्दरा, जमालपुर, मुंगेर जैसे तकरीबन डेढ़ दर्जन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नक्सलियों के सुरक्षित इलाके माने जाते हैं. जबकि गोविंदपुर, वारसलीगंज, नवादा, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मुंगेर, मटिहानी, तेघड़ा, खगड़िया, गोपालपुर, बिहपुर, बेलदौर जैसे कई निर्वाचन क्षेत्र बाहुबलियों के क्रीड़ा केंद्र रहे हैं. इन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना की प्रशासन के लिए चुनौती रहा है. इस बार भी प्रशासन का दावा है कि नक्सली हिंसा समेत अन्य सभी हिंसाओं को नियंत्रित करने के सारे उपाय कर लिए गए हैं. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के दस्ते बिहार पहुंचने लगे हैं और उनकी तैनाती भी शुरू हो गयी है.

चुनाव अपने आप में उत्तेजक होते ही हैं, पर इस बार उत्तेजना पिछले चुनावों की तुलना में कुछ अधिक ही है. बिहार विधानसभा का यह चुनाव साम, दाम, दंड और भेद का उत्तम नमूना है. सत्ता के दोनों दावेदार(एनडीए और महागठबंधन) बागी उम्मीदवारों से त्रस्त हैं. यह सत्य है कि एनडीए के घटक दलों में बेटिकट लोगों की संख्या महा–गठबंधन के दलों की तुलना में काफी कम है. लोजपा और रालोसपा के कोई विधायक थे ही नहीं, हम के सभी विधायकों को जगह मिल ही गई है लेकिन, भाजपा ने अपने एक दर्जन से अधिक विधायकों को इस बार टिकट से वंचित कर दिया. इनमें सबसे अधिक चर्चा ब्रह्मपुर (बक्सर) से बेटिकट दिलमणि देवी को लेकर हुई है. बिहार में भाजपा को खड़ा करने में दधीचि की भूमिका निभाने वाले कैलाशपति मिश्र की बहु के पराभव पर काफी कुछ कहा गया. इसी तरह चंद्रमोहन राय (चनपटिया), रश्मि वर्मा (नरकटियागंज), विक्रम कुंवर(रघुनाथपुर), आनंन्दी यादव (सिकटी), पद्मपराग राय वेणु (फॉरबिसगंज) आदि को भी बेटिकट कर दिया गया. पहले चरण में भाजपा ने तेघड़ा से ललन कुंवर, पीरपैंती(सु) से अमन कुमार और रजौली(सु) से कन्हैया कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया. लेकिन महा–गठबंधन में तो इसकी तुलना काफी लोगों को बेटिकट किया गया और ऐसा कर लालू प्रसाद के पुत्रों सहित अनेक नेताओं के नाते–रिश्तेदारों को राजनीति में लॉचिंग का मौका दिया गया. इसके बाद चुनावी समीकरण की गोटी फिट करने के ख्याल से भी कई विधायकों को बेटिकट कर नए प्रत्याशियों को टिकट दिए गए. बहुतों का आरोप है कि ऐसा केवल अपने खासम–खास को जगह देने के लिए ही किया गया. जहां जद(यू) के कुल 32 विधायक बेटिकट हुए, वहीं राजद के दस. जद(यू) ने स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह और मत्स्य पालन मंत्री बैद्यनाथ सहनी को टिकट नहीं दिया. पहले चरण में महा–गठबंधन के जिन नेताओं को बेटिकट होना पड़ा उनमें मंत्री बैद्यानाथ सहनी (मोरवा) सहित जदयू के रामचंद्र सदा (अलौली), नरेन्द्र कुमार नीरज (गोपालपुर), अनन्त कुमार सत्यार्थी (मुंगेर), गजानंद शाही (बरबीघा) व रामेश्वर पासवान (सिकन्दरा) और राजद के अजय कुमार बुल्गानिन (मोहिउद्दीन नगर), दुर्गाप्रसाद सिंह (उजियारपुर) आदि हैं.

दोनों गठबंधनों(एनडीए और महा–गठबंधन) के बेटिकट या उम्मीदवारी की दौड़ में उपेक्षित राजनेताओं का नया ठिकाना समाजवादी पार्टी, एनसीपी और पप्पू यादव की जअपा सहित कुछ अन्य दलों का समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बन गया है. इस मोर्चे के अलग–अलग दलों में शामिल होकर महा–गठबंधन या एनडीए के अलग–अलग दलों के ये बागी और बेटिकट अपने पूर्व दल को चुनौती देने को बेताब हैं. बेटिकट व बागियों की ऐसी जमात सूबे के दोनों के राजनीतिक ध्रुवों के लिए परेशानी का सबब है. पहले चरण के चुनावों में बेटिकट व बागियों की यह जमात समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, मोहिउद्दीननगर, परबत्ता, भागलपुर, मुंगेर, रजौली, झाजा, चकाई सिकन्दरा आदि कई निर्वाचन क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण हो जायेगी. चकाई की सीट तो एनडीए में लोजपा और हम के वीच विवाद का कारण बन गई. निवर्त्तमान विधायक व पूर्व कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह के पुत्र सुमित सिंह को एनडीए के विद्रोही के तौर पर चुनाव में उतारना पड़ा है. यह सीट लोजपा, हम और नरेन्द्र सिंह के लिए मूंछ का सवाल बन गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महा–गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है. गत विधानसभा चुनाव और उसके बाद के उप–चुनावों में इन 49 सीटों में से 37 पर महा–गठबंधन के दल काबिज हुए. इनमें से 31 सीटों पर तो सत्तारुढ़ जद(यू) काबिज है जबकि चार सीटों पर राजद और दो सीटों पर कांग्रेस. हालांकि, पिछले संसदीय चुनाव में हालत बदल गई और इस हिस्से के समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, नवादा आदि संसदीय सीटों पर एनडीए क़ाबिज हुआ था, जबकि भागलपुर और बांका में राजद. इस लिहाज से देखें तो दोनों राजनीतिक ध्रुवों के लिए विधानसभा चुनाव का यह चरण अग्निपरीक्षा जैसा है. महा–गठबंधन के सामने इन सीटों पर जीत का परचम लहराये रखने की चुनौती है तो एनडीए के सामने संसदीय चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराने की. हालांकि चुनावी हवा का मौजूदा रूख एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन संसदीय चुनाव के प्रदर्शन को दोहराना उसके लिए असंभव जैसा ही है. समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई आदि जिलों में एनडीए आंतरिक रूप से बंटा हुआ है. हालांकि यह विभाजन नाराजगी के स्तर पर है. यह नाराजगी बाहरी या वंशवादी उम्मीदवारों को टिकट दिये जाने को लेकर है. सामाजिक विभाजन भी अपना काम कर रहा है. बागियों की मार एनडीए के बनिस्वत महा–गठबंधन पर अधिक है. माय को छोड़कर अन्य कोई दबंग मतदाता समूह इसके साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है. हालांकि अतिपिछड़ी जातियों के मतदाताओं में उसकी स्थिति एनडीए की तुलना में बेहतर है और महादलितों के एक समूह का वोट भी उसकी ओर जाता दिख रहा है. लेकिन उसके लिए एक और परेशानी वाम मोर्चा है. समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, जमुई आदि जिलों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महा–गठबंधन के लिए वाम दल संकट पैदा कर रहे हैं. वस्तुतः इन दलों के उम्मीदवारों को एनडीए विरोधी वोट ही मिल रहे हैं. लेकिन अब तक की हवा महा–गठबंधन को इतनी उम्मीद दे रही है कि संसदीय चुनाव की अपेक्षा इस बार उसकी हालत बेहतर रहेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

दामोदर राउत

अजय प्रताप

पशुपति पारस

पूनम देवी

रामबालकजी

रेणु कुशवाहा

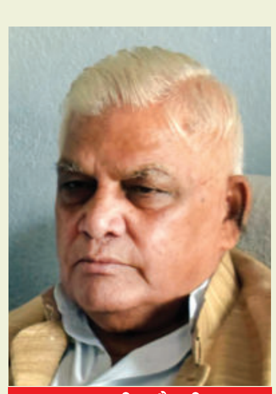
शकुनी चौधरी

सुभाष पासवान

सुमित सिंह

विजय कुमार चौधरी

महा-गठबंधन के लिए केवल इतना संकट नहीं है. उसे माय को तो बचाना ही है, अतिपिछड़ा और महादलितों को भी अपने दायरे में गोलबंद रखना उसकी बड़ी जरूरत है. नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में इन सामाजिक समूहों के राजनीतिकरण व सशक्तिकरण का अभियान चलाया था. इसका लाभ उन्हें पिछले विधानसभा चुनावों में मिला था. पिछले संसदीय चुनावों में नरेन्द्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अतिपिछड़ों में तो भाजपा की घुसपैठ हुई, लेकिन महादलित समुदाय नीतीश कुमार के साथ ही रहा. पर, जीतनराम मांझी प्रकरण ने इसे तहस नहस कर दिया.

सबके निशाने पर माय

बिहार चुनाव विशेष

विकास के सपने पर जाति का सच भारी

भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दलों ने माय(मुस्लिम-यादव) में बिखराव का उपाय किया है. महागठबंधन- मुख्यतः राजद और जद(यू) के यादव प्रत्याशियों के खिलाफ मुस्लिम और मुस्लिम प्रत्याशियों के विरोध में यादव प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है. दरभंगा जिला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. वहां दरभंगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में राजद के वरिष्ठ नेता ललित कुमार यादव के खिलाफ हम के नौशाद आलम को और अलीनगर में श्री सिद्दिकी के खिलाफ मिश्रीलाल यादव को मैदान में उतारा गया है. जिले के केवटी में भाजपा के यादव विधायक हैं तो राजद ने वहां से मुस्लिम उम्मीदवार दिया है. इसी तरह हम ने साहबपुर कमाल (बेगूसराय) में राजद के श्रीनारायण यादव के खिलाफ मोहम्मद असलम व बेलागंज (गया) में सुरेन्द्र यादव के विरोध में शारिम अली को अपना उम्मीदवार बनाया है.

सुकान्त

बिहार विधानसभा का चुनाव अभियान अपने शबाब पर पहुंच रहा है. राजनीतिक गठबंधनों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन की बात तो दूर, इनसे बाहर के छोटे-बड़े दलों ने भी अपनी चालें चल दी हैं. सभी राजनीतिक गठबंधनों और दलों ने अपने-अपने चुनाव अभियान की शुरुआत बिहार के विकास की जरूरत से की, पर अंततः वे जाति पर ही आकर टिक गये. अब वे जाति की गोटी फिट कर, कुर्सी की जुगत भिड़ाने का कोई उपाय बाकी नहीं छोड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस बार अभी नहीं, तो कभी नहीं की भावना से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और येन-केन प्रकारेण वह हिन्दीपट्टी के इस प्रखर राज्य की सत्ता पर क़ाबिज होने के लिए संकल्पित है. इस लिहाज़ से प्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भी वह सब कर रही है जिनका कुछ वर्ष पहले तक उसका नेतृत्व प्रखर विरोध करता था.

भाजपा अगड़ी जाति, दलित और पिछड़ों का नया राजनीतिक समीकरण तैयार करने में पिछले कई महीनों से जुटी है. अपने इस अभियान में वह बहुत हद तक सफल भी होती दिख रही है. बिहार के 13 प्रतिशत अगड़ी जाति के मतदाताओं में से तकरीबन तीन चौथाई भाजपा के साथ हैं. वह दलितों का भी अच्छा-खासा समर्थन हासिल होने का दावा कर रही है. पिछले संसदीय चुनाव में रामविलास पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) एनडीए में शामिल हो गई थी. अब जीतनराम मांझी और उनका हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के साथ आने से बिहार का दलित नेतृत्व एनडीए के पाले में है. इसके साथ ही पिछड़े सामाजिक समूहों से वैश्य और कुशवाहा भी उससे जुड़ गए हैं. इन दोनों पिछड़े सामाजिक समूहों का पूरा नेतृत्व एनडीए के साथ है. बिहार में वैश्य समाज में सुशील कुमार मोदी से बड़ा या उनके समानांतर दूसरा कोई नाम नहीं है. उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) संसदीय चुनाव में ही एनडीए का दामन थाम लिया था. इस बार हम के बहाने कुशवाहा समाज के दूसरे बड़े नेता भी एनडीए से जुड़ गए हैं. लेकिन पिछड़ों में सबसे जुझारू, बड़ी और राजनीतिक जातियां यादव व कुर्मी और अति-पिछड़ी जातियां अब भी भाजपा और एनडीए के दायरे से आम तौर पर बाहर ही हैं. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि बिहार में लालू-नीतीश की जोड़ी को बेअसर करने के लिए इन सामाजिक समूहों पर निशाना साधना बेदह जरूरी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में हुई रैली में खुद को द्वारकाधीश का प्रतिनिधि बताकर यदुवंशियों का संरक्षक घोषित किया था. इसी रणनीति के तहत भूपेन्द्र यादव और नंदकिशोर यादव जैसे अपेक्षाकृत युवा नेताओं के साथ-साथ नवागंतुक रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को भी पार्टी में तवज्जो दी जाने लगी है. भाजपा की इस रणनीति का असर उसके उम्मीदवारों की सूची में भी दिखाई पड़ता है. इस रणनीति का पालन उसने अपने सहयोगी दलों से भी करवाया है.

भाजपा ने बड़ी चतुराई से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की घेराबंदी की है. भाजपा ने अपने चुनाव चिन्ह पर दो दर्जन से अधिक यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. इसके अलावा सहयोगी दलों को भी इस पर खास तवज्जो देने को कहा गया. इसके बाद हालात ऐसे बने कि राजद से दुखी यादवों को बुला-बुला कर टिकट दिए गए. नालंदा जिला के इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र से जिस वीरेन्द्र गोप को उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें कुछ ही घंटे पहले भाजपा में शामिल कराता गया था. लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव (राघोपुर) के खिलाफ जद(यू) के निवर्त्तमान विधायक सतीश कुमार यादव को तकरीबन बारह घंटे पहले और राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी (अलीनगर) के खिलाफ राजद के पूर्व विधान पार्षद मिश्रीलाल यादव को तकरीबन चौबीस घंटे पहले ही भाजपा की सदस्यता दी गई. इसे कहते हैं घर बुला कर सिंबल देना. ये तो अंतिम समय के कुछ उदाहरण हैं. इससे पहले भी की राजद और जद(यू) से नाराज़ उसके कई नामचीन यादव उम्मीदवारों को पार्टी ने सम्मानित किया है. इसके अलावा, डॉ. रवीन्द्रचरण यादव (बिहारीगंज) और श्रीकान्त निराला (मनेर) भी राजद से भाजपा में आकर टिकट पानेवाले प्रमुख लोगों में शामिल हैं.

भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दलों ने माय(मुस्लिम-यादव) में बिखराव का उपाय किया है. महागठबंधन- मुख्यतः राजद और जद(यू)- के यादव प्रत्याशियों के खिलाफ मुस्लिम और मुस्लिम प्रत्याशियों के विरोध में

यादव प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतराने का फैसला किया है. दरभंगा जिला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. वहां दरभंगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में राजद के वरिष्ठ नेता ललित कुमार यादव के खिलाफ हम के नौशाद आलम को और अलीनगर में श्री सिद्दिकी के खिलाफ मिश्रीलाल यादव को मैदान में उतारा गया है. जिले के केवटी में भाजपा के यादव विधायक हैं तो राजद ने वहां से मुस्लिम उम्मीदवार दिया है. इसी तरह हम ने साहबपुर कमाल (बेगूसराय) में राजद के श्रीनारायण यादव के खिलाफ मोहम्मद असलम व बेलागंज (गया) में सुरेन्द्र यादव के विरोध में शारिम अली को अपना उम्मीदवार बनाया है. लोजपा ने सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन के यादव उम्मीदवार के खिलाफ मुसलमान को टिकट दिया है. हालांकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा-अर्थात तीसरे मोर्चा के उम्मादवारों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है. पर, इस मोर्चा में भी माय को निशाने पर लेने की तैयारी है. वस्तुतः यह मोर्चा राज्य में दोनों गठबंधन से निराश राजनेताओं का नया आश्रय-स्थल है. इस मोर्चा में शामिल सासंद पप्पू यादव ने तो साफ शब्दों में राजद के बड़े मुस्लिम नेता तसलीमुद्दीन को अपनी जनअधिकार पार्टी में शामिल होकर पप्पू यादव को नेतृत्व देने के लिए साथ आने का न्योता दिया है. यहां जिस ढंग से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है वही बताता है कि जहां माय को भेदने के उपाय में भाजपा या एनडीए चूक गया, वहां तीसरी मोर्चा इस काम को बखूबी पूरा कर रहा है. डुमरांव निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए की रालोसपा ने रामबिहारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है. इसलिए, वहां टिकट से वंचित जद(यू) के निवर्त्तमान विधायक दाउद अली जन अधिकार पार्टी (जअप) से उम्मीदवार हो रहे हैं. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद- और इस लिहाज से महा-गठबंधन के लिए यह चुनाव अग्निपरीक्षा है. माय लालू प्रसाद की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है. महा-गठबंधन के समर्थन का सामाजिक आधार भी यही है. बिहार के सबसे पुराने इस राजनीतिक-सामाजिक समीकरण को एकजुट रखना और ऐसा करते हुए उसे जुझारू मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाना, लालू प्रसाद व महा-गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है. यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में यादव समाज का तीव्र राजनीतिकरण हुआ है और उनकी राजनीतिक आकांक्षायें परवान चढ़ने लगी हैं. उनकी इसी महत्वाकांक्षा का उपयोग हर राजनीतिक दल कर रहा है. एनडीए के आक्रामक यादव पटाओ अभियान की काट महागठबंधन के पास नहीं दिखाई पड़ रही है. राजद और जद(यू) ने निवर्त्तमान विधानसभा के अपने तकरीबन पचास विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया है. यह संख्या दोनों दलों के कुल विधायकों के एक तिहाई से अधिक है. हालांकि इसमें सभी सामाजिक समूहों के विधायक हैं. लेकिन यह भी सही है कि माय के दायरे के विधायकों की संख्या भी कम नहीं है. इस घाव को महा-गठबंधन ने भरने की कोशिश की है. उसकी प्रत्याशियों की जारी सूची के अनुसार अगड़े सामाजिक समूहों को पंद्रह प्रतिशत व दलित समुदाय को सोलह प्रतिशत उम्मीदवारी दी गई है. विधानसभा की शेष 69 प्रतिशत सीटों पर इसने पिछड़ा-अतिपिछड़ा और मुसलमानों को अपना प्रत्याशी बनाया है. महा-गठबंधन के तीनों दलों ने मिलकर मुसलमानों को 16 प्रतिशत उम्मीदवारी दी है. महा-गठबंधन के लिए केवल इतना संकट नहीं है. उसे माय को तो बचाना ही है, अतिपिछड़ा और महादलितों को भी अपने दायरे में गोलबंद रखना उसकी बड़ी जरूरत है. नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में इन सामाजिक समूहों के राजनीतिकरण व सशक्तिकरण का अभियान चलाया था. इसका लाभ उन्हें पिछले विधानसभा चुनावों में मिला था. पिछले संसदीय चुनावों में नरेन्द्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अतिपिछड़ों में तो भाजपा की घुसपैठ हुई, लेकिन महादलित समुदाय नीतीश कुमार के साथ ही रहा. पर, जीतनराम मांझी प्रकरण ने इसे तहस नहस कर दिया. माना जा रहा है कि मांझी के कारण इन सामाजिक समूहों का समर्थन भाजपा (एनडीए) को मिलेगा. लेकिन यह बहुत हद तक सही नहीं है. पासवान, मुसहर जैसे दलित समुदायों का समर्थन एनडीए को मिल सकता है, पर अन्य जातियों पर नीतीश कुमार का प्रभाव अब भी है. इस लिहाज से महादलित में महा-गठबंधन की एक हिस्सेदारी बनती है. अब यह महा-गठबंधन के रणनीतिकारों पर निर्भर करता है कि वे इसे किस हद तक बचा कर रखते हैं. इसी तरह अतिपिछड़ी जातियों में से कुछ भाजपा (या एनडीए) के साथ हो गई हैं और उनकी नीतीश कुमार के साथ वापसी कठिन है. पर, कुछ जातियों में अब भी नीतीश कुमार का असर है. इन सबके बावजूद लाख टके का सवाल यह है कि मतदान के दौरान और उसके बाद, इनके साथ कौन रहेगा? इस प्रश्न के जवाब में काफी कुछ निर्भर करता है. बिहार में अतिपिछड़ों की आबादी लगभग बत्तीस प्रतिशत है. सूबे की चुनावी गोलबंदी का असर सामाजिक तौर पर भी पड़ा है और अधिकांश बड़ी जातियां स्पष्टतः इस पक्ष या उस पक्ष में हैं. लेकिन अतिपिछड़ी जातियां और कुछ दलित समुदाय अभी भी इस तरह की गोलबंदी से बाहर हैं. महा-गठबंधन के नेताओं को इनके बारे में, इनकी सुरक्षा के बारे में विचार करना है. मतदान के दौरान और उसके बाद इनकी सुरक्षा की गारंटी किसी भी राजनीतिक समूह की जीत को आसान बना देगी. इस फ्रंट पर महा-गठबंधन को एनडीए की तुलना में वामदलों के मोर्चा से कम खतरा नहीं है. अतिपिछड़े और दलित समुदाय वामदलों का मूल आधार रहे हैं. इस बार सभी वाम दल(छह) एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं. इन सभी को एक साथ सामने रखकर देखें तो राज्य के तकरीबन चार दर्जन निर्वाचन क्षेत्रों में इनकी ताकत है. इन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को ये प्रभावित कर सकते हैं. कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि महा-गठबंधन की घेराबंदी कई तरह से हो रही है. महागठबंधन और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी ताकत माय है, और इसे इसी तरह के किसी जातीय हथियार से भेदने का कोई भी उपाय एनडीए या लालू-नीतीश विरोधी मध्यमार्गी दल बाकी नहीं छोड़ेगा. एनडीए हो या तीसरा मोर्चा या एमआईएम सुप्रीमो असदउद्दीन ओवैसी. सूबे की महा-गठबंधन विरोधी राजनीतिक ताकतों के लिए माय को निशाने पर लेना और इसे बिखेरना, इन सबकी राजनीतिक जरूरत है. राज्य की लगभग 40 प्रतिशत विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों को माय की एकजुटता प्रभावित करती है.

माय की एकजुटता लालू प्रसाद की मूल पूंजी है और पिछले कई चुनावों से इन सामाजिक समूहों के मतदाताओं की मतदान शैली पर उनका गहरा असर रहा है. इसलिए, इसे तोड़े बगैर बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के प्रभाव को बेअसर नहीं किया जा सकता. इसीलिए एनडीए ने इस चुनाव में तीस से अधिक यादव प्रत्याशी दिए हैं. इसके साथ ही भाजपा की कोशिश रही है कि महागठबंधन के यादव प्रत्याशियों के खिलाफ एनडीए के अन्य दल व परोक्ष-सहयोगी मुस्लिम प्रत्याशी दें. बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि में इसके उदाहरण बिखरे पड़े हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

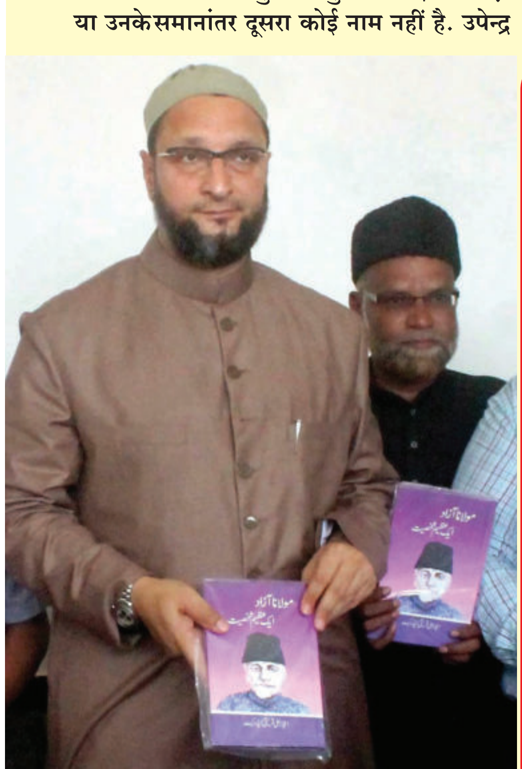

माय की एकजुटता लालू प्रसाद की मूल पूंजी है और पिछले कई चुनावों से इन सामाजिक समूहों के मतदाताओं की मतदान शैली पर उनका गहरा असर रहा है. इसलिए, इसे तोड़े बगैर बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के प्रभाव को बेअसर नहीं किया जा सकता. इसीलिए एनडीए ने इस चुनाव में 30 से अधिक यादव प्रत्याशी दिए हैं. इसके साथ ही भाजपा की कोशिश रही है कि महागठबंधन के यादव प्रत्याशियों के खिलाफ एनडीए के अन्य दल व परोक्ष-सहयोगी मुस्लिम प्रत्याशी दें.

तीसरा मोर्चा : ख़ुद भले न जीते, दूसरों का खेल बिगाड़ेगा

नवीन चौहान

बिहार विधानसभा चुनावों का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है. दो गठबंधनों के बीच अब तीसरे मोर्चे ने भी दस्तक दे दी है. मुलायम सिंह की अगुवाई में 6 पार्टियों ने मिलकर समाजवादी सेक्लुयर फ्रंट बनाया है. यह मोर्चा प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. राजनीतिक समीक्षक इसका सीधा असर महा-गठबंधन के वोट बैंक पर पड़ने के आसार जता रहे हैं. इसके साथ ही विरोधी दलों का आरोप है कि सपा बिहार में भाजपा की मदद कर रही है. अभी तक के चुनावी सर्वे के मुताबिक जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा था, लेकिन तीसरे मोर्चे के मैदान में उतरने के बाद चुनावी गणित के बदलने के आसार प्रबल हो गये हैं.

2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत से भारतीय राजनीति में गहमागहमी बढ़ गई थी. विपक्षी दलों को लगने लगा था कि तात्कालिक परिस्थितियों में वे अकेले भाजपा का मुक़ाबला नहीं कर सकती हैं. इसके लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर भाजपा का मुक़ाबला करना होगा. उसी समय विघटित जनता दल को एक बार फिर से नये स्वरूप में लाने की कवायद शुरू हुई. इस कवायद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मुख्य रूप से शामिल थे. इन सभी ने कई दौर की बातचीत के बाद अपनी-अपनी पार्टियों के विलय के बाद एक नई पार्टी के गठन पर सहमति जताई और एक झंडा एक निशान की मंत्रणा में लग गये. इसके लिए मुलायम सिंह को अधिकृत किया गया. बातचीत का केंद्र बिहार चुनाव था. इसलिए सभी निर्णय आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किये जा रहे थे, लेकिन चुनाव के करीब आते-आते किसी तरह की सहमति नहीं बन पायी. खासकर सपा, जद(यू), और राजद के बीच मतभेद गहरा गये. हालांकि इन मतभदों को किसी तरह दूर करने की कोशिश की गयी. अंततः जब बात सीटों के बंटवारे की आई तो 243 सीटों में से राजद और जद(यू) ने 100-100 सीटें आपस में बांट लीं. 40 सीटें कांग्रेस को दे दी गईं और सबसे कम 3 सीटें सपा को दी गईं. सीटों के बंटवारे के विषय में महागठबंधन के प्रमुख मुलायम सिंह यादव से किसी तरह विचार-विमर्श किया गया. सीटों के बंटवारे की घोषणा के समय सपा का कोई नुमाइंदा भी उपस्थित नहीं था, जबकि कांग्रेस की ओर से सीपी जोशी उपस्थित थे. यह बात सपा को नागवार गुजरी और उसने महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया.

कौन कितना सीटों पर लड़ेगा

समाजवादी पार्टी	85
जन-अधिकार मोर्चा	64
एनसीपी	40
एसएसपी (नागमणी)	28
एसजेडी-डी (डीपी यादव)	23
एनपीपी (पीए संगमा)	03
कुल	243

सपा पहले भी बिहार में अलग से चुनाव लड़ती रही है. सपा के कई उम्मीदवार विधायक भी रहे हैं. ऐसे में उन्हें केवल पांच सीटें देना गलत था. इसके बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने एनसीपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही. धीरे से उनके साथ 4 और दल भी शामिल हो गये, जिसमें सबसे प्रमुख जन-अधिकार मोर्चा के संयोजक पप्पू यादव हैं. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की समरस समाज पार्टी(एसएसपी), पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का समाजवादी जनता दल(एसजेडी), पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) शामिल है.

तीसरा मोर्चा सोशलिस्ट सेक्युलर मोर्चा के नाम से चुनाव लड़ेगा, जिसकी कमान एनसीपी सांसद तारिक अनवर को सौंपी गई है. हालांकि तीसरा मोर्चा बिहार में अपनी जड़ें तलाश रहा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रचार में भूमिका प्रमुख होगी. अखिलेश यादव ने पिछले साढ़े तीन सालों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो प्रयास किये हैं, वह उसे बिहार के लोगों के सामने रखेंगे. सपा नेताओं का कहना है कि यदि बिहार में तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो यहां उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाया जाएगा. अखिलेश का कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन सकता है तो बिहार में क्यों नहीं. तीसरे मोर्चे का मुख्य फोकस है यादव और मुस्लिम वोट बैंक. जिस माय वोट पर आरजेडी बिहार में अपना आधिपत्य बताती रही है, तीसरा मोर्चा उसी वोट बैंक पर सेंध लगाने की फिराक में है. पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में लालू यादव व नीतीश कुमार के कुनबे के सफाये की शुरुआत हो गयी है. चुनाव के बाद पूरा कुनबा साफ हो जाएगा. बिहार में नयी ताकत के रूप में तीसरा मोर्चा उभर रहा है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में बिहार में तीसरी ताकत ने आकार ग्रहण किया है.

लोकसभा सांसद और एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि नीतीश व लालू का गठबंधन सुविधा का गठबंधन है, जिसे जनता नकार देगी. जनता गैर-कांग्रेस व गैर-भाजपा गठबंधन को स्वीकार करेगी. सांसद पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में लालू यादव व नीतीश कुमार के घमंड को तोड़ने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है. भाजपा की भी नहीं चलने दी जाएगी. तीसरा विकल्प भारत निर्माण का है और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में नए भारत के सपने को साकार करेगा. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से सपा 85, जन अधिकार पार्टी 64 सीटों पर, जबकि एनसीपी 40, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) तीन, समरस समाज पार्टी 28 और समाजवादी जनता दल राष्ट्रीय 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

तीसरे मोर्चे के एलान से न तो बीजेपी गठबंधन फिक्रमंद है और न ही महागठबंधन, लेकिन तीसरे मोर्चे के गठन से दूसरे दलों के टिकट न मिलने की वजह से असंतुष्ट उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के लिए एक नया विकल्प खड़ा हो गया है. ऐसे नेताओं ने तीसरे मोर्चे का दामन थामना भी शुरू कर दिया है. राजद के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे रघुनाथ झा औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये. सपा में शमिल होने के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था. ऐसे में तीसरे मोर्चे को अपने लिए उम्मीदवार तलाशने में कोई परेशानी नहीं होगी. इसके साथ ही दूसरे दलों के बागी उम्मीदवार अपने पुराने दल के लिए निश्चित तौर पर परेशानी खड़ी करेंगे.

तारिक अनवर को तीसरे मोर्चे ने बिहार में अपना चेहरा इसलिए भी बनाया है, ताकि मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके. इसका सीधा असर महागठबंधन पर पड़ेगा. कई बार पप्पू यादव कह चुके हैं कि तीसरा मोर्चा यदि बिहार में जीत हासिल करता है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम बनेगा. हालांकि सपा ने पप्पू यादव के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन तीसरा मोर्चा मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है. नीतीश-लालू को ठेंगा दिखाने के बाद बने तीसरे मोर्चे का दारोमदार भी सपा की यूपी सरकार की उपलब्धियों पर टिका है. ऐसे में अखिलेश द्वारा उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन साल में किए गए विकास को आधार बनाकर बिहार में पोस्टर लगाये जा रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तीसरा मोर्चा यूपी की तरह बिहार में भी विकास को तवज्जो देगा.

हालांकि तारिक अनवर और पप्पू यादव जमीनी नेता हैं, लेकिन बिहार में उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित है. ऐसे में इन दोनों नेताओं का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा. तीसरे मोर्चे को उन्हीं सीटों पर जीत हासिल होगी, जहां नेताओं की जमीनी पकड़ होगी. कुल मिलाकर लोग तीसरे मोर्चे को वोटकटवा पार्टी के रूप में देख रहे हैं, जो भले ही जीत हासिल न कर सके, लेकिन दूसरे दलों का खेल निश्चित तौर पर खराब करेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

Digital India
Power To Empower

डिजिटल इंडिया
डिजिटल मध्यप्रदेश

सहूलियतें आपके लिए :
- डिजिटल लॉकर
- एम.पी. मोबाइल एप के जरिये 120 सेवाएँ
- सरकारी काम-काज में तेजी के लिये एम.पी. ई-मेल सेवा
- 400 से अधिक वर्चुअल क्लास रूम की सुविधा
- 60 लाख, 40 हजार से ज्यादा डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र जारी
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 22 विभाग की 135 सेवाएँ
- एस.एम.एस. गेटवे के जरिये 9 करोड़ से अधिक एस.एम.एस.
- जी.आई.एस. लैब स्थापित।

मध्यप्रदेश में डिजिटल इंडिया की पहल

और अब नई पहल
- कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) की शुरुआत
- ई-शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत
- लगभग 1 करोड़ महिलाओं को पहुँचेगा लाभ
- ई-दक्ष
- ई-ऑफिस
- एक क्लिक पर संपत्ति का पंजीयन
- ई-ऑक्शन से रेत की नीलामी।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2015

तस्वीरों में यह सप्ताह

फोटो-पीटीआई व प्रभात पाण्डेय

1. नई दिल्ली में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा के टिकट के लिए रोते हुए अशोक गुप्ता. 2. नई दिल्ली में इंडियन एयर फोर्स(आईएएफ) आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के सदस्य 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के गोल्डन जुबली महोत्सव के अवसर पर रिहर्सल के दौरान. 3. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडु, नितिन गडकरी और चौधरी विरेंद्र सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. 4. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी कृष्णा बोस कोलकाता पुलिस म्यूजियम में नेताजी से संबंधित गोपनीय फाइल को देखते हुए. 5. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती नई दिल्ली में अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. 6. नई दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान सम्मान रैली के दौरान राहुल, सोनिया और मनमोहन सिंह. 7.एफटीआईआई के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ एफटीआईआई के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भारतीय लेखिका अरुंधती राय. .

निशाने पर पत्रकार

निखिल वागले

लोकतंत्र में सच के ख़िलाफ यह किसका षड्यंत्र है

गोवा के हिन्दुवादी सनातन संस्था के सदस्य समीर की गिरफ्तारी के बाद उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ जानकारी हासिल हुई. इस जानकारी से पता चला कि लोकमत के पूर्व संपादक निखिल वागले की जान को खतरा है. इसी के साथ एक और मराठी पत्रकार श्याम सुंदर सोनार की जान के खतरे को लेकर भी खबरें आईं. महाराष्ट्र में समाजवादी गोविंद पनसारे की हत्या के सिलसिले में सनातन संस्था के एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी के बाद निखिल वागले को लगातार धमकियां मिल रही हैं. वागले कहते हैं कि चार साल पहले उन्हें सनातन संस्था की ओर से धमकियां मिलीं थीं. सनातन संस्था से अभय वरतक उस कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चल दिए थे, जिसे वागले ने आयोजित किया था.

चौथी दुनिया ब्यूरो

कहते हैं, पत्रकार जनता की आवाज होते हैं, लेकिन जब पत्रकार की आवाज को ही दबाने की कोशिश हो, यहां तक कि उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगेगी तो तय मानिए कि लोकतंत्र का चौथा खंभा बस ढहने ही वाला है और किसी भी इमारत का एक खंभा ढह जाए, तो उस इमारत की हालत क्या होगी, इसका अन्दाजा आप खुद लगा सकते हैं. पिछले कुछ समय से देश के भीतर तार्किक बातें करने वाले लोगों, सच कहने वाले पत्रकारों और सही आलोचना करने वाले लोगों को धमकियां मिल रही हैं. जान से मारने की धमकी दी जा रही है. हालांकि, इसमें वैसे पत्रकार शामिल नहीं हैं, जो सरकार की नीतियों में कसीदे पढ़ते हैं. इसमें वैसे पत्रकार भी शामिल नहीं हैं, जो हवा के रुख के मुताबिक अपनी पीठ फेरने में उस्ताद हैं और जो येन-केन-प्रकारेण सत्ता की गलियारों में घुसपैठ करने में माहिर हैं. इन धमकियों के शिकार बस ऐसे पत्रकार हो रहे हैं, जो सरकार की नीतियों, उन्मादी संगठनों के कुकृत्यों के खिलाफ बोलते या लिखते हैं. ताजा उदाहरण मुम्बई का है. गोवा के हिन्दुवादी सनातन संस्था के सदस्य समीर की गिरफ्तारी के बाद उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ जानकारी हासिल हुई. इस जानकारी से पता चला कि लोकमत के पूर्व संपादक निखिल वागले की जान को खतरा है. इसी के साथ एक और मराठी पत्रकार श्याम सुंदर सोनार की जान के खतरे को लेकर भी खबरें आईं.

महाराष्ट्र में समाजवादी गोविंद पनसारे की हत्या के सिलसिले में सनातन संस्था के एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी के बाद निखिल वागले को लगातार धमकियां मिल रही हैं. वागले कहते हैं कि चार साल पहले उन्हें सनातन संस्था की ओर से धमकियां मिलीं थीं. सनातन संस्था से अभय वरतक उस कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चल दिए थे, जिसे वागले ने आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में तब नरेन्द्र डाभोलकर भी शामिल थे. इस कार्यक्रम के दौरान पैनल और वागले के बीच काफी तीखी बहस हुई थी. इसके बाद, सनातन संस्था ने निखिल वागले का फोन नंबर सार्वजनिक कर अपने समर्थकों से निखिल वागले का विरोध करने की अपील की थी. इस संस्था की सनातन प्रभात पब्लिकेशन में वागले को चेतावनी देते हुए एक लेख भी छापा गया. वागले के मुताबिक, कुछ ही दिन पहले मुम्बई के पुलिसकर्मी उनके पास आए और कहने लगे कि उन्हें सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है. वागले का कहना है कि मैं एक पत्रकार हूं. मैं सुरक्षा के साथ भला कैसे काम कर सकता हूं. सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है. उन्होंने कहा कि उन्हें सनातन संस्था की ओर से ट्विटर के जरिए और संस्था के मुखपत्र सनातन प्रभात के जरिए भी धमकी दी गई है. मराठी अखबार प्रहार के पत्रकार श्याम सुंदर सोनार ने भी गोविंद पनसारे की हत्या को लेकर काफी कुछ लिखा है और अपने परिवार के लिए पुलिस को पत्र लिखकर सिक्योरिटी की मांग की है.

सनातन संस्था से जुड़े समीर गायकवाड़ को पानसारे की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. कोल्हापुर पुलिस ने गायकवाड़ से पूछताछ की है और इसी के बाद से यह जानकारी हासिल हुई कि इन लोगों के निशाने पर अब निखिल वागले जैसे पत्रकार भी हैं. 16 फरवरी, 2015 को 82 वर्षीय पनसारे की मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनके घर के पास कोल्हापुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पनसारे की मौत के पीछे संदिग्ध कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था के सदस्य समीर गायकवाड़ को कथित तौर पर फोन पर यह कहते हुए सुना गया कि पनसारे के बाद अगला नंबर वागले का है. मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब तक पत्रकार पूरी तरह से स्वतंत्रत नहीं हो पाए. खबर के नाम पर राजनेताओं द्वारा पत्रकारों पर बनाया जाने वाला दबाव, कोर्ट केस, मानहानि के केस के अलावा अब तो सीधे उन्मादी संगठनों द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है. समाज में दबे-कुचले लोगों की आवाज उठाने में पत्रकार अहम रोल निभाते हैं, लेकिन पत्रकारों की आवाज को ही दबाने की कोशिश की जा रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

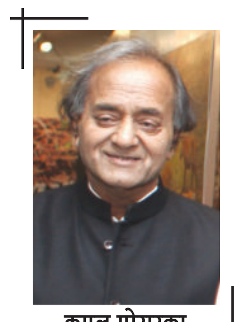
कमल मोरारका

बिहार चुनाव हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. आरएसएस प्रमुख ने एक बयान जारी किया कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए. ये बहुत ही ग़लत सोच है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए. ये कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा आरएसएस द्वारा संचालित होती है, इसीलिए ये बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

आरक्षण ख़त्म करने की सोच ग़लत है

पिछले दिनों की सबसे बड़ी ख़बर भारतीय क्रिकेट के अगुआ जगमोहन डालमिया का निधन है. मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानता था. मैं उनकी क्षमता, कार्यशैली, जोशीले व्यक्तित्व और बेहतर प्रशासनिक क्षमता का कायल रहा हूं. कई मौके ऐसे आए, जिनमें वे कोई ख़ास फैसले ले सकते थे, लेकिन बुद्धिमता की बात यह थी कि क्रिकेट के दीर्घकालिक हित के लिए वैसे फैसले सही नहीं थे. इसलिए उन्होंने वे फैसले नहीं लिए. इसलिए उन्होंने ऐसे मौकों को जाने दिया, जब वे अपने पसन्द के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा सकते थे. क्रिकेट एक प्रतिस्पर्द्धात्मक खेल है. भारत में क्रिकेट प्रशासन खेल से भी ज्यादा प्रतिस्पर्द्धात्मक है. हर कोई किसी न किसी पद के पीछे भाग रहा है. किसी भी लोकतांत्रिक संस्था में चुनाव होते हैं, लेकिन क्रिकेट की संस्थाओं का चुनाव अलग तरह का हो गया है. मुझसे उनकी जितनी भी बातचीत हुई, उससे मुझे लगा कि वे क्रिकेट का व्यापक हित चाहते थे, न कि कोई तात्कालिक लाभ. मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी ग़लत या आधी-अधूरी जानकारी थी, जिसका इस्तेमाल उनके महत्व को घटाने के लिए किया गया. लेकिन, उन्होंने इस सब का बहादुरी से मुकाबला किया. बीसीसीआई की तरफ से ही उन्हें अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया था और उन्हें दोनों पक्षों ने निर्विरोध बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया. हालांकि, वे 75 साल के थे, लेकिन यह उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती. लेकिन, जब तक वे जिये, अपने जीवन को प्रतिष्ठा के साथ जिये और प्रतिष्ठा के साथ इस दुनिया से रुख़सत हुए. यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान देते हुए अंतिम विदाई दी. उनके परिवार के लोग उनके दोस्त और समर्थक शोकाकुल हैं. हम आशा करते हैं कि चीजें सही दिशा में जाएंगी और क्रिकेट प्रशासन सही हाथों में जाएगा.

दूसरा बिन्दु यह है कि प्रधानमंत्री विदेशी भूमि को व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त समझते हैं. पिछले दिनों उन्होंने आयरलैंड में ऐसी टिप्पणी की, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी. बेहतर होता कि ऐसी टिप्पणी वे भारत की धरती पर करते, न कि पिछली सरकारों की भर्त्सना करने या उसके महत्व को कम करने के लिए विदेशी ज़मीन पर ऐसी टिप्पणी करते, लेकिन जो आदत होती है, वह बहुत मुश्किल से जाती है. मुझे शक है कि उन्हें मालूम हैं कि कुछ राजनीतिक मापदंड होते हैं, जिनका पालन करना चाहिए.

दरअसल, आरएसएस अक्सर यह कहती है कि वह राजनीति में नहीं है. यानी कि अराजनीतिक है, इसलिए वो चुनाव के नतीजों की परवाह नहीं करते या इसका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. लेकिन, मुझे नहीं मालूम कि दोनों के बीच में किस तरह की सहमति है. लेकिन, अगर वे आरक्षण पर गंभीर बहस चाहते हैं तो ये एक अलग तरह के प्रारूप और अलग समय में सामने आना चाहिए.

बिहार चुनाव हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. आरएसएस प्रमुख ने एक बयान जारी किया कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए. ये बहुत ही ग़लत सोच है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए. ये कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा आरएसएस द्वारा संचालित होती है, इसीलिए यह बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

चुनावी सन्दर्भ में बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि अगर आप आरक्षण ख़त्म करेंगे, तो पिछड़े वर्ग के लोग आहत होंगे. वो आपको वोट नहीं देंगे. दरअसल, आरएसएस अक्सर यह कहती है कि वह राजनीति में नहीं है, यानी कि अराजनीतिक है, इसलिए वह चुनाव के नतीजों की परवाह नहीं करते या इसका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. लेकिन, मुझे नहीं मालूम कि दोनों के बीच में किस तरह की सहमति है. लेकिन, अगर वे आरक्षण पर गंभीर बहस चाहते हैं, तो ये एक अलग तरह के प्रारूप और अलग समय में सामने आना चाहिए. अगले दो सप्ताह में देखते हैं, क्या होता है? बिहार में कुछ दिलचस्प चीजें सामने आएंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी हर तरह के दांव अपनाएगी. साम-दाम-दंड-भेद यानी हर तरह के तरीक़े और सेक्युलर ताक़तें उनका विरोध करेंगी. देखते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

फूलन को आत्मसमर्पण करने से किसने रोका?

बेहमई कांड की खलनायिका फूलन पुलिस की गोली से नहीं मरना चाहती थी, वह आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन जीना चाहती थी. मलखान के बाद उन दिनों मध्यभारत का नंबर एक डाकू घनश्याम भी अपराधी जिन्दगी सदा के लिए छोड़ना चाहता था. बहुत संभव था कि 17 नवंबर 1982 को जालौन जिले के रामपुरा कस्बे में आयोजित इनका समर्पण समारोह एक हकीकत में बदला जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अस्पष्ट डाकू नीति तथा पुलिस अधिकारियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण सब कुछ धरा का धरा रह गया और डाकू फिर जंगलों में लौट गए.

चम्बल घाटी की स्त्री डाकुओं की श्रृंखला में पुतली के बाद सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली फूलन आज चम्बल, कुंआरी, पहुज, यमुना और सिंध नदियों के किनारे-किनारे भटक रही है. वह अपनी जिंदगी को एक सभ्य मोड़ देना चाहती है, पर मौत उसका पीछा कर रही है. वह चाहकर भी प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर पा रही है. विडम्बना तो यह है कि उसके लिए मौत का प्रावधान उन्हीं के द्वारा किया गया है, जिन्होंने उसे डाकू बनाया, जिन्होंने उसके औरत होने के एहसास को वेश्या होने के एहसास में बदला.

फूलन कैसे डाकू बनी, इसके बारे में रविवार ने देश भर में सबसे पहले प्रमाणिक जानकारी पाठकों के सामने रखी. किस तरह उसके चचेरे भाइयों ने उसके पिता की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, फूलन द्वारा विरोध करने पर उसके चचेरे भाइयों ने उसे चोरी के झूठे आरोप में थाने में बन्द करा दिया था, किस तरह थाने में उसके साथ बलात्कार किया गया, किस तरह उसकी ज़मानत करानेवालों ने उसका यौन शोषण किया तथा किस तरह बाबू गूजर उसे जबरदस्ती उठा ले गया-यह सब अब कोई अनकही कहानी नहीं रही. फूलन के नाम के आगे अपराधों की कोई लंबी सूची भी नहीं जुड़ी है-सिर्फ एक बेहमई हत्याकांड के. लेकिन बेहमई की भी अपनी एक पृष्ठभूमि है.

जब बाबू गूजर फूलन को बन्दूक की नोक पर उठा ले गया, तो उसने बलात्कार तो किया ही, फूलन को बिल्कुल नंगा कर पूरे गिरोह के सामने ज़मीन पर लेटने को मजबूर भी किया. इससे बौखला कर विक्रम ने बाबू गूजर की हत्या कर दी. इसी गिरोह के लालाराम-श्रीराम ने फूलन को विक्रम के खिलाफ बरगलाने की कोशिश की, पर फूलन ने विक्रम को धोखा देने से इनकार कर दिया. गिरोह न टूटे, इसलिए उसने इस घटना का विक्रम से जिक्र तक नहीं किया, और यही उसकी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई. लालाराम-श्रीराम ने विक्रम की हत्या कर दी तथा फूलन को बन्दूक की नोक पर बेहमई गांव ले आए. यहां उसे सबके उपहास का पात्र बनना पड़ा. पुरुष तो पुरुष, औरतें तक मल्लाहिन कहकर उसका तिरस्कार करती थीं. जिस कोठरी में उसे बन्द करके रखा गया था, उसमें रोज रात को, कभी-कभी तो दोपहर में भी, पांच से सात आदमी उसके साथ बलात्कार करते थे. एक उसे रौंदता, तो बाकी सब पाशविकता से उसे नोचते तथा हंसते.

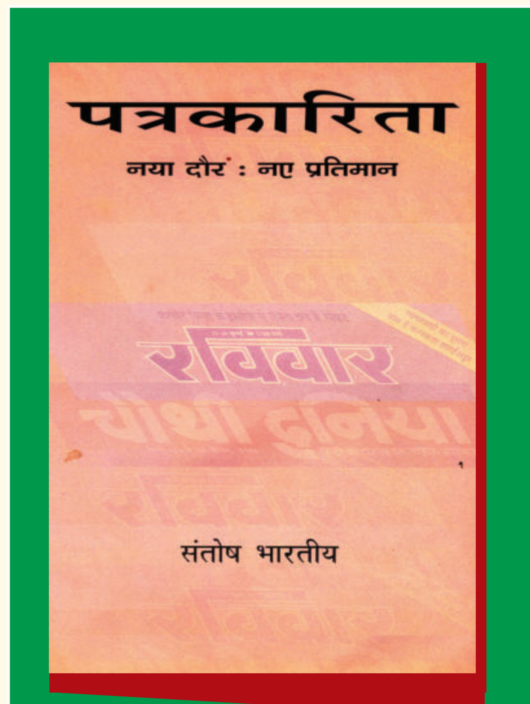

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

ग्याहर दिन तक यह बर्बर सिलसिला जारी रहा. एक शाम वह शौच के लिए यमुना किनारे गई. तीन आदमी उसकी पहरेदारी कर रहे थे. फूलन ने अचानक नदी की तरफ दौड़ना शुरू किया. वे तीनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, लेकिन इसके पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वह नदी में कूद चुकी थी. पीछा करने वाले तीनों व्यक्ति झिझक गए और फूलन नदी के दूसरे किनारे बसे मल्लाह के गांव पालगांव में माताप्रसाद के घर पहुंच गई. फूलन को शरण देने के अपराध का प्रायश्चित माताप्रसाद को अभी दो महीने पहले ही करना पड़ा, जब लालाराम-श्रीराम ने पालगांव पहुंच कर उसकी हत्या कर दी.

यहीं अपमानित, बलत्कृत फूलन बदले की आग लिए बेहमई पहुंची तथा उसने चुन-चुन कर उन सबको गोली मार दी, जिन्होंने उसे लांछित और अपमानित किया था. वह लालाराम-श्रीराम को भी तलाश रही थी, पर वे कायरों की तरह भाग गए थे. इस घटना के बाद फूलन फिर शांत हो गई. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसके खिलाफ युद्ध ही छेड़ दिया. उस समय का शक्तिशाली दस्यु-सरदार मलखान भी फूलन के खिलाफ हो गया.

फूलन के विरुद्ध पुलिस ने अपने सम्पर्क के पत्रकारों के माध्यम से कई कहानियां प्रचारित कराई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि नीच जाति की होने के कारण वह चरित्रहीन भी थी. उसके साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया, बल्कि उसी ने सबको यौन निमंत्रण दिया. दूसरी कहानी है फूलन की क्रूरता की कि कैसे वह डाकों में जाती है तथा अपनी आंखों के सामने औरतों पर बलात्कार कराती है. तीसरी यह कि वह कोई हैसियत ही नहीं रखती, सिवाय एक रखैल के. इन सबके पीछे साजिश यह है कि फूलन के प्रति लोगों के मन में इतनी घृणा पैदा हो जाए कि जब फूलन मारी जाए, तो किसी के मन में उसके प्रति कण भर भी सहानभूति न हो.

हालांकि इस सबका वास्तविक कारण यह है कि फूलन यदि जिन्दा पकड़ ली जाती है, तो हो सकता है वह पुलिस तथा समाज के तथाकथित भद्रपुरुषों की कलई खोल दे. यही डर फूलन के आत्मसमर्पण में बाधक है, यद्यपि फूलन ने इसके लिए कई बार कोशिश की है. नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में फूलन का आत्मसमर्पण लगभग तय था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अस्पष्ट डाकू नीति तथा पुलिसवालों में मौजूद भयंकर विभागीय प्रतिस्पर्धा के कारण न केवल उसका, बल्कि मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में फिलहाल दस्यु-आतंक की प्रतिमूर्ति घनश्याम का आत्मसमर्पण भी पूरी तैयारी के बावजूद नहीं हो सका. हजारों नागरिकों, पत्रकारों व पुलिस अधिकारियों को रामपुरा(जालौन) से निराश लौटना पड़ा तथा उक्त दोनों डकैत एक बार फिर बीहड़ों में वापस चले गए. इस घटना के साथ ही इन दो कुख्यात अपराधियों को अपनी जिन्दगी को नए सिरे से शुरू करने का अवसर भी नहीं मिल सका. अब सबकी जुबान पर यही सवाल है कि यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह श्रीपति मिश्र की वर्तमान सरकार भी डाकुओं के आत्मसमर्पण की नीति में विश्वास नहीं रखती, तो उसे इन डकैतों से समर्पण की बात ही नहीं करनी चाहिए थी. इस मामले में ढुलमुल नीति अपनाने से तो स्थिति और बदतर ही होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकार की असंवेदनशीलता इन मौतों की वजह है

मुझे सनील दत्त जी याद हैं, जिनकी मौत ऐसी ही बीमारी की वजह से हुई थी. सुनील दत्त के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. इसलिए जरूरत इस बात की है कि दिल्ली ही नहीं, सारे देश में, क्योंकि दिल्ली तो नमूना है, जहां कुछ हो ही नहीं रहा, सफाई, मच्छर, बैक्टीरिया को लेकर और आने वाली बीमारी के बचाव में क्या-क्या किया जा सकता है, इसको लेकर चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है. अफसोस की बात यह है कि न सरकार चिंतित है, न मीडिया चिंतित है. अब तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया ने अस्पतालों के हालात के ऊपर भी नजर डालना बंद कर दिया है, क्योंकि नजर डालेंगे, तो सरकार को थोड़ी परेशानी होगी, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो.

अभी तक डेंगू के ऊपर सरकार कारगर ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है. जैसे डेंगू की दवाएं, प्लेटलेट्स की व्यवस्था. डेंगू जिन्हें हो चुका है, उनके लिए बिस्तर और डेंगू की जांच वैसी की वैसी महंगी चल रही है. सरकार के ऑर्डर को कोई नहीं मान रहा है. सरकार इनइफेक्टिव हो गई है. चाहे वह मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार. इस बीमारी की वजह से जिनकी मृत्यु हो रही है, उनकी लाश तब तक अस्पताल नहीं दे रहे हैं, जब तक उन्हें इलाज का पूरा पैसा नहीं मिल जाता. टेस्ट किट अभी भी महंगी ही है.

दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीज को दाखिल करने के लिए बिस्तर नहीं है. बड़े अस्पताल मैक्स हों, अपोलो हों या छोटे अस्पताल, हर जगह से लोगों को भगाया जा रहा है. एक बच्चे को लेकर 6 से 7 घंटे तक उसके मां-बाप अस्पताल-दर-अस्पताल घूमते रहे. उस बच्चे की मौत हो गई और अपने बच्चे को न बचाने के दुख में मां-बाप ने भी आत्महत्या कर ली और उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया. पर ये वो सिलसिला है, जो कैमरे की नजर में आ जाता है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो डेंगू से पीड़ित हैं, जो अस्पताल की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये ख़बर है कि अस्पताल बच्चों को अपने यहां भर्ती नहीं कर रहे हैं. सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माना लगाने की ताक़त है, अधिकार है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब अस्पतालों को एक नोटिस भेजते हैं और कहते हैं कि एक महीने के भीतर इसका जवाब दीजिए. ये है संवेदनशीलता का आज का नमूना. दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार डेंगू जैसी बीमारी को लेकर असंवेदनशीलता दिखा रही हैं. इसके अलावा दिल्ली वो जगह है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी. साल भर में दिल्ली साफ नहीं हो पाई और सालभर में उन संस्थाओं की जिम्मेदारी भी तय नहीं हुई, जिनके ऊपर दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी थी और जो सालभर के भीतर हम नागरिकों में भी ये भावना नहीं भर पाए कि किस तरीक़े से हम सफाई करें.

अभी हम डेंगू के बारे में कुछ नहीं कर पाए, सरकारें कुछ नहीं कर पाईं और एक नया ख़तरा स्वाइन फ्लू का आ रहा है. अख़बारों और टीवी चैनलों ने स्वाइन फ्लू को लेकर चेतावनी दी है और ये चेतावनी सूचना के आधार पर सत्य साबित होती है. मुझे पूरा विश्वास है कि जब स्वाइन फ्लू फैल जाएगा, जब लोग मरने लगेंगे, तब सरकार चेतेगी और उसके बारे में कोई रणनीति बनाएगी. दरअसल, हमारे यहां प्रीकॉशन की या लोगों को चेतावनी देने की या लोगों को समझाने की या लोगों को सलाह देने की कोई व्यवस्था है ही नहीं. सरकार के सारे विभाग निकम्मे साबित हो रहे हैं. सरकार नाम की संस्था चाहे मोदी सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, हालांकि दिल्ली सरकार केन्द्र सरकार के अधीन ही है, पूरी तौर पर नकारा साबित हो रही हैं.

मुझे कल एक बड़ी गंभीर बात किसी ने कही. उसने कहा आज से तीस साल पहले या चालीस साल पहले एक विभाग बना था मलेरिया डिपार्टमेंट, जिसके जिम्मे मच्छर मारने का काम था. आपमें से बहुत लोगों को याद होगा और दीवारों पर लिखते थे, न मच्छर रहेगा, न मलेरिया रहेगा. थोड़े दिनों बाद वहां लिखना शुरू हुआ मच्छर तो रहेंगे, पर मलेरिया नहीं रहेगा. और मलेरिया कहां छूट गया पीछे, अब तो उससे बड़ी-बड़ी

अभी हम डेंगू के बारे में कुछ नहीं कर पाए, सरकारें कुछ नहीं कर पाईं और एक नया ख़तरा स्वाइन फ्लू का आ रहा है. अखबारों और टीवी चैनलों ने स्वाइन फ्लू को लेकर चेतावनी दी है और ये चेतावनी सूचना के आधार पर सत्य साबित होती है. मुझे पूरा विश्वास है कि जब स्वाइन फ्लू फैल जाएगा, जब लोग मरने लगेंगे, तब सरकार चेतेगी और उसके बारे में कोई रणनीति बनाएगी. दरअसल, हमारे यहां प्रीकॉशन की या लोगों को चेतावनी देने की या लोगों को समझाने की या लोगों को सलाह देने की कोई व्यवस्था है ही नहीं.

बीमारियां जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू आ गई हैं. कुछ ऐसे वायरल हैं, जिनका नाम हमें नहीं मालूम है. ये गंदगी और मच्छर की वजह से होते हैं. 67 साल की सफाई अभियान में लोगों की अरुचि, सरकार की काहिली, सफाई के ऊपर ध्यान देने वाले विभागों का बिल्कुल निष्क्रिय होना, हमारे सामने महामारी का ख़तरा देश में पैदा हो गया है. आबादी कम करने का अगर ये इलाज सरकार सोचती है, तो ये बहुत ख़तरनाक इलाज है, क्योंकि इसमें उनकी भी मौत हो सकती है, जो बड़े घरों के रहने वाले हैं. मुझे सनील दत्त जी याद हैं, जिनकी मौत ऐसी ही बीमारी की वजह से हुई थी. सुनील दत्त के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दिल्ली ही नहीं, सारे देश में, क्योंकि दिल्ली तो नमूना है, जहां कुछ हो ही नहीं रहा, सफाई, मच्छर, बैक्टीरिया को लेकर और आने वाली बीमारी के बचाव में क्या-क्या किया जा सकता है, इसको लेकर चुस्त और दुरुस्त होने की ज़रूरत है. अफसोस की बात यह है कि न सरकार चिंतित है न मीडिया चिंतित है. अब तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया ने अस्पतालों के हालात के ऊपर भी नजर डालना बंद कर दिया है, क्योंकि नजर डालेंगे, तो सरकार को थोड़ी परेशानी होगी, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो. परेशानी होगी तो टेलीविजन चैनल को परेशानी होगी, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलेंगे. यही हाल अख़बारों का है. लेकिन आप लोग सरकार में नहीं हैं. आप सरकार की इस काहिली के शिकार हैं या इन बीमारियों के सबसे ज्यादा शिकार हैं. आपसे मेरी अपील है कि आप लोग खड़े हों, खड़े होकर अपने आस-पास गंदगी के ख़िलाफ़ लड़ने की योजना बनाएं. अगर आप नहीं बनाएंगे तो निश्चित मानिए, जिनके पास साधन नहीं हैं, ज्यादा मौंते उनकी होती हैं. साधन का मतलब, जो अपोलो में नहीं जा सकते, मैक्स में नहीं जा सकते, मेदान्ता में नहीं जा सकते, ऐसे 90 प्रतिशत लोग हमारी दिल्ली में हैं और देश में हैं. बड़े अस्पतालों में भी जगह नहीं है और अगर जगह है, तो आधे घंटे के तीन-तीन लाख रुपये ले रहे हैं. आपमें से पांच प्रतिशत शायद ये पैसा दे सकते हों, पर 95 प्रतिशत ये पैसा नहीं दे सकते और ज्यादा मौत इन 95 प्रतिशत लोगों के घरों में हो रही हैं. इसलिए निर्भरता छोड़िए, क्योंकि जान सबसे कीमती चीज है. अपने यहां टोलियां बनाइए. अपने ग्रुप्स बनाइए. सफाई के प्रति पूरे मोहल्ले को जागरूक कीजिए. गांव को जागरूक कीजिए और गंदगी के ढेरों को समाप्त कीजिए. मैं जानता हूं, सरकार के पास गंदगी के निपटारे की कोई योजना नहीं है. कूड़ा इकट्ठा होगा. वहीं सड़ता रहेगा, वो उठकर कहां जाएगा. ये किसी को नहीं पता. पर फिर भी जितना कर सकते हों, जितना अपना दिमाग लगा सकते हों, उतना लगाइए. मैं जानता हूं कि आपमें से बहुत सारे नौजवान, ख़ासकर छात्रों के दिमाग में अगर ये बात घर कर जाए कि कूड़े का हमको क्या इस्तेमाल करना है, तो ये समस्या हल हो सकती है. सरकार ये नहीं सोचेगी. सरकार मौत देने में ज्यादा रुचि रखती है, बजाय बचाने के. ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वह तब जागती है, जब मौंते शुरू हो जाती हैं. इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, बल्कि अनुरोध कर रहा हूं कि आप जागें और आप खड़े हों, यह अतिआवश्यक है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

भारतीय लोकतंत्र को किसने कमज़ोर किया

यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया जेरेमी कोबिन को एक वैधता प्रदान करती है. यह वैधता अगले आम चुनावों में उनके नाकाम होने की आशंकाओं को भी ख़ारिज करती है. इस चुनाव में केवल 10 प्रतिशत सांसदों ने कोबिन को वोट दिया. दरअसल, कोबिन ने उन पुराने समाजवादी विचारों का सहारा लिया, जो जनता का वोट हासिल करने में रुकावट साबित हुए हैं. अब इसे देख कर ऐसा कहा जा सकता है कि या तो दुनिया बदल गई है और कोबिन उस जनता का वोट हासिल करके सबको हैरान कर देंगे, जो पहले ऐसे विचारों के प्रति उदासीन थी या लेबर पार्टी 2020 में एक बार फिर हार जायेगी.

जिस पार्टी से मैं पिछले 44 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी ने अभी-अभी अपना नया नेता चुना है. मई 2015 में लेबर पार्टी के चुनाव हारने के अगले ही दिन पार्टी नेता एड मिलिबैंड ने त्यागपत्र दे दिया था. नए नेता के चुनाव की एक प्रकिया है, जिसके तहत पार्टी के सांसद उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं. इस बार चार उम्मीदवारों का नामांकन हुआ था. उपनेता के चुनाव में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनाई जाती है. इन उम्मीदवारों ने पूरे देश में पार्टी सदस्यों की 35 सभाएं कीं, आपसी वाद-विवाद के साथ-साथ सदस्यों के सवालों के जवाब दिए. इस बार लेबर पार्टी ने जेरेमी कोबिन को नेता चुना. वह पार्टी के अति वामपंथी विचारधारा के लोगों में से हैं. उन्होंने अक्सर पार्टी अनुदेश (व्हिप) का उल्लंघन किया है. (ब्रिटेन में भारत के विपरीत एक सांसद को अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने विचार रखने की आज़ादी है.) कोबिन को कुल चार लाख मतों में से 60 प्रतिशत मत हासिल हुए, यह हालिया कुछ वर्षों में किसी पार्टी नेता पद के उम्मीदवार को मिले सर्वाधिक मत हैं.

यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया जेरेमी कोबिन को एक वैधता प्रदान करती है. यह वैधता अगले आम चुनावों में उनके नाकाम होने की आशंकाओं को भी छ ारिज करती है. इस चुनाव में केवल 10 प्रतिशत सांसदों ने कोबिन को वोट दिया. दरअसल कोबिन ने उन पुराने समाजवादी विचारों का सहारा लिया, जो जनता का वोट हासिल करने में रुकावट साबित हुए हैं. अब इसे देख कर कहा जा सकता है कि या तो दुनिया बदल गई है और कोबिन उस जनता का वोट हासिल करके सबको हैरान कर देंगे, जो पहले ऐसे विचारों के प्रति उदासीन थी या लेबर पार्टी 2020 में एक बार फिर हार जायेगी. साथ में ये संभावना भी है कि पार्टी के सांसद चुनाव से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दें.

ब्रिटेन में पार्टी के नेता चुने जाने की प्रक्रिया और भारत में पार्टियों के नेता चुने जाने की प्रक्रिया में बहुत फर्क है. भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल वंशवाद के इर्द-गिर्द घूमते हैं. पार्टी नेता के चुनाव में न तो कोई सार्वजनिक बहस होती है, न किसी तरह का चुनाव होता है और न ही सदस्यों की भगीदारी होती है. यहां तक कि पिछले दिनों माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था. यह नेतृत्व परिवर्तन मतदान से नहीं हुआ था. ग़ौरतलब है कि सीताराम येचुरी, प्रकाश करात की जगह पार्टी के महासचिव बने थे. भाजपा में वंशवाद नहीं है. पार्टी के पास एक अनौपचारिक प्राइमरी है, जिसने नरेन्द्र मोदी को लोकसभा चुनावों में अपना नेता घोषित किया था. लेकिन वहां भी किसी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया था, ताकि आगे के कार्यक्रमों में पार्टी के नेता पद के उम्मीदवारों के बीच वाद-विवाद हो सके. यहां भी पार्टी के सदस्यों को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं है.

भारतीय चुनाव प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है, लेकिन यहां पार्टी उम्मीदवारों और पार्टी के नेता का चुनाव बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से होता है. इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को दलबदल विरोधी कानून से और भी मजबूती मिलती है. इस कानून के मुताबिक एक सांसद पार्टी अनुदेश से अलग अपनी राय नहीं रख सकता. यहां जनप्रतिनिधि मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वे अपने पार्टी के नेता के हितों साधने का काम करते हैं.

हालांकि भारतीय चुनाव प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है, लेकिन यहां पार्टी उम्मीदवारों और पार्टी के नेता का चुनाव बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से होता है. इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को दलबदल विरोधी कानून से और भी मजबूती मिलती है. इस कानून के मुताबिक एक सांसद पार्टी अनुदेश से अलग अपनी राय नहीं रख सकता. यहां जनप्रतिनिधि मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वे अपने पार्टी के नेता के हितों को साधने का काम करते हैं. दरअसल, उन्हें भेड़-चाल चलने पर आसानी से मजबूर किया जा सकता है. वे तार्किक रूप से किसी को अपनी बात मनवा सकें या अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें, भारत में ऐसा नहीं होता है. 1950 के दशक में भारत में एक जीवंत राजनीतिक और लोकतांत्रिक सोच विद्यमान थी. उस समय यहां कद्दावर सांसद थे, जिन्होंने नेहरू सरकार से जवाब-तलब किया. वह जीवटता कहां गुम हो गई? भारतीय लोकतंत्र को किसने कमज़ोर किया? क्या नेहरू के वारिस इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? ■

feedback@chauthiduniya.com

जब अगरू का वृक्ष 21 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है, तब इसकी लकड़ी पकने लगती है. किसी-किसी के मत से इसके परिपक्व होने के लिए 50 से 60 वर्ष लगते हैं. पकने के पहले इसकी लकड़ी बहुत साधारण पीत वर्ण की, गंधरहित होती है. इन लकड़ियों को काटकर अगर के नाम से बेचा जाता है. उक्त रस लकड़ी में जितना अधिक होता है, लकड़ी उतनी उत्तम और भारी होती है.

जीवाणुरोधी होता है अगरू

परिचय

यह बड़ा तथा सदा हरा-भरा रहने वाला वृक्ष है. अगरू की प्रसिद्धि अत्यन्त प्राचीन काल से है. चरक संहिता में शिरोवेदनाहर एवं शीतहर प्रलेपों में तथा शीतऋतुचर्या में इसके प्रलेप और अनुलेपन का उल्लेख किया गया है. प्राचीन काल में भारत वर्ष में इस द्रव्य का अत्यन्त महत्व था. कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस द्रव्य के व्यापार का बड़ा व्यापक व्यापार का वर्णन प्राप्त होता है.

वाह्य स्वरूप

अगरू का वृक्ष लगभग 18-20 मी ऊंचा, सदैव हरा-भरा रहने वाला, टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं से युक्त होता है. इसकी छाल कोमल हलकी लचीली, कागज के समान पतली, श्वेत अथवा हलकी पीताभ-श्वेत वर्ण की होती है. इसके फल 2.5 सेमी लंबे सूखने पर झुरींदार होते हैं. इसके पुष्प और फल नवम्बर से मई तक प्राप्त होते हैं.

विशेष

जब अगरू का वृक्ष 21 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है, तब इसकी लकड़ी पकने लगती है. किसी-किसी के मत से इसके परिपक्व होने के लिए 50 से 60 वर्ष लगते हैं. पकने के पहले इसकी लकड़ी बहुत साधारण पीत वर्ण की, गंधरहित होती है. इन लकड़ियों को काटकर अगर के नाम से बेचा जाता है. उक्त रस लकड़ी में जितना अधिक होता है, लकड़ी उतनी उत्तम और भारी होती है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- अगरू रस में कटु, तिक्त, कटु विपाक, उष्ण वीर्य; लघु व स्निग्ध तीक्ष्ण गुणयुक्त होता है. यह कफवात शामक व पित्तवर्धक होता है.
- अगरू सुगंधित, लेप लगाने पर शीतल, हृद्य, रुचिकारक, श्वासहर, शीतप्रशामक, शिरोविरेचक, मेदशोषक तथा वर्णप्रसादक होता है.
- इसका प्रयोग कर्णरोग, अक्षिरोग, कुष्ठ, हिक्का, छर्दि. श्वास, मेह, पाण्डु, कण्डू, पिडिका, कोठ तथा विष-विकारों की चिकित्सा में किया जाता है.
- कृष्णागुरु-कटु, तिक्त रस युक्त, उष्ण वीर्य; किंचित त्रिदोषशामक तथा विशेषकर पित्तशामक होता है व इसका लेप शीतल होता है.
- काष्ठागुरु- कटु रस; उष्ण वीर्य युक्त तथा कफ शामक होता है तथा इसका लेप रूक्ष होता है.
- दाहागुरु- कटु रस; उष्ण वीर्य; केशवर्धक, वर्णकारक तथा केश विकार शामक होता है.
- मंगल्यागुरु- शीत, गुरु; योगवाहि तथा कुष्ठ निवारण में प्रशस्त है.
- अगुरु-सार के स्नेह-कटु, तिक्त, कषाय रसयुक्त, उष्ण, वातकफशामक व दुष्ट व्रण शोधक, कृमि तथा कुष्ठ नाशक होता है. इसका धूम सुगन्धित एवं वात शामक होता है.
- श्रेष्ठ अगरु के गुण-श्रेष्ठ अगरु जल में डूबने वाला होता है.
- परखनलीय परीक्षण में यह मानव नासा ग्रसनी कर्कटार्बुद कोशकाओं पर कार्य करता है.
- इसका ऐथिल एसीटेट सार अनॉक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है.
- इसका पत्र-सार जीवाणुरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग:

1. शिर:शूल- अगरू की लकड़ी को चन्दन की तरह घिसकर उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर मस्तिष्क पर लेप करने से शिर:शूल में लाभ होता है.

वृक्ष रोग :

1. कास-1-3 ग्राम अगुरू चूर्ण में थोड़ा-सा सोंठ मिलाकर मधु के साथ सेवन करने से कफज कास में लाभ होता है.
2. श्वासनलिका शोथ-अगुरू चूर्ण तथा कपूर को पीसकर वक्ष स्थल पर लेप करने से श्वास-नलिका शोथ में लाभ होता है.
3. श्वास-ताम्बूल पत्र में 2 बूंद अगरू तैल को डालकर सेवन करने से श्वास रोग में शीघ्र लाभ होता है.

उदय रोग:

1. अर्बुद- अगुरु काष्ठ को लगभग 10 ग्राम लेकर उसका क्वाथ बनाकर 20-40 मिली मात्रा में नियमित सेवन करने से उदरगत अर्बुद में लाभ होता है.
2. वमन एवं हल्लास- 1-2 ग्राम अगुरू काष्ठचूर्ण का सेवन करने से वमन तथा हल्लास में लाभ होता है.
3.मन्दाग्नि- 1-3 ग्राम अगुरु काष्ठ चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से मन्दाग्नि में लाभ होता है.

गुदा रोग

1. रक्तार्श- 1-3 ग्राम अगुरु चूर्ण में तीन गुना मिश्री तथा प्रचुर घी मिलाकर पकाने के पश्चात शीतल करके सेवन करने से रक्तार्श का शीघ्र शमन होता है.

वृक्कवस्ति रोग:

1. पाठा पंचांग, अगुरु काष्ठ तथा हल्दी को समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर 10-20 मिली मात्रा में सेवन करने से लवणमेह में लाभ होता है.

प्रजनन संस्थान रोग:

1. सूतिका रोग: प्रसव के पूर्व एवं पश्चात अगुरु काष्ठ का क्वाथ बनाकर 20-30 मिली की मात्रा में प्रयोग करने से सूतिका रोगों में लाभ होता है. इसमें अज़वायन न सोंठ मिलाने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है.

अस्थिसंधि रोग:

1. वात रोग- अगुरु को पीसकर लेप करने से वातरक्त, आमवात, संधिशोथ तथा अंगघात में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग:

1. वात रोग- अगुरु को पीसकर लेप करने से वातरक्त, आमवात, संधिशोथ तथा अंगघात में लाभ होता है.

त्वचा रोग:

1. अगुरु काण्ड को पीसकर या घिसकर लेप करने से त्वक विकारों में लाभ होता है.
2. अगुरु काण्ड को पीसकर या घिसकर लेप करने से त्वक विकारों में लाभ होता है.

सर्वशरीर रोग:

1. शोथ- चोरक तथा अगुरु को पीसकर लेप करने से कफज शोथ में लाभ होता है.
2. ज्वर- अगुरु काष्ठ से भावित जल के सेवन करने से ज्वरजन्य पिपासा (प्यास/तृष्णा) में लाभ होता है.

रसायन वाजीकरण:

1. रसायन- 2-5 ग्राम अगुरु कल्क को एक लोहे के पात्र के भीतर लेप कर, रात भर छोड़ दें, प्रात: काल 375 मिली जल में अगरू लेप को घोल कर पीना चाहिए. ऐसे ही प्रतिदिन एक वर्ष तक नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था जन्य व्याधियों से मुक्ति मिलती है तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है.
2. 2-5 ग्राम अगुरु को दूध के साथ मिलाकर 15 दिन से एक वर्ष तक सेवन करने से बल, आयुष्य आदि रसायन गुणों की प्राप्ति होती है.
3. 1-2 बूंद अगुरु तैल का नियमित सेवन करने से बल की वृद्धि होती है.
4. पान के पत्ते में 1-2 बूंद पुराने अगुरु तैल को डालकर मुख में धारण करने से कामोत्तेजना तथा वाजीकरण में वृद्धि होती है.

विष चिकित्सा:

1. जांगमविष-अगुरु काष्ठ को पीसकर लेप करने से सर्प एवं वृश्चिक दंशजन्य वेदना आदि विषाक्त प्रभावों का शमन होती है.

प्रयोज्यांग : कवक संक्रमिक अंत: काष्ठ तथा तैल.

मात्रा : तैल 1-5 बूंद, चूर्ण, 0.5-3 ग्राम. क्वाथ 10-40 मिली. चिकित्सक के परामर्शानुसार.

विशेष : अधिक मात्रा में त्वक चूर्ण या क्वाथ का सेवन वमन (छर्दि, कै) तथा अतिसारकारक होता है.

आचार्य बालकृष्ण

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

मध्याह्न भोजन योजना की जानकारी ऐसे करें हासिल

देश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी स्कूलों में उपस्थिति के लिए सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की. सरकार की इस योजना से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन सरकारी पैसों की लूट जमकर मची. भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों का मकसद हमेशा से ही इस योजना से सिर्फ पैसा बनाना था, यही कारण है कि देशभर में सैकड़ों बच्चों के विषाक्त भोजन खा लेने से असामयिक मौत की खबरें आती रहीं. अगर आप मध्याह्न भोजन में हो रहे भ्रष्टाचार का पता लगाना चाहते हैं, अगर आप इस योजना से संबंधित सरकार की किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इस योजना से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं और समय रहते खुद की या दूसरों की काफी हद तक मदद कर सकते हैं. इस अंक में हम इस योजना से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

आवेदन का प्रारूप
(मध्याह्न भोजन योजना का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

.... के प्राथमिक विद्यालय के मध्याहन भोजन योजना के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का विवरण निम्नलिखित ब्यौरे के साथ दें:
(क) दिनांक...........से.............के दौरान उपरोक्त स्कूल को उपलब्ध कराई गई खाद्य-सामग्री का विवरण (मासिक ब्यौरे के साथ) उपलब्ध कराएं.
(ख) विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खाद्य-सामग्री कितने विद्यार्थियों को वितरित की जानी थी?
(ग) यह खाद्य-सामग्री किस राशन दुकानदार/एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध करायी गई?
(घ) उपरोक्त दुकान/एजेंसी का चुनाव किस प्रकार किया गया? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये सभी नियमों/आदेशों/दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.
(ड.) इस दौरान विभाग द्वारा विद्यालय को खाद्य-सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं.
2. मध्याह्न भोजन योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता बनाये रखने से संबंधित सरकार व विभाग द्वारा जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों कि प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
3. मध्याह्न भोजन योजना में कालाबाजारी/भ्रष्टाचार आदि के रोकथाम के लिए विभाग द्वारा की गई व्यवस्था से संबंधित सभी दिशानिर्देशों/नियमों/कानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
4. दिनांक..........से.............के दौरान उपरोक्त विद्यालय से क्या विभाग को मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराएं.
5. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत खाद्य-सामग्री यदि किसी कारणवश किसी विद्यालय द्वारा उपयोग नहीं की जाती है तो उस खाद्य-सामग्री के निष्पादन की विभाग ने क्या व्यवस्था की है? इससे सम्बंधित नीतियों/दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
6. मध्याह्न भोजन योजना से सम्बंधित विभिन्न नियमों, निर्देशों, आदेशों एंव सर्कुलर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपया अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय

नाम :
पता :
फोन नं :

संलग्नक : (यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है. शीत युद्ध खत्म होने के बाद 1992 से इसकी मांग तेज भी हो गई थी. उसी समय से भारत विश्वभर से स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन जुटाता रहा, जिसमें इसे 23 साल बाद सफलता मिली है. भारत के लिए यह खास उपलब्धि इसलिए है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहला मौका है, जब विभिन्न सदस्य राष्ट्रों ने इसके लिए अपने लिखित सुझाव दिए हैं. हालांकि स्थाई सदस्य देश चाहते हैं कि भारत को स्थाई सदस्यता मिलने पर भी वीटो पावर नहीं मिले, जबकि भारत वीटो पावर भी चाहता है.

भारत को बड़ी कामयाबी

सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता की पहल

जो ताकतें दुनिया को अधिक उदार व लोकतांत्रिक बनाने की वकालत करती रहीं, वे ही सुरक्षा परिषद के जरिए खुद को दुनिया का पुलिसमैन बनाए रहीं. इन सब के बावजूद भारत के लिए शांति की उपयोगिता पर सवाल खड़ा किया जाता है. शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थाई सीट आज तक भारत को नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तारों को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी मिल गई है. वो दिन दूर नहीं, जब सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा और भारत भी इस परिषद के स्थाई सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा. सुरक्षा परिषद में विस्तार पर चर्चा के बहाने ही सही, लेकिन इस ओर पहल शुरू हो भी गई है.

राजीव रंजन

आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश (एवं 2 आब्जर्वर सदस्य) हैं, जबकि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या आज भी वही है, जो 1963 में थी, यानी 15 सदस्य. इसका मतलब यह हुआ कि अब सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों का मात्र 7.77 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, जबकि स्थायी सदस्य मात्र पांच हैं अर्थात वीटो धारक मात्र 2.59 प्रतिशत. इस पक्षपात का परिणाम यह हुआ कि दुनिया संघर्ष व बिखराव की तरफ खिसकती चली गई. इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत जैसे देश को स्थायी सदस्य बनाना आज की जरूरत है. पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आम सहमति से सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार पर चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कूटनीतिज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र का यह कदम भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है. देखा जाए तो आज के दौर में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र प्रभावी नजर नहीं आ रहा है. कुछ देशों ने इसे पंगु बनाकर रख दिया है, जिसके कारण इसकी पहचान नखदंतविहीन संगठन के रूप में बन गई है. ऐसे में भारत जैसे देशों को इसमें जगह देने से संयुक्त राष्ट्र के उन उद्देश्यों को साकार करना आसान हो जाएगा, जिसकी कल्पना इसकी स्थापना के समय की गई थी.

सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद 1992 से तेज हो गई थी. उसी समय से भारत विश्वभर से स्थाई सदस्यता के लिए सर्मथन जुटाता रहा, जिसमें इसे 23 साल बाद सफलता मिली है. भारत के लिए यह खास उपलब्धि इसलिए है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहला मौका है, जब विभिन्न सदस्य राष्ट्रों ने इसके लिए अपने लिखित सुझाव दिए हैं. हालांकि स्थाई सदस्य देश चाहते हैं कि भारत को स्थाई सदस्यता मिलने पर भी वीटो पावर नहीं मिले, जबकि भारत वीटो पावर भी चाहता है, इसीलिए विस्तार पर चर्चा लंबे से टलती रही. स्थाई सदस्यता पाने की दौड़ में जर्मनी, जापान और ब्राजील भी शामिल हैं. हालांकि भारत के पक्ष में एशिया, यूरोप, अफ्रीका व खाड़ी के अधिकतर देश हैं. इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है. इसकी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं करने की नीति है. 1971 के युद्ध के दौरान भारत के कब्जे में 90 हजार पाकिस्तानी सैनिक थे. अगर भारत उदार देश नहीं होता तो निर्णय कुछ और होता, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की धरती को रक्तरंजित नहीं करना चाहा और पाकिस्तानी फौजियों को वापस कर दिया. द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय जवानों ने अपने लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि उसका मकसद दुनिया की शांति से जुड़ा था. ऐसे में भारत से अच्छा उदारवाद और लोकतांत्रिक कोई और देश कैसे हो सकता है. भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश भी है.

हालांकि भारत को कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है, तो मुश्किलें भी कम नहीं हैं. भारतीय राजनेता, शिक्षाविद् और मीडिया मानते हैं कि स्थायी सदस्यता पाने में चीन सबसे बड़ी बाधा है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर बीजिंग ने कभी भी खुलकर नई दिल्ली की संयुक्त राष्ट्र में उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया है. चीन ने हाल ही में सुधार वाले मसले पर अड़ंगा डालने की कोशिश की भी थी, लेकिन इस मसले पर उसे दूसरे मुल्कों का साथ नहीं मिला. इसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. भारत की सबसे बड़ी गलती जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर गठबंधन बनाना है. इन तीनों देशों के इस क्षेत्र में विराधी मौजूद हैं. चीन और दक्षिण कोरिया जापान की उम्मीदवारी का निश्चित तौर पर कड़ा विरोध करेंगे. रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है. रूस ने यह आश्वासन ऐसे समय में दिया है, जब पिछले दिनों रूस, अमेरिका और चीन ने यूएनएससी सुधारों पर बातचीत के अंतिम मसौदे में योगदान से इनकार कर दिया था, जिसे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिशों को नाकाम करने का प्रयास माना जा रहा. अमेरिका का कहना है कि परिषद के सुधार की प्रक्रिया के मुद्दे पर उसके भारत के साथ मतभेद हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की बात पर वो पूरी तरह कायम है. ओबामा इस मसले पर भारत को समर्थन देने की बात कई बार कह भी चुके हैं.

हालांकि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया पूरी होने में एक साल का समय लगेगा. 193 सदस्य देश सुधार के विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव देंगे. मसौदा तैयार हो जाने के बाद महासभा में उसे वोटिंग के लिए रखा जाएगा. वहां पास होने के लिए दो-तिहाई वोट की जरूरत होगी. ऐसे में भारत को 129 से अधिक देशों का समर्थन हासिल करना होगा. सरकार को अभी से इस मुहिम में जुट जाना चाहिए. कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता हासिल करने की भारत की उम्मीदें बरकरार हैं. भारत का कहना है कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की प्रक्रिया अनंतकाल तक लंबित नहीं रह सकती और ठोस परिणाम के लिए ये ज़रूरी है कि इसे परिणाम पर आधारित समय सीमा में पूरा किया जाए. संयुक्त राष्ट्र महासभा कि कार्यसूची में ये मामला 23 साल से लंबित है और इसे और लटकाए रखने के लिए लगातार बढ़ रहे दवाब और चुनौतियों के संदर्भ में ये कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. अगर संयुक्त राष्ट्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, उसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तो आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता भी खतरे में पड़ सकती है. हालांकि यह बात भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 1963 में सुरक्षा परिषद में जब सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, तब अस्थायी सदस्य 11 थे, जिसे बढ़ा कर 15 किया गया था. यह निर्णय भी महासभा ने स्थायी सदस्यों की मर्जी के खिलाफ लिया था. बहरहाल, भारत के राजनय की यह उपलब्धि सराहनीय है. यद्यपि सुरक्षा परिषद की स्थाई सीट तक पहुंचने की राह काफी लंबी है, लेकिन उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सुधार की ओर उठे ये कदम अब पीछे नहीं हटेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

जब सीरियल किलर बना पत्रकार

जैक अन्टरवैगर ऑस्ट्रिया का सीरियल किलर था, जिसने गुनाह की दुनिया से पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा, लेकिन जब उसे पत्रकारिता की दुनिया रास नहीं आई, तो वह वापस अपनी उसी गुनाह की दुनिया में जा पहुंचा. जैक ने अपनी खतरनाक मानसिकता के चलते वैश्यावृत्ति में लिप्त कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था. जैक अन्टरवैगर का जन्म 16 अगस्त, 1950 को ऑस्ट्रिया में हुआ. जैक का बचपन ऑस्ट्रिया के स्टायरिया शहर में गुज़रा, लेकिन आम बच्चों से बिल्कुल अलग प्यार की जगह उसे दुर्व्यवहार मिला और मां की ममता की जगह उसे दूरियां मिलीं. कहते हैं कि जब जैक छोटा बच्चा था, तभी उसकी वैश्या मां उसे छोड़ कर चली गई थी. मां के छोड़ कर चले जाने से जैक सात साल तक अपने नाना के साथ रहने लगा, लेकिन नाना के शराबी होने की वजह से उसकी ज़िन्दगी पर गलत असर पड़ा. किशोावस्था में पहुंचते ही जैक छोटे-मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा. 16 साल की उम्र में जैक को एक वैश्या पर हमला करने के आरोप में पहली बार जेल हुई. आगे चलकर1976 में अपनी गलत संगति और खराब मानसिकता के चलते उसने 18 साल की माग्रेट शेफ़र, वैश्या को बड़ी बेहरहमी से गला घोंट कर उसे मौत की नींद सुला दिया. जैक के इस अपराध के लिये उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई. जेल में सजा काटते वक्त जैक को बुद्धिजीवियों का साथ मिला और इन्हीं बुद्धिजीवियों की संगती में रहते-रहते जैक पढ़ने-लिखने लगा. पढ़ने और लिखने के प्रति रुचि बढ़ने से जैक ने जेल में ही अपनी पहली किताब लिखी. यह किताब कारावास में रहे जैक की आत्मकथा पर आधारित थी. आगे चलकर इस किताब से जैक लोकप्रिय उपन्यासकार बना. जैक की बढ़ती लोकप्रियता ने प्रशासन को यह यक़ीन दिलाया कि वह सुधर गया है. 1990 में

प्रशासन ने जैक को पैरोल पर रिहा कर दिया. जैक के सामने एक नई दुनिया पलकें बिछाये उसका इंतज़ार कर रही थी. जैक की लिखी किताब पर फिल्में बनने लगीं. बातचित जैसे कार्यक्रमों में जैक को अतिथि के तौर पर बुलाया जाने लगा, लेकिन कौन जानता था कि जैक अभी भी मन ही मन अपनी पुरानी मानसिकता में जी रहा था. ऑस्ट्रिया में एक बार फिर से वैश्याओं की हत्याओं के मामले सामने आने लगे, लेकिन जब तक ऑस्ट्रिया की पुलिस जैक के खिलाफ सबूत जुटाती, तब तक जैक अमेरिका जा चुका था. अमेरिका के लॉस एंजिलस शहर में तीन वैश्याओं की मौत सामने आई. जब इन मामलों की जांच हुई, तो यह पाया गया कि इन तीनों को पहले पिटा गया, फिर उनका यौन शोषण किया गया और अंत में बड़े दर्दनाक तरीके से गला घोंट कर मार दिया गया. इन मामलों में वही तरीका अपनाया गया, जिस तरीके से अन्टरवैगर जैक अपने अपराधों को अंजाम दिया करता था. इस वजह से अमेरिकी पुलिस को जैक पर संदेह हुआ और वे जैक पर निगरानी रखने लगे. आखिरकार 27 फरवरी, 1992 में अमेरिकी पुलिस एफबीआई ने जैक के खिलाफ सबूत जुटा कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान जैक अपने आप को बेकसूर बताता रहा. 1994 में अदालत ने जैक पर 11 नरहत्याओं के आरोपों को सही ठहराते हुये उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और उसी रात जैक ने अपने जूते के लेस और अपने पजामे के नाड़े की मदद से अपना गला घोंटकर आत्महत्या कर ली. आखिरकार सबको दर्दनाक मौत देने वाला सीरियल किलर अन्टरवैगर जैक ने आत्महत्या का रास्ता चुना. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

शारजाह में फंसे हैं 17 भारतीय नाविक

भारतीय नाविकों का एक 17 सदस्यीय दल पिछले आठ महीने से शारजाह में फंसा हुआ है. वे शारजाह के तटीय इलाकों में एक जहाज पर फंसे हुए हैं. इन 17 नाविकों के अलावा जहाज पर इसका कैप्टन भी है. यह कैप्टन म्यांमार का है. यह जहाज पनामा में पंजीकृत है, जो 18 जनवरी से संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री इलाके में लंगर डाले हुए है. जहाज पर खाना और पानी सीमित मात्रा में है. इस पर काम करने वालों को कोई वेतन नहीं मिला है, हालात बेहद खराब हैं. दुबई सामुद्रिक नगर प्राधिकरण को दी गई शिकायत के आधार पर यह जानकारी दी गई है. जहाज के कप्तान का नाम टिम को है. उन्होंने जल्द से जल्द मदद भेजने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि जहाज के नाविकों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है. जहाज दुबई स्थित एक भारतीय ब्रजेंद्र कुमार चक्रवर्ती की कंपनी विहान ट्रेडिंग का है. नाविकों ने शिकायत में कहा है कि ब्रजेंद्र ने उनकी दशा सुधारने के लिए अभी तक सिर्फ झूठे वादे किए हैं. जहाज के अधिकारी हेमाद्री उपाध्याय ने कहा कि हम जब भी फोन कॉल करते हैं, वे यही कहते रहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. हर चीज की एक हद होती है. यह जहाज के मालिक की गलती है. रपट में नाविकों की दुर्दशा और कंपनी की लापरवाही के अलावा जहाज के शारजाह के पास आठ महीने से खड़े रहने की वजह के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. ■

मक्का में 14 भारतीयों सहित 717 की मौत

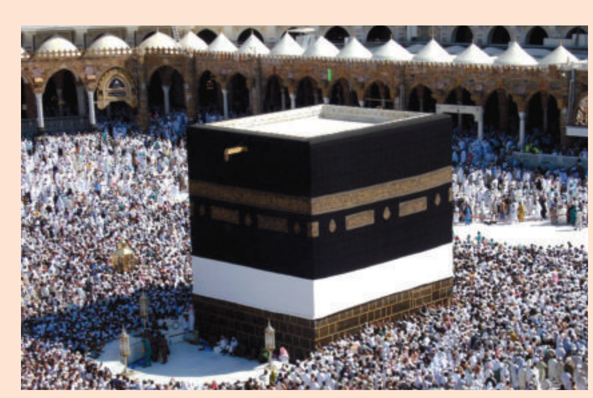

सऊदी अरब के मक्का में हज के दौरान पिछले दिनों भगदड़ मचने से 717 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 863 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. मरनेवालों में 14 भारतीय हैं. घायल भारतीयों की संख्या 13 है. भगदड़ शैतान को पत्थर मारने के दौरान मची. बता दें कि सऊदी में जिस समय भगदड़ मची, उस समय बकरीद (ईद उल अधा) मनाई जा रही थी. हज की यात्रा का उस दिन आखिरी दिन था. उस दिन ही मक्का में ईद का दिन था. हाजी उसी दिन मीना, मुज़दलफा और मैदान-ए-अराफात से वापसी के बाद जमेरात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा करते हैं. एक हाजी फरीद शमसी का कहना है कि प्रशासन की तरफ से काफी अच्छे इंतेजाम थे, जिस रास्ते से पत्थर मारने के लिए जाने का इंतजाम है, उससे लौटने की मनाही होती है, लेकिन कुछ लोग उसी रास्ते से वापस आ गए, जिससे ये हादसा हुआ है. हालांकि, सऊदी सरकार की ओर से ये नहीं बताया गया है कि हादसा कैसे हुआ. शैतान को पत्थर मारने के दौरान हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले 2006 में इस तरह के हुए हादसे में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इस साल हज के लिए 1.30 लाख भारतीय हज पर गए हैं. इससे पहले 11 सितंबर को जुमे की शाम हुए एक हादसे में 107 लोग मारे गए थे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

साईं की महिमा

दास-भाव को हम सर्वश्रेष्ठ भाव इस कारण कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मात्र सेवा करने का भाव है, अहंकार या कुछ पाने की कामना नहीं होती. दास अपने मालिक के प्रति पूर्णत: समर्पित रहता है. वह मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहता है. उसमें कहीं कोई कर्ता-भाव या अपनी कोई हठधर्मिता नहीं होती. यह दूसरी बात है कि मालिक अपनी खुशी से उसे कुछ देना चाहे, तो दे और न देना चाहे तो न दे.

साईं वंदना

भक्ति भाव ही सबसे अच्छा

बाबा के प्रति शुद्ध प्रेम-भाव धीरे-धीरे आता है. इसके लिए बाबा के प्रति दृढ़निष्ठा के साथ धैर्य आवश्यक है. प्रेम की मात्रा बौद्धिक जानकारी से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता. वह जैव पदार्थों की भांति धीरे-धीरे विकसित होता है. इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है. पढ़ो, चिंतन एवं मनन करो तथा बाबा के सत्कर्मों एवं वचनों का गुणकथन करो.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

दास भाव

बाबा के भक्तों के लिए किस भाव का सर्वोपरि महत्व है?

भक्ति भाव ही सबसे अच्छा है. भक्ति नवधा है – जैसे श्रवण, पूजन, पाद-सेवन आदि. किसी व्यक्ति का यदि एक भी भाव पूर्णत: शुद्ध है और उसमें किसी प्रकार का संदेह अथवा नकारात्मकता नहीं है, तो उस एक भाव के माध्यम से वह आगे बढ़ता जाएगा. नवधा भक्ति में से यदि एक भी भाव को शुद्धता से धारण किया जाएगा, तो वह एक भाव उसे अन्य भाव-संबंधों से जोड़ देगा. तब यह प्रतीत होगी कि सभी भाव एक ही भाव में समाहित हैं, जिसको संत लोग महाभाव कहते हैं. फिर भी दास-भाव को हम सर्वश्रेष्ठ भाव इस कारण कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मात्र सेवा करने का भाव है, अहंकार या कुछ पाने की कामना नहीं होती. दास अपने मालिक के प्रति पूर्णत: समर्पित रहता है. वह मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहता है. उसमें कहीं कोई कर्ता-भाव या अपनी कोई हठधर्मिता नहीं होती. यह दूसरी बात है कि मालिक अपनी खुशी से उसे कुछ देना चाहे तो दे और न देना चाहे तो न दे. उसके जीवन का ध्येय मालिक की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है.

विशुद्ध प्रेम

हम बाबा के प्रति शुद्ध प्रेम-भाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

बाबा के प्रति शुद्ध प्रेम-भाव धीरे-धीरे आता है. इसके लिए बाबा के प्रति दृढ़निष्ठा के साथ धैर्य आवश्यक है. प्रेम की मात्रा बौद्धिक जानकारी से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता. वह जैव पदार्थों की भांति धीरे-धीरे विकसित होता है. इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है. पढ़ो, चिंतन एवं मनन करो तथा बाबा के सत्कर्मों एवं वचनों का गुणकथन करो. इस रूप में यदि बाबा हमारी चेतना के अंग बन जाते हैं, तो उनके प्रति विशुद्ध प्रेम-भाव स्वत: विकसित हो जाएगा.

जैसा भाव वैसा अनुभव

बाबा के सभी भक्त समान रूप से उनकी उपस्थिति का अनुभव कर पाने में सफल नहीं होते. इसका क्या कारण है?

आप अपने जीवन में जिस अनुपात में बाबा को स्थान देंगे, उसी अनुपात में वे आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालेंगे. जीवन में आवश्कता इस बात की है कि बाबा को भाव-रूप से हृदय के केन्द्र में धारण किया जाए. भक्त का जैसा भाव होगा, वैसा ही अनुभव वह प्राप्त करेगा-

जया मनी जैसा भाव.
तया तैसा अनुभव.

मैं तो यही प्राथना करता हूं-

शरत्सुधांशुप्रतिमप्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ.
त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु.
उपासनादैवतसाईनाथ, स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्त्वम्.
रमेन्मनो में तव पादयुग्मे, भृगों यथाब्जे मकरंदलुब्ध:

-हे साईनाथ, आपकी कृपा की छाया तो शरत् ऋतु के चन्द्रमा के अप्रतिम प्रकाश की भांति है. अपने चरणों में आए हुए लोगों के त्रिविध ताप को अपनी शीतल छाया से दूर करें.

हे साईनाथ! आप मेरे देव हैं, जिनकी मैं उपासना करता हूं. मेरा मन आपके चरण-कमलों में उसी प्रकार रमे जिस प्रकार भौंरा मधु के लोभ में कमल पर मंडराता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

ऐसा मंदिर, जहां प्रसाद में चूहों का जूठा मिलता है

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान भारत का बेहद खूबसूरत राज्य है. राजस्थान में दैवीय शक्ति करणी माता का मंदिर है, जो देखने में अतिसुंदर है. करणी माता का मंदिर कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है. करणी माता को मां जगदम्बा का साक्षात अवतार माना जाता है. यह मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलो मीटर दूर देशनोक में स्थित है. करणी माता का मंदिर चूहों वाली माता और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इस मंदिर में करणी माता के साथ चूहों के भी दर्शन होते हैं. मंदिर में 20000 चूहे हैं और यहां आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद मिलता है. आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बावजूद भी मंदिर में बिल्कुल बदबू नहीं आती है. आज तक चूहों का झूठा खाने से कोई भी बीमारी नहीं फैली और न ही कोई बीमार हुआ. मंदिर में ज्यादातर काले चूहे ही नज़र आते हैं. मान्यता है कि अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी. इन चूहों को यहां काबा कहा जाता है और इन काबाओं को बाकायदा दूध, लड्डू आदि भक्तों के द्वारा परोसा जाता है. असंख्य चूहों से भरे इस मंदिर से बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आता और न ही मंदिर के भीतर कभी बिल्ली प्रवेश करती है. कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने राजस्थान में चारण जाति के एक परिवार में कन्या के रूप में जन्म लिया और फिर अपनी शक्तियों से सभी के दुखों को दूर करती देतीं. करणी माता जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजाओं की आराध्य हैं. पहले इनका नाम रिघुबाई था पर जनकल्याण के कार्यों के कारण करणी माता के नाम से इन्हें पूजा जाने लगा. यह नाम इन्हें मात्र 6 साल की उम्र में ही उनके चमत्कारों व जनहित में किए गए कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने दिया था. साल में दो बार यानी नवरात्रि में यहां विशेष मेला लगता है और पूरे देश से माता के भक्त आते हैं. चुहों के बार में प्रचलित कथा के अनुसार करणी माता के सौतेले पुत्र की कुएं में गिरने से मौत हो गई, तब उन्होंने यमराज से बेटे को जीवित करने की मांग की. यमराज ने करणी माता के आग्रह पर उनके पुत्र को जीवित तो कर दिया पर

चूहे के रूप में. तब से ही यह माना जाता है चूहे करणी माता के पुत्र हैं. करणी माता का मंदिर बीकानेर के राजा गंगासिंह ने बनवाया था. संगमरमर पर की गई नक्काशी और आकर्षित करती आकृतियों के अलावा चांदी के दरवाजे मंदिर की शोभा और भी बढ़ा देते हैं. करणी माता का मंदिर आज पूरे देश में आस्था और रहस्य का केंद्र माना जाता है. ■

प्रेरक कहानी

जैसी भावना वैसी मनोकामना

एक बार भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे. उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा कि जागो! समय हाथ से निकला जा रहा है. इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई. सभा के बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ घूमने के लिए. अभी विहार के मुख्य द्वार तक पहुंचे ही थे कि एक किनारे रुक कर खड़े हो गए.

प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था, लेकिन उसमें से निकल कर एक स्त्री ने कहा कि बुद्ध मैं नर्तकी हूं. आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी. आपने कहा जागो समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई. उसके बाद एक डाकू आया उसने कहा तथागत मै भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई.

इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया वृद्ध ने कहा तथागत! जिन्दगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा. अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है, तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई. आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं. आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा. जब सब लोग चले गए, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद! प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला. कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी जितनी झोली होती है, उतना ही दान वह समेट पाता है. निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है. इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है. इस प्रेरक प्रसंग में भी ऐसा ही है. ■

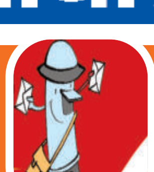

पाठकों की

गीता प्रेस की मदद करे सरकार

गीता प्रेस गोरखपुर देश की एक बड़ी प्रकाशन संस्था है, जिसने कई दशकों तक लागत मूल्य से भी कम कीमत पर धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर, उन्हें भारत के घर-घर में पहुंचाने का महान कार्य किया है. धार्मिक पुस्तकों में घटती जनरुचि के परिणाम स्वरूप आज प्रेस पर दुर्दिन के बादल मडरा रहे हैं. प्रेस अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति में नहीं है. ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह प्रेस को आर्थिक सहायता दे. प्रेस को सस्ते दर पर कागज उपलब्ध कराए.

-राजकिशोर पाण्डेय,
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सावधानी ही बचाव है

दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों में डेंगू तेजी से फैल रहा है. डेंगू से अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की जाने जा चुकी हैं और इसकी चपेट में हजारों लोग आ चुके हैं. बरसात से स्थिति और भी भयावह हो सकती है. दिल्ली और केन्द्र सरकार ने डेंगू को लेकर कई फैसले लिए, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया. अस्पतालों में बेड बढ़ाने के बाद भी जगह नहीं है. डेंगू से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार लड़ रही हैं. विपक्ष भी हमेशा की तरह सरकार पर आरोप लगा रहा है. सरकारें जब डेंगू या किसी बीमारी से लोग मरने लगते हैं, तब जागती हैं. इसलिए खुद लोगों को जागरूक होना चाहिए और आगे आना चाहिए. अपने आस-पास फैली गंदगी को सभी लोग मिलकर साफ करें. छत पर खुली टंकी न छोड़ें. कूलर के पानी को हर तीसरे दिन साफ करें. कहीं आस-पास बरसात का पानी इकट्ठा न होनें दें और पूरे शरीर को ढंककर रखें. सावधानी ही बचाव है इसलिए खुद बचाव करें.

-मनोज कुमार सिंह,
द्वारका, दिल्ली.

नेपाल में नया संविधान

कवर स्टोरी-माओवादियों-आईएसआई के निशाने पर राजघराने की अकूत दौलत, नेपाल के पूर्व नरेश की जान ख़तरे में(21 सितंबर-27 सितंबर 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. प्रभात रंजन दीन ने बिल्कुल सही कहा है कि पहाड़ बनाम तराई का संघर्ष अराजकता फैलाकर हित साधने वाले तत्वों की भड़काऊ साजिश का परिणाम है. इसमें माओवादी भी खुश हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी यही चाहती है. माओवादी और आईएसआई दोनों वहां की अशांति के लिए जिम्मेदार हैं. हिंसा और खून खराबे के बीच नेपाल में नया संविधान लागू हो गया. हिंसा और खून खराबे को देखते हुए 14 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. मधेशियों के मांग को नए संविधान में शामिल नहीं किया गया है. मधेशियों की मांग को शामिल न करने पर हो रही हिंसा को लेकर भारत भी चिंतित है. संघर्ष को देखते हुए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है.

-ब्रज बिहारी,
समस्तीपुर, बिहार.

पत्रकारों की भूमिका

जब तोप मुकाबिल हो-पत्रकार मिटा सकते हैं भारत-पाकिस्तान की तल्खी(21 सितंबर-27 सितंबर 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय से मैं सहमत हूं कि पत्रकार भारत और पाकिस्तान की तल्खी मिटा सकते हैं. भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों को सरकार के प्रवक्ताओं की तरह बोलना बंद कर देना चाहिए. सच्चाई यह है कि दोनों जगह के राजनीतिक दल नहीं चाहते कि रिश्ते सुधरें, क्योंकि राजनीतिक दलों को इससे वोटों का फायदा होता है. यह बिल्कुल सही है कि दोनों देशों के लोग चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो और लोग एक दूसरे के यहां घूमने के लिए आए-जाएं. भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पत्रकारों को चाहिए कि वे अपनी-अपनी सरकारों को सुझाव दें. अगर दोनों देशों के पत्रकार चाहें, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते से सुधर सकते हैं. पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों देशों के लोगों को समझाना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, सिवाय नुकसान के. इसलिए अब पत्रकारों को आगे आना चाहिए और दोनों देशों के कड़वाहट को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए.

-सिद्धार्थ सक्सेना,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

कांटे की टक्कर

आलेख-बिहार विधानसभा चुनाव, सर्वे का बाजार गर्म है (21 सितंबर-27 सितंबर 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. यह बिल्कुल सही है कि चुनाव आते ही सर्वे का बाजार गर्म हो जाता है और सभी टीवी चैनल अपने-अपने सर्वे पेश करने लगते हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र ने सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे प्रकाशित किया था. सभी समाचर चैनलों ने उसी सर्वे को पुख्ता किया है. चौथी दुनिया समाचार पत्र के सर्वे पर सवाल खड़ा करना गलत है. केवल इंडिया टुडे-सिसरों और जी न्यूज के सर्वे को छोड़ दें, तो सभी सर्वे में महागठबंधन(जदयू, राजद, कांग्रेस) को बढ़त दिखाया गया है और नीतीश कुमार को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है. इन दोनों सर्वे में भी नीतीश कुमार को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है. इसलिए चौथी दुनिया के सर्वे पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है. समाचार चैनलों और अखबारों के सर्वे चाहे जो कहें, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है.

-चक्रधारी यादव, *पटना, बिहार.*

आचार्य द्विवेदी पर अद्भुत ग्रंथ

अनंत विजय

हिंदी की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अब लगभग अप्राप्य हैं, जिसकी वजह से नए ज़माने के पाठकों का उनसे और उसके लेखक से परिचय नहीं है. ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके पुन:प्रकाशन से हिंदी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती या फिर हिंदी के पाठकों को समृद्ध करने में मदद मिलती. एक जमाने में काशी नागरी प्रचारिणी, नागिरी प्रचारणी सभा, खडगविलास प्रेस, नवल किशोर प्रेस आदि से इतनी महच्वपूर्ण किताबें छपी थीं जो कि इस वक्त लगभग अप्राप्य हैं. पिछले दिनों पंडित किशोरीदास वाजपेयी की किताब हिंदी शब्दानुसान पढ़ने की जरूरत महसूस हुई. इस किताब को खोजने का प्रयास शुरू हुआ, दिल्ली से लेकर वाराणसी तक के अपने संपर्कों को खटखटाया लेकिन किताब उपलब्ध नहीं हो सकी. बाद में मित्र अरुण माहेश्वरी ने वो पुस्तक उपलब्ध करवाई. हिंदी लिखनेवालों के लिए पंडित किशोरी दास वाजपेयी की यह किताब उतनी ही आवश्यक है जितनी जिंदगी को चलाने के लिए खाना या पानी. हो सकता है मेरी यह तुलना कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लगे लेकिन जिस तरह से किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी और अन्य भाषाओं को जोड़कर शब्दों के उपयोग को सिखाया है, वह अद्भुत है. अफसोस कि यह किताब लगभग अनुपलब्ध है. अब संभवत: वाणी प्रकाशन से इसको छापने की योजना बन रही है. ऐसी ही कई किताबें हैं जिनका फिर से प्रकाशन किया जाना चाहिए. दूसरी बड़ी समस्या है कि जिन किताबों का फिर से प्रकाशन हुआ उसमें धीरे-धीरे खुद ही बदलाव होते चले गए. जैसे प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गो-दान से गोदान हो गया. जब दस जून 1936 में प्रेमचंद का उपन्यास गो-दान छपा था तब गो और दान के बीच हाइफन था. उसके आवरण पृष्ठ पर यह शीर्षक अंकित है. साथ ही नीचे सरस्वती प्रेस, बनारस और हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई छपा हुआ है. अभी प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान कमल किशोर गोयनका के संपादन में प्रकाशित हुई गो-दान में कई दिलचस्प बातें हैं. जैसे कमल किशोर गोयनका ने जनार्दन प्रसाद झा द्विज को उद्धृत करते हुए लिखा है - जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद की उपन्यास कला में लिखा है कि प्रेमचंद ने इसका नाम गौ-दान रखा था, परंतु मेरे कहने से गौ के स्थान पर गो अर्थात गो-दान कर दिया. अब ये सब हिंदी के पाठकों के लिए दिलचस्प प्रसंग हैं. हालांकि इस प्रसंग में तो विस्तृत शोध की आवश्यकता है कि क्यों और कैसे गो-दान से गोदान हो गया? अपनी इस किताब में कमल किशोर गोयनका ने इस बात के पर्याप्त संकेत किए हैं कि प्रेमचंद के इस उपन्यस के मूल पाठ में भी बदलाव हुआ है. यह विषय एक अलग लेख का है, जिसपर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

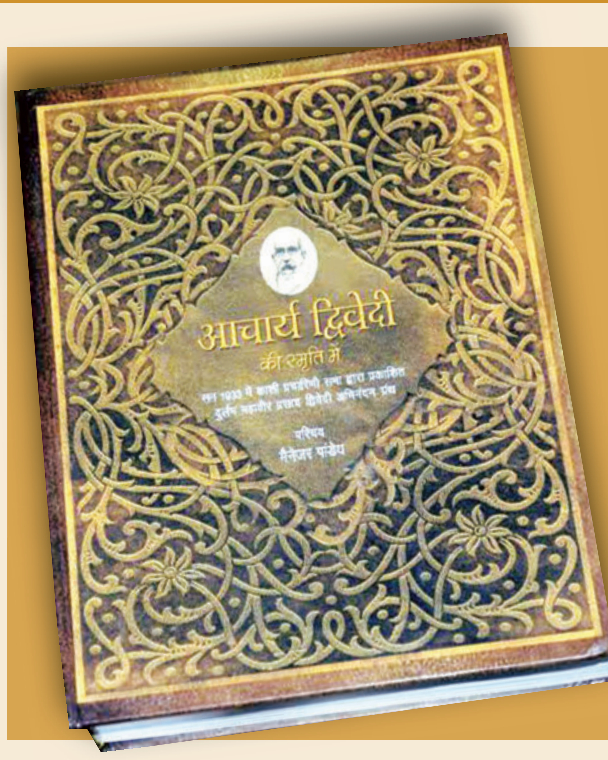

अभी हाल ही में हिंदी के एक और पुराने और दुर्लभ ग्रंथ का पुनर्मुद्रण हुआ है. यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ. यह किताब आज से करीब बयासी साल पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सत्तरवें वर्ष में प्रवेश के मौके पर 1937 में छपा था. दरअसल इस ग्रंथ के छपने के पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है. बात 1932 की है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक दिन के लिए काशी पधारे थ. उस वक्त काशीनागिरी प्रचारिणी सभा की ओर से उनको एक अभिनंदन पत्र दिया गया था.

अभी हाल ही में हिंदी के एक और पुराने और दुर्लभ ग्रंथ का पुनर्मुद्रण हुआ है. यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ. यह किताब आज से करीब बयासी साल पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सत्तरवें वर्ष में प्रवेश के मौके पर 1937 में छपा था. दरअसल इस ग्रंथ के छपने के पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है. बात 1932 की है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक दिन के लिए काशी पधारे थ. उस वक्त काशीनागिरी प्रचारिणी सभा की ओर से उनको एक अभिनंदन पत्र दिया गया था. बात आई गई हो गई थी. कई दिनों बाद शिवपूजन सहाय ने काशी नागिरी प्रचारिणी सभा के मंत्री से चर्चा की कि सभा को केवल मानपत्र देकर ही नहीं रह जाना चाहिए, आचार्य के अभिनंदन के लिए एक सुंदर ग्रंथ का भी प्रकाशन होना चाहिए. सभा ने आचार्य शिवपूजन सहाय के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी और किताब छपने का काम शुरू कर दिया गया. आर्थिक संकट से निबटने के अलावा देश दुनिया के विद्वानों की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में राय मंगवाने की भी बड़ी चुनौती थी. काम शुरू हुआ तो आगे चलता चला गया. आचार्य अभिनंदन ग्रंथ के प्रकाशन के लिए इसके कर्ताधर्ताओं ने बेहद बारीकी से योजना बनाई थी. उस वक्त के अखबारों में इस योजना की चर्चा शुरू की गई ताकि इस किताब के बारे में उत्सुकता का एक वातावरण तैयार हो सके. यह योजना काम कर गई थी और हिंदी पट्टी में आचार्य के ऊपर प्रस्तावित ग्रंथ की चर्चा शुरू हो गई थी. एक समय तो ऐसा आया था कि लगा कि अब इस किताब के प्रकाशन की योजना पर ग्रहण लग जाएगा. जब इस किताब को छापने के लिए सभा के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ तो उस वक्त देश के तमाम बड़े और धनवान लोगों के पास आर्थिक सहायता के लिए पत्र भेजा गया लेकिन बड़े-बड़े लोगों ने कोई मदद नहीं की. सबने योजना को अच्छा बताते हुए उसकी तारीफ की लेकिन आर्थिक मदद करने में असमर्थता ज़ाहिर कर दी थी. इसके बाद राजाओं के पास संदेश भेजा गया. अखबारों में चर्चा का एक लाभ यह हुआ कि राजाओं के पास इस योजना की जानकारी पहुंच चुकी थी. उस वक्त के कई राजाओं ने इस किताब को छापने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की. सीतामऊ के राजपरिवार ने न केवल सौ रुपये की आर्थिक मदद की बल्कि देश भर के राजघरानों से आर्थिक मदद दिलाने में सभा की सहायता की. उस ग्रंथ की भूमिका में भी इस बात का उल्लेख मिलता है-विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण हमें आर्थिक सहायता प्राप्त करने में बड़ी अड़चन पड़ी. हमारे उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हुए भी बड़े-बड़े श्रीमानों तक ने हमें कोरा उत्तर दे दिया. यदि सीतामऊ के राजकुल ने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो संभवत: हमें यह प्रस्ताव स्थगित कर देना पड़ता. हमारी प्रार्थना पहुंचते ही वहां के विद्या रसिक महाराज महोदय ने सौ रुपए का दान देकर हमें प्रोत्साहित किया. इसके अनंतर वहां के विद्वान राजकुमार ने, जिन्होंने हिंदी सेवा का व्रत धारण किया है और जो हिंदी के एक श्रेष्ठ उदीयमान लेखक हैं, अपने कई इष्ट-मित्र नरपतियों से हमें सहायता दिलवाई. अब इस तरह के वाकयों से हिंदी जगत लगभग अपरिचित है. इस तरह के ऐतिहासिक महत्व की किताबों को छापने का काम साहित्य अकादमी या नेशनल बुक ट्रस्ट को करना चाहिए.

अभी हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने आचार्य द्विवेदी के जन्मस्थान दौलतपुर में सक्रिय संस्था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के सौजन्य से हासिल इस दुर्लभ ग्रंथ को फिर से छापा है. दरअसल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 150वीं वर्षगांठ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति, रायबरेली ने इस दुर्लभ ग्रंथ को फिर से छपवाने का बीड़ा उठाया था. जिस तरह से पहली बार इस ग्रंथ को छापने में बाधा आई थी उसी तरह से कई कठिनाइयों का सामना इसके पुनर्प्रकाशन में भी करना पड़ा. साहित्यप्रेमी और पत्रकार अरविंद कुमार सिंह ने भी इसमें पहल की और नेशनल बुक ट्रस्ट इसको छापने के लिए तैयार हुआ. पुनर्प्रकाशित इस ग्रंथ के महत्व को रेखांकित करते हुए आलोचक मैनेजर पांडे ने विस्तार से एक लेख लिखा है. मैनेजर पांडे ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को युगद्रस्टा और युगस्रस्टा करार दिया है. मैनेजर पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि आचार्य जी की साहित्य की धारणा बहुत ही व्यापक थी. वे केवल कविता, कहानी, उपन्यास नाटक, और आलोचना को ही साहित्य नहीं मानते थे. उनके अनुसार किसी भी भाषा में मौजूद ज्ञानराशि साहित्य है. द्विवेदी जी की यही धारणा उनके लेखन में भी दिखाई देती है जब वो उस वक्त के लगभग हर विषय पर अपनी लेखनी चलाते नजर आते हैं. उनकी किताब संपत्तिशास्त्र इसका बेहतरीन नमूना है. कहा जाता है कि हिंदी में इस किताब की टक्कर की दूसरी किताब नहीं है. आचार्य अभिनंदन ग्रंथ को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके समकालीन उनके बारे में क्या सोचते थे. ये अभिनंदन ग्रंथ हाल के दिनों में छप रहे अभिनंदन ग्रंथ की तरह नहीं है बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसमें जिन लोगों की राय है उससे आचार्य की एक लेखक के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर छवि का निर्माण होता है. इस किताब में मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, मौलाना सैयद हुसैन शिबली, संत निहाल सिंह, जार्ज ग्रियर्सन से लेकर महादेवी वर्मा, प्रेमचंद के अलावा महात्मा गांधी की राय भी है. पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के पत्रों को संग्रहित संपादित किया था - पत्रों में समय संस्कृति. इसके बाद अब आचार्य अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी के लिए एक शुभ संकेत है. हालांकि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के गौरव द्विवेदी और पत्रकार अरविंद सिंह की पहल पर हुआ है, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट को इस दिशा में स्वतंत्र रूप से खोजबीन कर दुर्लभ ग्रंथों के प्रकाशन की पहल करनी होगी ताकि हिंदी के नए पाठकों का अपने गौरवशाली अतीत से परिचय हो सके. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

गंगा पर संकट की पड़ताल

कृष्णकांत

दुनिया भर में पर्यावरण संकट जितना गंभीर है, उससे निपटने के प्रयास उतने गंभीर नहीं हैं. यह स्थिति विकासशील देशों में और घातक है. भारत जैसे देश में, जहां पर सभ्यताएं नदियों के किनारे बसीं, विकसित हुईं, और आज भी बड़ी आबादी जल, जंगल, जमीन पर निर्भर है, वहां पर पर्यावरण की अनदेखी बेहद चिंता का विषय है. गंगा नदी लाखों-लाख लोगों के रोजगार का साधन होने के साथ-साथ भारतीय मानस में एक पवित्र स्थान रखती है. भारत में गंगा समेत कुछ नदियां, जो पौराणिक महत्व की हैं, उनमें लोगों की अटूट आस्था है. इन्हें इस तरह कहा जा सकता है कि गंगा यमुना जैसी नदियां सिर्फ जलस्रोत नहीं हैं, बल्कि वे संसाधन के रूप में लोगों का इहलोक तो सुधारती ही हैं, आस्था और विश्वास के रूप में परलोक भी सुधारती हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोविंद कुमार सक्सेना ने गंगा पर एक किताब लिखी है- 'कुंभ विजन 2025'. यह किताब इलाहाबाद के साहित्य भंडार प्रकाशन से छपी है, जिसमें करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र कुंभ मेले पर केंद्रित करते हुए गंगा की दुर्दशा और गंगा को निर्मल बनाने के असफल प्रयासों की पड़ताल की है. 2013 के कुंभ में इलाहाबाद में जुटे संतों और प्रशासन ने इलाहाबाद में गंगा को साफ करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए थे, लेकिन वह बेहद आंशिक साबित हुए. इस दौरान गंगा सफाई में खास भूमिका निभाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जिसने इलाहाबाद में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया. यह इलाहाबाद को पॉलीथीन मुक्त बनाकर गंगा को कचरामुक्त बनाने की एक पहल थी. लेकिन हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली गंगा को सिर्फ एक शहर में सफाई के प्रयासों से निर्मल नहीं किया जा सकता.

नवंबर 2008 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था. 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई. विश्व बैंक द्वारा हजारों करोड़ की धनराशि गंगा सफाई के नाम पर बहाई गई लेकिन फिलहाल यह कोशिश गंगा की धारा में बूंद बराबर साबित हुई है. गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है और जल की गुणवत्ता गिरती जा रही है. गंगा जिस भी शहर से गुजरती है, वहां की सारी गंदगी गंगा की धारा में बहाई जा रही है. गंगा के नाम पर नई सरकार ने मंत्रालय भी बनाया है और नमामि गंगे जैसी योजना चलाई है लेकिन इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गंगा की सफ़ाई के मामले में सरकार और उसके संस्थान को आड़े हाथ लिया था. कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से कहा कि वह गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के ख़िलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उनकी बिजली-पानी की आपूर्ति बंद करे. न्यायालय ने कहा था कि अधिकरण को यह जिम्मेदारी देना जरूरी है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी औद्योगिक इकाइयों के ख़िलाफ कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई थी कि 'यह संस्थागत विफलता है और आपकी कहानी तो पूरी विफलता, निराशा और बर्बादी की कहानी है. आपको प्रदूषण करने वाली इकाईयों के ख़िलाफ खड़ा होने की जरूरत है. अगर यह काम आप पर छोड़ दिया गया तो इसे पूरा करने में और 50 साल लगेंगे.' हालांकि, केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि गंगा नदी की सफाई सरकार के इसी कार्यकाल में पूरी हो जाएगी.

गोविंद कुमार सक्सेना की इस किताब में कुल नौ अध्याय हैं जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कुंभ विज़न का मूल्यांकन, उसके आध्यात्मिक महत्व, गंगा का महात्म्य, यमुना और सरस्वती के महात्म्य, संगम, माघ मेला, कुंभ के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की है. साथ ही उन्होंने संगम के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए ग्रीन कुंभ और स्मार्ट कुंभ जैसी परिकल्पनाएं की हैं. यह कल्पनाएं अगर साकार होती हैं तो पर्यावरण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महान उपलब्धि होगी. किताब में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आदि पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और गंगा सफाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं. कुंभ विज़न 2025 एक जरूरी किताब है जिसे हर पर्यावरण प्रेमी और आस्थावान को पढ़नी चाहिए ताकि गंगा नदी की दुर्दशा और उस पर मौजूद संकट की समग्र जानकारी हो सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक समीक्षा

किताब- कुंभ विज़न 2025
लेखक- गोविंद कुमार सक्सेना
प्रकाशक- साहित्य भंडार, इलाहाबाद
मूल्य- 400 (हार्डबैक)

कविता

गुलज़ार

एक परवाज़ दिखाई दी है,
तेरी आवाज़ सुनाई दी है.
जिस की आंखों में कटी थी सदियां,
उसने सदियों की जुदाई दी है
सिर्फ़ एक सफ़हा पलट कर उसने,
बीती बातों की सफ़ाई दी है.
फिर वहीं लौट के जाना होगा,
यार ने कैसी रिहाई दी है.
आग ने क्या क्या जलाया है शब भर
कितनी ख़ुश-रंग दिखाई दी है.

सांस लेना भी कैसी आदत है,
जीये जाना भी क्या रवायत है.
कोई आहट नहीं बदन में कहीं,
कोई साया नहीं है आंखों में.
पांव बेहिस हैं, चलते जाते हैं
इक सफ़र है जो बहता रहता है
कितने बरसों से, कितनी सदियों से,
जिये जाते हैं, जिये जाते हैं
आदतें भी अजीब होती हैं.

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें
CHAUTHI DUNIYA APP

पूर्णिमा की रात में यहां के ढोरडो क्षेत्र में गुजरात की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पूरे चंद्रमा यानी पूर्णिमा की रात कच्छ के रण में ऊंट की सवारी करना एक यादगार पल है. कच्छ में देखने लायक अन्य जगहों में से कच्छ का रण, नारायण सरोवर, बन्नी घास के मैदान, कच्छ के रेगिस्तान एवं वन्यजीव प्रमुख हैं.

सैर-सपाटा

सफेद रेगिस्तान की करें सैर

गुजरात के कच्छ जिले के थार मरूस्थल में स्थित कच्छ का दीर्घ रण एक मौसमी दलदल है. यह विश्व का सबसे बड़ा लवणीय मरूस्थल है. दीर्घ रण 7505 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है और यह कच्छ के लघु रण की तुलना में थोड़ा बड़ा है. यह विभिन्न प्रकार के जन्तु तथा पौधों की प्रजातियों के लिये घर है. विभिन्नता वाले मौसम के कारण यह कई प्रवासी पक्षियों के आराम करने का स्थान भी है. यह गुजरात के उत्तर पश्चिम में स्थित भारत का सबसे बड़ा जिला है. यहां 18 आदिवासी संस्कृतियां हैं, जो इस जगह को यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाती हैं. स्वप्निल क्षितिज के साथ कभी न खत्म होनेवाला रेगिस्तान मानसून में लुभावने दृश्य उकेरता है. मानसून के समय पानी में डूबकर कच्छ सपनों सरीखी जगह बन जाता है. आपको साल के बाकी समय में यहां दूर तक फैला सफेद नमक दिखायी देगा, जिसकी वजह से ये सफेद रेगिस्तान लगता है. पूर्णिमा की रात में यहां के ढोरडो क्षेत्र में गुजरात की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पूरे चंद्रमा यानी पूर्णिमा की रात कच्छ के रण में ऊंट की सवारी करना बहुत ही मनभावन लगता है और इसकी याद हमेशा दिलादिमाग में तरोताजा बनी रहती है. कच्छ में देखने लायक अन्य जगहों में से कच्छ का रण, नारायण सरोवर, बन्नी घास के मैदान, कच्छ के रेगिस्तान एवं वन्यजीव हैं.

कब जाएं

कच्छ आने का सबसे बढ़िया समय सर्दियों का मौसम है.

कैसे पहुंचें

कच्छ के लिये निकटतम हवाईअड्डा भुज हवाईअड्डा है. यह स्थान रेल तथा सड़क मार्गों से भी अच्छी तरह से जुड़ा है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

खाना पीना

ललचाती है गुजराती बासुंदी

बासुंदी उत्तर भारतीय रबड़ी की तरह से ही दूध को एकदम गाढ़ा करके और इसमें सूखे मेवे, नटमेग पाउडर और केसर मिला कर बनाई जाती है. इसे हम होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि जैसे किसी भी त्योहार पर बना कर परोस सकते हैं.

विधि

दूध को गरम करके रख दीजिये, दूध में उबाल आने के बाद काजू, बादाम, केसर और नटमैग पाउडर डालकर मिला दीजिये, गैस धीमी कर दीजिये. धीमी गैस पर दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है. दूध पर जैसे ही मलाई की परत आयेगी, उसे दूध में मिक्स कर दीजिये. इस प्रोसेस को बार-बार करें. जैसे ही मलाई की परत आयेगी, उसे दूध में मिक्स कर दीजिये. इस तरह मलाई की परतों से दूध में मलाई के लच्छे बनते जायेंगी और दूध गाढ़ा होता जायेगा. जब दूध का एक तिहाई भाग रह जाए और दूध गाढ़ा दिखने लगे, तब दूध में चीनी और इलाइची पाउडर डाल कर मिला दीजिये और गैस से उतार लीजिये. केसर बासुंदी तैयार है. केसर बासुंदी को फ्रिज में रखकर 2-3 दिन परोसा जा सकता है.

आवश्यक सामग्री

- दूध - 4 कप (1 लीटर)
- चीनी - 1/3 कप (70- 80 ग्राम)
- बादाम - 1 टेबल स्पून
- काजू - 2 टेबल स्पून (एक काजू को 6-7 टुकड़े करते हुए काट लीजिये)
- पिस्ता - 6-7
- केसर - 25-30 धागे
- नटमेग पाउडर = 1/4 छोटी चम्मच से आधा
- छोटी इलाइची - 4 छील कर पाउडर बना लीजिये. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

फैशन

सर्दी का मौसम आने में 2 महीने बचे हैं, लेकिन परिधानों का प्रदर्शन अभी से ही शुरू हो चुका है. पिछले दिनों बेंगलुरु में एविराट के विंटर कलेक्शन का रैंप पर प्रदर्शन करतीं मॉडल्स.

करियर

इवेंट मैनेजमेंट में बनाएं करियर

किसी भी प्रोग्राम को परफेक्ट तरीके से आयोजित करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है. फिर वो कोई अवॉर्ड फंक्शन हो या म्यूजिक लॉन्च. इस तरह के प्रोग्राम की प्लानिंग करने का काम करते हैं इवेंट मैनेजर. आजकल इवेंट मैनेजमेंट काफी चर्चित और लोकप्रिय करियर बन चुका है. अगर आप कमाई के साथ-साथ एक्साइटमेंट का भी मजा लेना चाहते हैं, तो आपका यह ख्वाब इवेंट मैनेजमेंट पूरा कर सकता है. इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोग किसी व्यावसायिक या सामाजिक समारोह को आयोजित करते हैं. उसमें मुख्य रूप से फैशन शो, संगीत समारोह, शादी समारोह, थीम पार्टी, प्रदर्शनी, कॉर्पोरेट सेमिनार, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, प्रीमियर के प्रोग्राम आते हैं. एक इवेंट मैनेजर क्लाइंट या कंपनी के बजट को ध्यान में रखकर प्रोग्राम का आयोजन करते हैं. होटल या हॉल बुक करने, साज-सज्जा, एंटरटेनमेंट, लंच या डिनर के लिए खास तरह के मेन्यू को तैयार करवाने, गेस्ट का स्वागत, तक की व्यवस्था इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल लोगों को करनी होती है. यह एक ऐसी फ़ील्ड है, जहां पर युवाओं की बहुत जरूरत होती है, क्यूंकि उनके पास प्रोमोट करने और ऑर्गनाइज करने के कई नए तरीके होते हैं. इसलिए यह फ़ील्ड उन सभी लोगों के लिए रोज़गार के अवसर लेकर आती है, जो मेहनती हैं. साथ ही उनके पास अलग-अलग तरीके हैं. यह काम थोड़ा सा रिस्की भी है, इसलिए आपको अपनी आंखे खुली रख कर काम करना होता है. सही प्लानिंग और सही सर्विसिंग इस व्यवसाय की जरूरत है.

योग्यता:

इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कई तरह के कोर्स हैं. डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एक साल का कोर्स है, जिसमें एडमिशन के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा 6 महीने का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है, जिसके लिए 12वीं पास होना चाहिए.

प्रमुख संस्थान:

एमिटी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, मुंबई

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

जगमोहन डालमिया ने बीसीसीआई को आत्मनिर्भर बनाया

जगमोहन डालमिया भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया, उसके लिए भारतीय क्रिकेट प्रेमी ताउम्र उन्हें याद रखेंगे. डालमिया का जन्म 30 मई 1940 को कोलकाता में हुआ था. डालमिया ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की थी. उन्होंने अपना करियर विकेटकीपर के तौर पर शुरू किया था. डालमिया कोलकाता के क्रिकेट क्लब के लिए खेला करते थे. उन्होंने खेलते हुए दोहरा शतक भी लगाया था. उन्होंने अपने पिता के बिजनेस कंपनी एमए डालमिया को ज्वॉइन किया और उसे भारत की नंबर वन कंस्ट्रक्शन फर्म में तब्दील किया. उन्ही की फर्म ने कोलकाता के एमपी बिड़ला प्लेनोटोरियम बनाया था, जो कि साल 1963 में बनकर तैयार हुआ था. साल 1979 में उन्होंने बीसीसीआई को ज्वॉइन किया और साल 1983 में डालमिया बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने. इसी साल भारत ने पहली बार विश्वकप जीता था. 1997 में जगमोहन डालमिया आईसीसी अध्यक्ष चुने गये. यह पहले एशियाई आईसीसी अध्यक्ष थे. अपने खिलाड़ियों के लिए डालमिया किसी से भी भिड़ जाने वाला रवैया रखते थे. 2000 में आईसीसी अध्यक्ष पद से हटने के बाद 2001 में वह बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे. डालमिया ने 10 साल बाद इसी वर्ष मार्च में दूसरी बार

बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था. 2004 के विवादित बीसीसीआई चुनाव में डालमिया के नजदीकी रणबीर सिंह महेंद्र अध्यक्ष चुने गए. हालांकि 2005 में शरद पवार के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद डालमिया को अपने विरोधियों का भी सामना करना पड़ा. डालमिया को बीसीसीआई से पूरी तरह बाहर कर दिया गया. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई. डालमिया ने हालांकि कानूनी लड़ाई जीतने के बाद 2006 में दोबारा खेल प्रशासक के तौर वापसी की और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष चुने गए.

डालमिया एक ऐसे शख्स थे, जिन्होंने बीसीसीआई को विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनाया. पहली बार क्रिकेट के साथ पैसा आया. डालमिया और बिंद्रा ने क्रिकेट का व्यापारीकरण किया. बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को हमेशा ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किया जाएगा, जिसने भारतीय क्रिकेट को आत्मनिर्भर संस्था बनाया और विश्व क्रिकेट में अंग्रेजों की ताकत को खत्म कर क्रिकेट को लॉर्ड्स से कोलकाता के ईडन गार्डंस तक पहुंचाया. उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एनकेपी साल्वे को मनाया कि रिलायंस कप के फाइनल का आयोजन वानखेड़े स्टेडियम की जगह कोलकाता के ईडन गार्डंस में कराया जाए. उन्होंने एक समय अपने मित्र रहे इंदरजीत सिंह बिंद्रा के साथ मिलकर इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया को पछाड़कर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को 1996 विश्व कप की सह मेजबानी दिलाई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

लोकेशन ढूंढते-ढूंढते मुंह से निकला

दिमाग का दही हो गया

फ़ौज़िया अर्शी

इंटरव्यू

हिंदी फिल्म जगत में बहुत कम ऐसे कलाकार हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हों. ऐसी ही एक कलाकार हैं ***फ़ौज़िया अर्शी.*** फ़ौजिया अर्शी डीएमएल के बैनर तले बनी फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** की निर्देशक और संगीतकार हैं. साथ ही उन्होंने इस फिल्म के कुछ गीत भी गाए हैं. इस फिल्म से क़ादर ख़ान फिल्मों में वापसी भी कर रहे हैं. बॉलीवुड के पांच दिग्गज हास्य कलाकारों को लेकर बनी यह फिल्म कई नए चेहरों को भी अपने साथ समेटे हुए है. यह फ़ौज़िया अर्शी की पहली फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी फिल्म काफी मायने रखती है. इससे उसका फिल्म जगत में भविष्य निर्धारित होता है. इस फिल्म के निर्माण और निर्देशन की कठिनाइयों पर ***चौथी दुनिया*** संवाददाता नवीन चौहान ने विस्तार से फ़ौज़िया अर्शी से बातचीत की. उन्होंने भी बड़ी संजीदगी से हर सवाल का खुलकर जवाब दिया. प्रस्तुत हैं इस बातचीत के कुछ अंश...

आपकी आने वाली फिल्म होग़या दिमाग़ का दही का शीर्षक बड़ा ही रोचक है, इस शीर्षक का चुनाव कैसे हुआ?

जब मैं फिल्म की शूटिंग की लोकेशन की तलाश में हिमाचल प्रदेश गई थी, उस वक्त हिमाचल में बहुत ठंड थी, वहां तूफानी बारिश हो रही थी, जबकि उस वक्त ऐसा नहीं होना था. अचानक से यह सब शुरु हुआ, तो लोकेशन मिलने में बहुत परेशानी आई. हिमाचल प्रदेश इतना खूबसूरत है कि अरे यह भी अच्छा लग रहा है, वह भी अच्छा लग रहा है. इसके साथ एक कन्फयूजन भी था, लेकिन जो एक बात मेरे ज़ेहन में आई कि एक हवेली थी जो फिल्म में दिखाई गई है एक खंडहर हवेली, वह फिल्म में एक कैरेक्टर की तरह खड़ी थी, उस खंडहर हवेली को ढूंढ़ने में बहुत वक्त लग रहा था, कभी यहां जा रहे थे, कभी वहां जा रहे थे और फिर उसके टेढ़े-मेढ़े रास्ते बहुत खूबसूरत भी थे, खैर ऐसे में एक दिन मेरे मुंह से निकला कि यार दिमाग का दही हो गया है लोकेशन ढूढ़ते-ढूढ़ते. वह मैंने कह तो दिया, लेकिन कहते ही मुझे लगा कि अरे यह तो कमाल का टाइटल है. उस वक्त मेरे साथ मेरे तीन साथी भी थे, वो सब भी हंस पड़े और मैनें कहा कि अब हम फिल्म का टाइटल रखेंगे दिमाग का दही और फिर इसे इंप्रोवाइज करते-करते हमने होगया दिमाग का दही टाइटल को फाइनल कर दिया.

यह बतौर निर्देशक आपकी पहली फिल्म है आपने कॉमेडी का ही चुनाव क्यों किया?

मुझे खुश रहना, लोगों को खुश रखना और हंसना अच्छा लगता है. दूसरी तरफ मैं जिस शहर से हूं वह है भोपाल. भोपाल अपनी हाज़िर-जवाबी और अच्छे मज़ाक के लिए मशहूर है. मैं वहीं पढ़ी-लिखी, मैं वहीं रह रही हूं. ऐसे में एक माहौल का असर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचीत और आपके तौर-तरीके में आता है, वो सब जिंदगी ने मुझे दिया और मैं उसे आगे लेकर बढ़ी और अपना काम शुरु किया. जब फिल्म बनाने कि बात आई, तो मुझे लगा कि मेरे सामने बहुत सारी स्क्रिप्ट थीं, कि यह बनाया जाए या वह बनाया जाए. फिल्म के निर्माता संतोष भारतीय हैं, उनसे मैंने डिसकस किया.फिर मैंने उनसे कहा कि सर हम किसी स्क्रिप्ट पर काम शुरू करें, बताइये क्या हो सकता है. कुछ तैयार हो जाए, फिर हमने कहां कि नहीं अब हम कॉमेडी फिल्म ही बनाएंगे, क्योंकि इतने अनुकूल माहौल में भी लंबे समय से कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म नहीं आ रही है और द्विअर्थी कॉमेडी फिल्में आ रही हैं.

क़ादर खान इस फिल्म से वापसी कर रहे हैं, उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए आपको कैसी मशक्कत करनी पड़ी?

पहले तो मुझे लोगों ने डरा दिया कि अरे क़ादर खान जी के पास तो जाना नहीं, वो तो बात करते ही नहीं हैं और वो तो आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे, तो एक-आध दिन तो ऐसे ही गुज़र गया. फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉमेडी मतलब क़ादर खान. जैसे ही कॉमेडी फिल्म के बारे में सोचा तो कॉमेडी फिल्म बिना क़ादर खान के बन ही नहीं सकती थी. इसके बाद यह जरूर सुना था कि वह शहर में नहीं हैं वह पुणे में रहने लगे हैं. इसके बाद मालूम हुआ कि वह बीमार चल रहे हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन हम एक दिन हिम्मत करके उनके घर पहुंच गए और हमने उनके सेक्रेटरी से कहा कि हमें एक बार कादर खान जी से मिलवा दीजिए, उन्होंने कहा कि वो तो नहीं मिलेंगे, हमने कहा कि यदि नहीं मिलेंगे, तो हम भाग जाएंगे. लेकिन हमें एक बार मिलावाइए तो सही. खैर उन्होंने कोशिश की और हमने उनसे मुलाकात की, तो क़ादर ख़ान जी से मैंने कहा कि कादर साहब मैं यह फिल्म बनाना चाहती हूं. कॉमेडी फिल्म है और आपके बिना यह फिल्म मैं नहीं बनाऊंगी और फिल्म में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पांच मिनट तक मुझे देखते रहे और कहने लगे कि अच्छा तुम करती क्या हो. मैंने कहा कि मैं फिल्म बनाती हूं. इसके बाद वह कहने लगे कि फिल्म तो बनाती हो, लेकिन उसके अलावा क्या करती हो, क्या किया है तुमने जिंदगी में, तो मैनें कहा कि कादर साहब मैं मैनेजमेंट की प्रोफेसर भी हूं. मैंने काफी सालों तक पढ़ाया लिखाया है, म्यूजीशियन भी हूं अब म्यूजिक और फिल्में ही मेरा शौक है, तो अब मैं यह कर रही हूं. तो उन्होंने कहा कि फिर कोई बात नहीं है अब आगे बताओ, क्योंकि तुममें और मुझमें एक चीज कॉमन है, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता था, तुम मैनेजमेंट पढ़ाती हो, अब तुम्हारी और हमारी बात बन जाएगी और हम काम करेंगे. एक इतने बड़े राइटर जिन्होंने अमिताभ बच्चन और दूसरे बड़े कलाकारों को बनाया हो अगर वह कहे कि स्क्रिप्ट में दम है डायलाग्स अच्छे हैं, तो कितना विश्वास आता है.

कादर ख़ान साहब को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, फिल्म जगत के किन किन लोगों ने आपके पत्र का समर्थन किया है.

देखा जाए तो इसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई इस बात के लिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं, बताइये हम इस बात का बिल्कुल सपोर्ट करेंगे कुछ लोगों ने अखबारों में कोट दिया. ऋषि कपूर साहब ने कोट दिया. अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया और उनसे अपनी मोहब्बत जताई. जाफरी बड़े राइटर हैं, उन्होंने ने बहुत इनकरेज किया. उन्होंने मुझे उनके ढेरों एचीवमेंट्स गिना दिए. उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ये सभी लोग. इसके अलावा जितेंद्र उन्होंने इस बात का सर्मथन किया है, असरानी, शक्ति कपूर, गोविंदा, अनिल कपूर, सलीम साहब हैं. इन सारे लोगों ने इसका सर्मथन किया.

बॉलीवुड के पांच बड़े कॉमेडियन को एक साथ कास्ट करने का आपका अनुभव कैसा रहा?

अनुभव बहुत ही खूबसूरत और कमाल का, बहुत ही एक्साइटिंग और अनोखा रहा. ये जो पांच लोग हैं उन्हें इकट्ठा एक छत के नीचे खड़ा करना और उनसे काम करवालेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था. मुश्किल इसलिए भी नहीं था, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि क्या करना है, मुझे स्क्रिप्ट मालूम थी, मैंने उसका पूरा होमवर्क किया हुआ था. मुझे बहुत बारीकी से पता था की फिल्म कैसी दिखेगी, तो परेशानी नहीं हुई और आसान इसलिए लगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया.

आप फिल्म की निर्माता है, निर्देशक हैं, संगीतकार हैं और गायिका भी. एक साथ इतनी भूमिकाएं अदा करने में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा?

मुझे इसमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये चारों जो रोल हैं मेरे ये चारों अलग-अलग हैं. यदि आप अपनी सीमाएं बना लें, दायरें बना लें. अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और उस वक्त प्रोड्यूसर के दायरे मे हूं, उस पर डायरेक्टर हावी नहीं होता और अगर डायरेक्टर हूं तो उस पर प्रोड्यूसर हावी नहीं होता. यदि म्यूजीशियन हूं, तो उस पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हावी नहीं होते. अगर हमें अपने दायरे पता हों, तो सारे काम असानी से हो जाते हैं. कोई कनफ्यूजन नहीं होता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तो इतनी भूमिकाएं अदा करना बिल्कुल कठिन नहीं था. बस इतना है कि हिन्दुस्तान में हॉलीवुड की तरह एक्सेप्टेंस जरा मुश्किल है. लोगों को यह हजम नहीं होता कि कोई एक इंसान इतने काम कर सकता है. वैसे हॉलीवुड में मडोना गाने भी लिखती हैं, ब्रिटनी स्पियर्स गाने भी लिखती हैं, उसपर परफॉर्म भी करती हैं, फिल्म में एक्ट्रेस भी हैं, अपने गाने कंपोज भी करती हैं, गिटार भी बजाती हैं, ड्रम्स भी बजाती हैं प्रोड्यूस भी करती हैं. मैं कहती हूं कि राजकपूर एक्टर भी थे डायरेक्टर भी थे, म्यूजीशियन भी थे और फिल्में प्रोडयूस भी करते थे, संजय लीला भंसाली म्यूजीशियन भी थे, डायरेक्टर भी और प्रोडयूसर भी थे, तो ऐसा कुछ नहीं है थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की बात होती है. बाकी पहले वाला पोर्शन मैंने आपको बताया कि उसमें कोई चैलेंज नहीं था.

> मुझे सबसे अच्छा संगीत लगता है. क्योंकि संगीत के माहौल में जब मैं होती हूं, अपने संगीत की धुन में होती हूं, अपने गाने के कंपोजिशन में व्यस्त होती हूं, तब सिर्फ मैं होती हूं और उस वक्त बड़ा ईमानदार माहौल होता है. वहां कोई चालाकी नहीं होती, कोई मैन्यूपुलेशन नहीं होता, इसलिए मुझे म्युजिक सबसे अच्छा लगता है. मैं खुद से मिलती हूं वहां पर कि मैं एक अच्छी इंसान हूं.

निर्देशन, संगीत और गायन इन तीनो में आपको सबसे ज्यादा क्या पंसद है?

बड़ा अच्छा सवाल है ये. इनमें से मुझे सबसे अच्छा संगीत लगता है. अब आप पूछेंगे कि संगीत ही क्यों अच्छा लगता है. क्योंकि संगीत के माहौल में जब मैं होती हूं, अपने संगीत की धुन में होती हूं, अपने गाने के कंपोजिशन में व्यस्त होती हूं तब सिर्फ मैं होती हूं, और उस वक्त बड़ा ईमानदार माहौल होता है. वहां कोई चालाकी नहीं होती, कोई मैन्यूपुलेशन नहीं होता, इसलिए मुझे म्यजिक सबसे अच्छा लगता है. मैं खुद से मिलती हूं. वहां पर कि मैं एक अच्छी इंसान हूं.

फिल्म के टीजर में फिल्म को नॉन-फैमिल ड्रामा बताया जा रहा है इसका क्या मतलब है?

आप पहले इंसान हैं जिसने हमसे यह सवाल पूछा. इसे कॉमेडी ड्रामा हमने व्यंगात्मक संदर्भ में कहा है. यह एक फैमिली की कहानी नहीं है यह करैक्टर की कहानी है. नहीं तो क्या लोगों को कन्फयूजन हो जाता है कि जहां एक घर है, बाप है उसके लड़के हैं, तो उनकी बहुएं हैं. बट इट्स नॉट अबाउट फैमिली इट्स अ युनीवर्सल फैक्ट जो इसमें हमने दिखाया है. यह फिल्म कैरेक्टर्स की कहानी है. जिसे पूरी फैमिली जाकर देख सकती है.

इतने सारे कॉमेडियन एक सेट पर होते थे, तो ऐसे में सेट का माहौल कैसा होता था?

बहुत अच्छा सवाल, मैं आपको कमाल की बात बताऊं, देखिए सब सोचते होंगे कि इतने सारे कॉमेडियन हैं, तो सेट पर बहुत हंसी-ठिठोली होती होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था. सेट पर उतनी ही देर मस्ती होती है, जितनी देर हम टेक कर रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है और हर शॉट में कॉमेडी थी, पंचेज थे मजा था. तो हम इसे बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन जैसे ही शॉट खत्म हुआ. जहां शॉट खत्म हुआ, ओमपुरी जी अपनी स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते थे देखने, एक तरफ राजपाल बैठ जाते थे और दूसरी तरफ संजय. सीन कैसे इंप्रोवाइज हो इस पर डिसकशन करने लगते थे. मतलब ये बहुत ज्यादा गंभीर कलाकार हैं. पर्दे पर ये लोग कॉमेडियन हैं. अन्यथा ये लोग बहुत सिंसियर और बहुत संजीदा लोग हैं. राजपाल आकर कहते थे अरे फौजिया जी देखिए ये सीन अपना ऐसा है मैं इसे ऐसे करके बताऊं. ओमजी इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन वह एक नए डायरेक्टर के साथ भी उसी तरह व्यहार कर रहे थे जैसे कि बहुत बड़े और पुराने डायरेक्टर के साथ व्यवहार करते हैं.

इस फिल्म में ओमपुरी का जो किरदार है मिर्जा किशन सिंह जोसेफ, इसका क्या रहस्य है और क्या इसमें कोई संदेश भी छिपा है?

ये हम आपको नहीं बताएगें यह आपको 16 अक्टूबर को ही पता चलेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

इंटरव्यू

रूहानी कव्वाली है मौला-मौला

भारतीय फिल्मों में जब भी कोई अच्छी कव्वाली आई, लोगों ने उसे हाथोंहाथ लिया. अब फ़ौज़िया अर्शी निर्देशित फिल्म हो गया दिमाग का दही में भी एक कर्णप्रिय कव्वाली है. इस कव्वाली को आवाज़ दी है मशहूर गायक कैलाश खेर ने. यह कव्वाली आते ही यूट्यूब व अन्य चैनलों पर खूब सुनी जा रही है. लोग इसे पसंद कर रहे हैं. इस कव्वाली के गायक कैलाश खेर से उनकी राय जानने के लिए उनसे बात की चौथी दुनिया संवाददाता *अरुण तिवारी* ने...पेश हैं मुख्य अंश

● **प्रश्न- फिल्म 'हो गया दिमाग का दही' में आपने कव्वाली 'मौला-मौला' को आवाज़ दी है. उसे लेकर आपका अनुभव कैसा रहा?**

जवाब- यह अनुभव अद्भुत और अलौकिक रहा क्योंकि आज के युग में काफी ज्यादा गहमा-गहमी और उच्चश्रृंखलता है. लेखन में गहराई का अभाव है. गायकी के भी स्तर में थोड़ी गिरावट आई है. यह कार्य अच्छे संकलन से हुआ है. इसमें अल्लामा इक़बाल, अमीर ख़ुसरो और कृष्ण बिहारी नूर जैसे बड़े शायरों की शायरी है. इन्हें फ़ौज़िया अर्शी ने संकलित किया है. फ़ौज़िया अर्शी को ईश्वर ने परमात्मा ने कई गुणों से लाभांवित किया है. वे फिल्म की निर्देशक भी हैं. और जब अच्छे काम का बुलावा आता है, तो हम उससे जुड़ जाते हैं.

● **प्रश्न- हाल में बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी जो सुपरहिट रही. उसमें अदनान सामी ने क़व्वाली गाई है और अब इस फिल्म में आप की क़व्वाली है. क्या फिर से कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया है?**

जवाब- देखिए, सिर्फ ट्रेंड कायम नहीं होता. दरअसल बीच-बीच में अच्छी चीजें फिर से आ जाती है. बाहुबली में हमारे शिव तांडव की विश्व स्तर पर चर्चा हुई. होता क्या है कि हमारे इर्द-गिर्द ही कोहिनूर घूमते हैं. तेरी काया नगर में राम-राम, तू जंगल-जंगल क्या ढूंढे/ तेरे रोम-रोम में राम-राम, तू पत्थर में सर क्या मारे.

● **प्रश्न- जैसी रूहानी मौशिकी के लिए आप जाने जाते हैं, मौला मौला को उसके कितने नज़दीक पाते हैं?**

जवाब- इसमें अच्छे शायरों के लेखन का संकलन है. आज के युग में अच्छी चीजें कम बनती हैं. इसका शुमार अच्छी चीजों में आएगा.

● **सवाल- हमारी जानकारी में फ़ौज़िया अर्शी पहली बार संगीत दे रही हैं. संगीतकार कैसी लगीं वे आपको?**

जवाब- पहला कार्य बड़ा जुनूनी होता है. जब हमारी पहली अलबम कैलाशा आई थी. तेरी दीवानी उसी का गाना है. इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाये हंसते-हंसते आशिक सूली चढ़ जाये, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले. तो फौजिया ने भी अपने पहले काम को जुनूनी तरीके से पूरा किया है.

● **फ़ौज़िया जी की आवाज भी है उस क़व्वाली में आपके साथ है गायिका के तौर पर आप उन्हें कैसा पाते हैं?**

फिल्म हो गया दिमाग़ की कव्वाली मौला-मौला के एक दृश्य में शाहबाज़ ख़ान

बहुत बहुत प्यारा है अभी-अभी देखिये सब अच्छा है. मेरे दाता ने चाहा तो अब इस को थोड़ा लोग सुनें. गाना आगे जाये और फिल्म लोगों द्वारा देखी जाये. अब तो केवल उतने की जरूरत है. यही गाना तार देगा लोगों को अगर दिल से सुन लिया तो.

● **यह कव्वाली ट्रेंड भी कर रही है यहां दिल्ली में बहुत जगहों पर इसे सुना भी जा रहा है एफएम पर, टीवी चैनलों हर जगह, इसे लेकर आपको कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है?**

अच्छी मिल रही है. सब लोग तारीफ कर रहे हैं. खुशी की बात है कि अच्छी चीजों की तारीफ हो वरना बुराइयों ने इतना घेर रखा है माहौल को, बाजार में घटिया माल इतना ऊतर आया है की अच्छे माल की कोई पहचान ही नहीं रही, थैंक गॉड अच्छी चीजें भी बाजार में है उनकी भी तारीफ हो रही है. उनके भी चाहने वाले हैं इस दुनिया में यानी दुनिया में पृथ्वी वीरों से खाली अभी नहीं है. यहां तक दिल्ली की बात है दिल्ली में तो संगीत के चाहने वाले रसिक बहुत पाये जाते हैं. और वहां मोहब्बत करने वाले, संगीत से प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं. चाहे हमारा अकड़ बम बम बम बम लहरी हो या बिस्मिल्लाह हो या अब मौला मौला मौला मौला रे जिसके बार में आप बात कर रहे हैं सभी को लोग बहुत चाहते हैं. ■

पुणे पहुंची होगया दिमाग का दही की टीम

पुणे के सीजन मॉल में होगया दिमाग का दही की टीम ने वहां मौजूद लोगों से बात की. इस दौरान मॉल में मौजूद हजारों लोगों ने इस फिल्म के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाते हुए कलाकारों से कई सवाल भी किए.

सवाल नंबर-4

फिल्म होगया दिमाग का दही का निर्देशन किसने किया है?

A. फ़ौज़िया अर्शी
B. संतोष भारतीय
C. डेविड धवन
D. प्रतीश नंदी

अपना जवाब मेल आईडी dailymultimedia1@gmail.com पर मेल करें सबजेक्ट Hogaya Dimaagh Ka Dahi QUIZFOUR (ऑप्शन A/B/C/D) शहर का नाम लिखें या मोबाइल नंबर पर **072104-38230** QUIZFOUR (स्पेस), (ऑप्शन A/B/C/D) जवाब मैसेज करें.

नोट

1. पुरस्कार दो लकी विजेताओं को मिलेगा.
2. दो से ज्यादा सही जबाब मिलने पर विजेता का फैसला लकी ड्रॉ द्वारा निकाला जायेगा.
3. फिल्म का टिकट आपके नजदीकी पीवीआर/ फन सिनेमा का दिया जाएगा.
4. आपके जवाब हमें 11 अक्टूबर,2015 को रात 12 बजे से पहले मिल जाने चाहिए.

होगया दिमाग का दही QUIZ के सवाल नंबर-1 के विजेताओं के नाम

1. विकास कुमार, राजेंद्र नगर, पटना (बिहार)
2. सबा, बालाचट बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

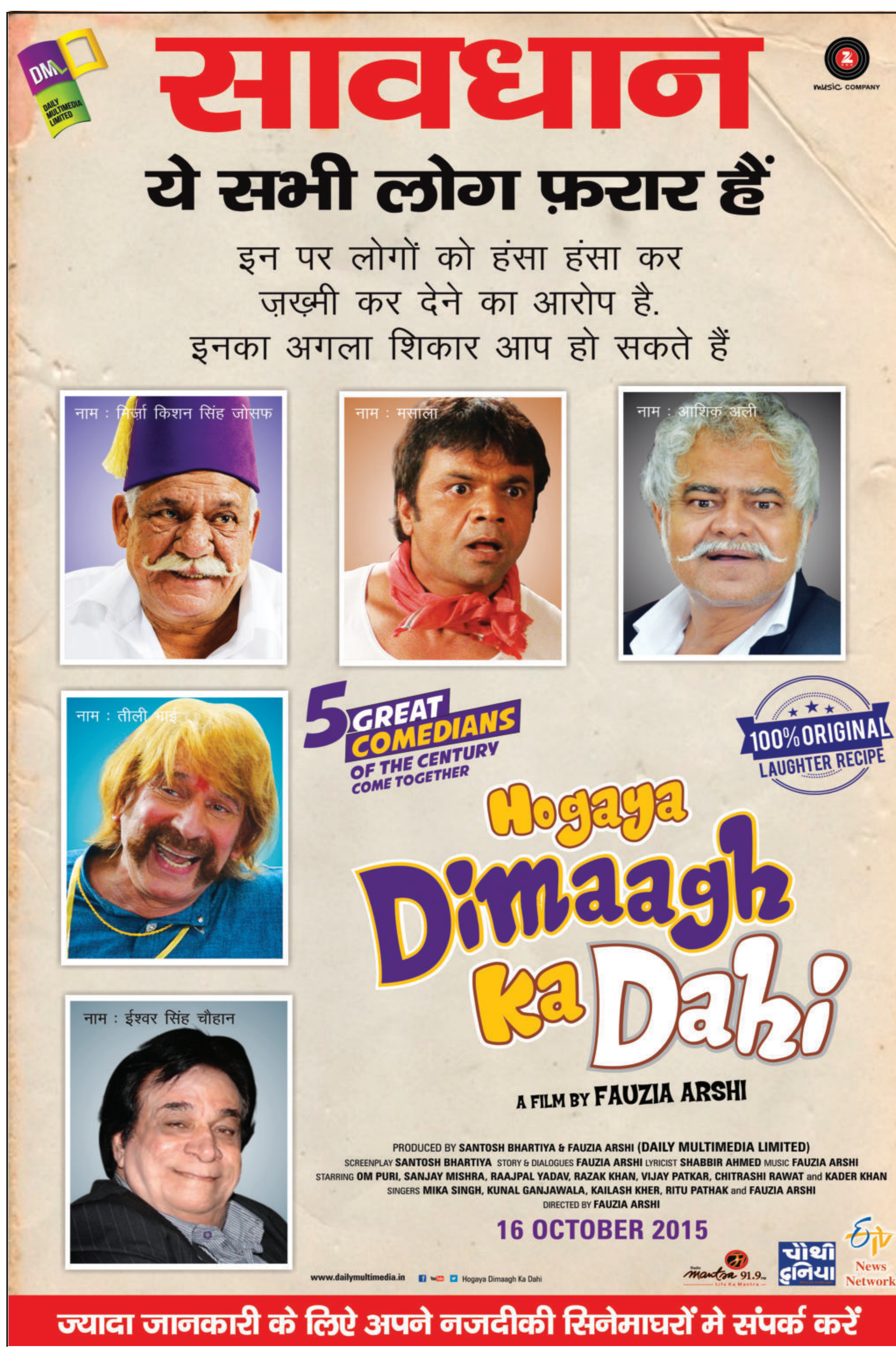

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

05 अक्टूबर-11 अक्टूबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

गन्ना किसान तबाह, अब आलू और मेंथा किसानों की बारी

किसान बर्बाद जय समाजवाद!

प्रभात रंजन दीन

कभी जय जवान-जय किसान का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के किसान अब किसान बर्बाद-जय समाजवाद का नारा लगा कर प्रदेश की समाजवादी सरकार को कोस रहे हैं. गन्ना किसानों को तबाह करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार आलू किसानों और मेंथा किसानों को तबाह करने पर तुली है. गन्ना किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपये का बकाया देने से चीनी मिलों ने साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सरकार चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही. अब हालत यह है कि गन्ना किसान गन्ने की खेती से भाग रहा है. अब यही हाल उत्तर प्रदेश के आलू किसानों और मेंथा उपजाने वाले किसानों का होने वाला है. आप जानते ही हैं कि कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, लेकिन आलू पैदा करने वाले किसानों की फसल कौड़ियों में बिक रही है और वह बर्बाद हो रहा है. इस वजह से कोल्ड स्टोरेज पर भी आफत है. आगरा से लेकर फर्रुखाबाद तक का विस्तृत आलू क्षेत्र बेहद संकट में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार किसान-हित के खोखले नारे लगाने में ही मस्त है.

कर्नाटक के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी आलू उत्पादन की पट्टी आगरा से लेकर फर्रूखाबाद तक है, जहां के आलू उत्पादक किसान और आलू उत्पादन पर निर्भर सारे उद्योग बर्बादी के कगार पर हैं. हालत यह है कि आलू उत्पादकों को लागत का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है. इससे आलू के किसान कोल्ड स्टोरेज में रखा अपना आलू नहीं निकाल रहे हैं और उन्होंने वहां आलू सड़ने के लिए छोड़ दिया है. आप सब जानते हैं कि जुलाई-अगस्त में ही आलू की सर्वाधिक निकासी होती है. लेकिन सितम्बर भी बीत गया और आलू की निकासी अब तक नहीं हो रही. आलू किसान की एक एकड़ में लगभग एक लाख रूपए की लागत आती है. एक एकड़ खेत में आलू किसान 35 कट्टे आलू का बीज लगाता है, यानि 1750 किलो आलू का बीज, जिसकी कीमत 42000 रुपये होती है. इसके अलावा वह 5000 रुपये की 200 किलो डीएपी, 2400 रुपये की 300 किलो यूरिया, 1200 रुपये का 20 किलो जिंक, 2000 रुपये का 20 किलो पोटाश, 9000 रुपये का 100 किलो सल्फर, 1400 रुपये का जाइम जैसी खादें और कीटनाशक डालता है. आलू की मशीन द्वारा बुआई से 1400 रुपये, जुताई में 3750 रुपये, खुदाई में 9000 रुपये, स्प्रे में 1500 रुपये सिंचाई में 4500 रुपये और बोरों में 4000 रुपये का खर्चा आता है. आलू पैदा होने के बाद किसान 102 रुपये प्रति पचास किलो आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने का किराया देता है, जो लगभग 18000 रुपये होता है. एक एकड़ में करीब 10000 किलो आलू का उत्पादन होता है. ऐसे में यदि आलू का रेट 12 रुपये से 15 रुपये हो, तभी आलू किसान को थोड़ा लाभ हो सकता है. जबकि इस समय आलू की किसान से खरीद 3 से 6 रुपये के बीच है. इससे आलू किसान बुरी तरह घाटे में जा रहा है. इस संकट में आलू के उत्पादन पर निर्भर कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी संकट के शिकार हो रहे हैं. यह कोल्ड स्टोरेज वाले 5 लाख रुपये प्रतिमाह बिजली का बिल दे रहे हैं. आश्चर्य यह है कि इन्हें कॉमर्शियल रेट पर 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, इतना ही नहीं 250 रुपये प्रति यूनिट पर डिमांड चार्ज लिया जाता है और 5.22 प्रतिशत वैट व 7.5 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है. आगरा के शमशाबाद में 30 प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी सरकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं है. पिछले साल आलू उत्पादन में अच्छी कमाई के कारण किसानों ने बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन किया. आलू उत्पादक किसानों के नेता द्वारिका सिंह कहते हैं कि जब आलू का उत्पादन बेहतर हुआ था, तो रोज सरकारी अधिकारी कोल्ड स्टोरेज पर छापा मार रहे थे और किसान-बही जांच रहे थे, लेकिन आज जब आलू किसान संकट में हैं, तो सरकार का कोई नुमाइंदा पूछना तो दूर, दिख भी नहीं रहा है.

उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ी संख्या में किसानों ने आलू की फ़सल बोई थी. लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान अपने इस फैसले पर पछता रहे हैं. आलू को रखने के लिए अब कोल्ड स्टोरेज में भी जगह नहीं मिल रही. बाजार में उचित रेट न मिलने से आलू को सड़कों पर फेंकने की नौबत आ गई है. दूसरा दुखद पहलू यह भी है कि किसानों की मजबूरी देखते हुए मुनाफा कमाने के चक्कर में कोल्ड स्टोरेज मालिक भी आलू रखने की जगह नहीं दे रहे. 50 फीसद से ज्यादा आलू अभी कोल्ड स्टोरेज से बाहर है. पूरा आलू भंडारित नहीं हो पाया. इससे ऊब कर सैकड़ों बीघा आलू की फसल को किसानों ने खेत में ही जोत दिया है. किसान कहते हैं कि आलू का ठीक भंडारण नहीं हो पाया, तो खुदे हुए आलू को फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा. कुछ किसानों ने अपने यहां खुले में ही इस उम्मीद के साथ आलू का

(शेष पृष्ठ 18 पर)

सरकार! किसानों पर कुछ तो ध्यान दो

आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज हैं. मगर पुरानी तकनीक पर आधारित होने की वजह से इनमें भंडारण की लागत बहुत अधिक है. इसके मुकाबले राज्य सरकारों ने इन कोल्ड स्टोरेज के किराए में कई वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया है. महंगी बिजली और महंगे मजदूर होने से उत्तर प्रदेश के कई कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं. कोल्ड स्टोरेज से होने वाली आय में लगातार गिरावट के चलते निवेशक हाथ डालने से बच रहे हैं. आलू उत्पादन में यूपी और कर्नाटक की हिस्सेदारी 35-35 फीसद है. यूपी का 50 फीसद आलू उत्पादन आगरा व अलीगढ़ मंडल में होता है. इसके बावजूद यहां पर कोल्ड स्टोर स्वामियों व किसानों को तमाम दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है. एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर सात करोड़ की लागत आती है. डेढ़ करोड़ की सब्सिडी मिलती है. सब्सिडी से ज्यादा खर्चा मानकों को पूरा करने में ही आ जाता है. यह सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा तक नहीं चुका पाते. अनेक कोल्ड स्टोरेज बंद होने की कगार पर हैं. कोल्ड स्टोरों को देहात की जगह इंडस्ट्रियल फीडर से बिजली मिलनी चाहिए. सड़कें खराब होने से परिवहन के दौरान आलू की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पलटने की घटनाएं खूब हो रही हैं. सरकार के पास आलू उत्पादन व किसानों का कोई डाटा तक नहीं है. सरकार को निर्यात खोल देना चाहिए, ताकि आलू खराब न हो और उसे सड़कों पर फेंकने की नौबत न आए. ■

अकबरपुर को महाराणा प्रताप की जरूरत है

समस्याएं हैं, पर समाधान नहीं

अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात विद्युतकर्मियों की संख्या अपर्याप्त बताई जाती है. जो हैं भी, उनकी शारीरिक बनावट ऐसी नहीं है कि खम्भों पर चढ़कर तार-केबल ठीक कर सकें. इसलिए उन लोगों ने अपने लिए सहायक रख रखे हैं और उन्हीं सहायकों से सारा काम कराया जाता है.

सत्यम सिंह

अम्बेडकरनगर जिले का मुख्यालय है अकबरपुर. यहां इतनी समस्याएं है कि लोग आमतौर कहते मिलेंगे कि अकबरपुर अब कोई महाराण प्रताप ही ठीक कर पाएगा. फिलहाल अकबरपुर की बिजली-समस्या की शाश्वत्तता का दृश्य देखें, आपको वाकई लगेगा कि इस अकबरपुर को महाराणा प्रताप जैसा व्यक्तित्व ही ठीक कर सकता है, और किसी में बूता नहीं है. इस शहर में एक अति प्राचीन विद्युत उपकेंद्र है, जिसकी क्षमता है 33/11 केवीए. अकबरपुर शहर के लिए शक्ति भवन से 18 से 20 घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने का निर्देश हैं, लेकिन जर्जर अवस्था को प्राप्त अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र के सभी फीडर ओसीबी और अन्य उपकरण निष्प्रयोज्य से हो चुके हैं, जिसके कारण शक्ति भवन द्वारा निर्धारित समयानुसार विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है. अकबरपुर में लोकल फॉल्ट के चलते कुल मिलाकर बमुश्किल 10 से 12 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पाती है. ट्रान्सफार्मर जलना, केबिल, तार, जम्पर आदि में त्रुटियां आने पर अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारी समझ ही नहीं पाते कि गड़बड़ी कैसे ठीक हो. हालत यह हो चुकी है कि जरा सी हवा चली नहीं और बूंदा-बांदी हुई नहीं कि बिजली आपूर्ति ठप्प. पूछने पर कहा जाता है, ब्रेक डाउन है, फॉल्ट ढूंढा जा रहा है.

यहां के लोग पवन एवं वरूण देव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि इस क्षेत्र पर कम ही हो. अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात विद्युतकर्मियों की संख्या अपर्याप्त बताई जाती है जो हैं भी, उनकी शारीरिक बनावट ऐसी नहीं है कि खम्भों पर चढ़कर तार-केबल ठीक कर सकें, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए सहायक रख रखे हैं और उन्हीं सहायकों से सारा काम कराया जाता है. उच्चाधिकारियों को छोड़कर बीच के जितने भी अधिकारी/कर्मचारी हैं, उन्हें उपभोक्ताओं की समस्या से कोई लेना-देना नहीं रहता. चाहे कहीं केबिल टूटकर गिरे या ट्रान्सफार्मर से आग लगे, उनकी बला से. ये लोग समय-समय पर विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों में अपना योगदान दिखाकर उच्चाधिकारियों से अपनी पीठ थपथपवा कर कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं. विद्युत उपभोक्ता कितनी समस्याओं से जूझ रहा है, इन्हें इससे कुछ लेना-देना नहीं होता है. अकबरपुर शहर की सड़कों के अलावा विभिन्न गली मोहल्लों में चलना जान जोखिम में डालने के समान है. यहां से गुजरने वालों के सिर पर हर समय मौत मंडराती रहती है. मौत का खतरा और कुछ नहीं बल्कि जगह-जगह पुराने घोसलों की तरह उलझे पड़े जर्जर विद्युत तार हैं. तार टूटकर कब किसके सिर पर गिर जाए और एक बड़े हादसे का सबब बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं और कई लोग इन जर्जर तारों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं. शॉर्ट-सर्किट होना, तारों का आपस में सटकर दगना यह तो प्रायः होता ही रहता है. यह स्थिति देखकर प्रतीत होता है कि बदहाली का यह सिलसिला कभी नहीं थमेगा. गली-कूचों से

गुजरने वाले यही प्रार्थना करते गुजरते हैं कि किसी तरह सही-सलामत अपने गन्तव्य तक पहुंच जाएं, बस. अकबरपुर शहर को विद्युत आपूर्ति करने वाला कम्पोजिट मेन फीडर प्रायः निष्प्रयोज्य हो जाया करता है. कभी तार टूटना, जम्पर उड़ना और कभी लो-वोल्टेज या शून्य वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता आजिज आ चुके हैं. इस फीडर से लगभग तीन किलो मीटर लंबे क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है, जाहिर सी बात है कि टीपीएमओ के अभाव में यदि कहीं भी लोकल फॉल्ट आई, तो पूरा शहर विद्युत-विहीन हो जाता है. विद्युत कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान का हाल यह है कि वे टीपीएमओ क्या बला है, इस बारे में आम लोगों को कुछ नहीं बता पाते. अकबरपुर में विद्युत कर्मियों की जो फौज है वह विद्युत गड़बड़ियां तलाशने के बजाय धन तलाशने में अधिक लगी रहती है. कुल मिलाकर अकबरपुर के लोगों का बिजली के बिना बुरा हाल है.

गौरतलब है कि गत वर्ष सरकार के निर्देश पर चलाए गए विद्युत चोरी रोको अभियान में इस जिले ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए लक्ष्य से कई गुना अधिक की वसूली की थी. विद्युत चोरी रोको और बकाया राजस्व वसूली अभियान में यह जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा. विभाग की इस उपलब्धि से जिले का नाम रौशन हुआ और इसके लिए जिले के हाकिम को पुरस्कृत भी किया गया. राजस्व वसूली में अव्वल आने के बाद भी इस विभाग का कोई हाल पूछने वाला नहीं है. उपकरणों की बात तो दूर, तार, केबिल, इन्सुलेटर तक का यहां अकाल है. कहीं गड़बड़ी आने पर एक मीटर तार की भी जरूरत पड़ी, तो इसके लिए लाइनमैनों को प्राइवेट ठेकेदारों का सहारा लेना पड़ता है. ऐसे में इस विभाग की स्थिति कब और कैसे सुधरेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार का आंकड़ा ही कर रहा समाजवाद का पर्दाफाश

यूपी में दलित-उत्पीड़न सबसे अधिक

एसआर दारापुरी (पूर्व आईपीएस)

उत्तर प्रदेश दलितों (अनुसूचित-जाति) पर अपराध के मामले में पूरे देश में काफी समय से आगे रहा है. इस सम्बन्ध में एक यह तर्क दिया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी (4 करोड़ 13 लाख) दूसरे सभी राज्यों से अधिक है. अतः अपराध के आंकड़े भी अधिक ही रहते हैं. इस तर्क में कुछ सच्चाई है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा वर्ष 2014 के लिए दलितों के विरुद्ध हुए अपराध सम्बन्धी जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के विरुद्ध अपराध बहुत अधिक हैं, खास कर संगीन अपराध.

वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में दलितों के विरुद्ध 8075 अपराध हुए थे, जो देश में दलितों के विरुद्ध कुल घटित अपराध (47064) का 17.2 प्रतिशत और कुल संज्ञेय अपराध का 19.5 प्रतिशत रहा है. उपरोक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में दलितों की 245 हत्याएं हुईं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के विरुद्ध घटित कुल अपराध (744) का 33 प्रतिशत था. वर्ष 2014 में अपहरण के 383 मामले हुए जो इस अवधि में पूरे देश में दलितों के विरुद्ध घटित कुल घटित अपराध (758) का 51 प्रतिशत था. उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं को विवाह के लिए विवश करने के इरादे से 270 अपहरण हुए थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के विरुद्ध घटित इन मामलों की संख्या (427) का 63 प्रतिशत था. वर्ष 2014 के दौरान उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं पर बलात्कार के 459 मामले हुए, जो राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के विरुद्ध घटित कुल अपराध (225) का 20 प्रतिशत था. इससे स्पष्ट है कि दलित महिलाओं पर बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में काफी अधिक हैं. उपरोक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं पर बलात्कार के प्रयास के 32 मामले हुए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दलित महिलाओं के विरुद्ध घटित कुल अपराध का 36 प्रतिशत था. वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 254 मामले हुए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के विरुद्ध घटित कुल अपराध का 30 प्रतिशत था. उपरोक्त अवधि में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करने के 32 मामले हुए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के विरुद्ध घटित कुल अपराध का 22 प्रतिशत था. इसी अवधि में दलित महिलाओं पर दुष्कर्म के लिए हमला करने के 427 अपराध हुए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के विरुद्ध घटित कुल अपराध (2354) का 18 प्रतिशत था. उत्तर प्रदेश में दलितों के विरुद्ध बलवे के इस दरम्यान 342 मामले हुए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर घटित कुल अपराध (1147) का 30 प्रतिशत था.

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में दलितों के विरुद्ध घटित अपराध खास करके हत्या और महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि इसकी दर राष्ट्रीय स्तर पर घटित अपराध से बहुत ज्यादा है. दलितों पर अपराध के उपरोक्त आंकड़े वह हैं, जो पुलिस द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन यह यथार्थ से परे हैं. वास्तविकता यह है कि पुलिस में जो अपराध लिखे जाते हैं वे कुल घटित अपराध का थोड़ा हिस्सा ही होते हैं, क्योंकि यह सर्वविदित है कि दलित तथा अन्य कमज़ोर वर्गों पर घटित होने वाले अधिकतर अपराध तो दर्ज ही नहीं किए जाते. इसका एक मुख्य कारण है पुलिस अधिकारियों की जातिवादी मानसिकता और दूसरा है अपराध के आंकड़ों को कम करके दिखाना. इसका एक अच्छी उदहारण यह है कि 2014 में दलितों के जो मामले ऊपर दिखाए गए हैं, उनमें 1500 मामले धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अदालत के आदेश से दर्ज किये गए थे, क्योंकि इनको पुलिस ने थाने पर दर्ज करने से मना कर दिया था. बहुत से मामले ऐसे होते हैं, जिनमें लोग विभिन्न कारणों से थाने में रिपोर्ट लिखाने ही नहीं जाते हैं. इस प्रकार सरकारी आंकड़े दलितों के विरुद्ध कुल घटित अपराध को नहीं दिखाते हैं.

उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जहां पर दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, में दलितों पर होने वाले उत्पीड़न के अपराध खास करके संगीन अपराध सबसे अधिक हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. एक तो वैसे ही समाजवादी सरकार का अब तक का रवैया दलित विरोधी ही रहा है. इसका सबसे बड़ा उदहारण यह है कि थानों पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति में 21 प्रतिशत का आरक्षण होने के बावजूद थानों पर उनकी बहुत कम नियुक्ति की गई है, जिसका सीधा प्रभाव दलितों सम्बन्धी अपराध के पंजीकरण पर पड़ता है. हाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया है कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए मुख्यमंत्री तथा जिला स्तर पर निर्धारित अवधि में की जाने वाली समीक्षा बैठक बिल्कुल नहीं की जा रही है, जिस कारण दलितों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम तथा उनकी अदालतों में की जाने पैरवी की कार्यवाही समुचित ढंग से नहीं की जा रही है. यह बात निश्चित है कि यदि दलितों के प्रति समाजवादी सरकार का यही रवैया रहा, तो उनको इसका खामियाजा अगले चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसान बर्बाद, जय समाजवाद!

पृष्ठ 17 का शेष

भंडारण किया है कि कोल्ड स्टोर से आलू निकलेगा, तो उन्हें जगह मिल जाएगी या फिर आलू बिक जाएगा. पर कई कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने यह कह कर उन्हें सकते में डाल दिया है कि वे बीच में आलू नहीं रखेंगे. ऐसी हालत पूरे प्रदेश में है. लेकिन राज्य सरकार आलू किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही और न सरकारी कोल्ड स्टोरेज खोलने या बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को काम में लाने के कोई उपाय ही किए जा रहे हैं. इस प्रदेश के साथ विडंबना यह है कि बम्पर पैदावार होने के बाद भी आलू किसान मौत के ही दहलीज़ पर खड़ा है. आलू किसानों ने मुनाफे की उम्मीद में आलू की खेती का रकबा बढ़ा दिया था, लेकिन अब उन्हें इसका पछतावा हो रहा है. कौड़ियों के भाव में आलू बेचना अब उनकी मजबूरी बन गई है.

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि सरकार को अपना वायदा निभाते हुए लागत मूल्य में 50 प्रतिशत जोड़कर आलू की कीमत देने और किसानों की जिदंगी बचाने के लिए मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों के हॉटकुक मील, सरकारी कैंटीन और औद्योगिक कैंटिन जैसे तमाम कामों के लिए आलू खरीदने का सरकारी आदेश जारी करना चाहिए. किसानों को मौजूदा हालत में राहत देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए. सरकार को किसानों की कर्ज-माफी और उनके कर्ज वसूली पर रोक लगानी चाहिए और जिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू संरक्षित है उन्हें बिजली बिल में सब्सिडी देनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों से मजाक कर रही यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विभिन्न मंचों से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन में लगे किसानों का हौसला बढ़ाने के तमाम बयान देते रहते हैं, लेकिन ये बयान असलियत में धोखा है. इस धोखेबाजी का आधिकारिक दृश्य देखिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये के बजट में दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए महज 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. यह प्रदेश के लोगों के साथ और दुग्ध उत्पादन के जद्दोजहद में लगे किसानों के साथ कितना भद्दा मजाक है. इस भद्दे मजाक का और वीभत्स पहलू यह है कि स्वचालित दुग्ध संचय (ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन) के लिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने मात्र तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. है न प्रदेश के लोगों के साथ फूहड़ मजाक! ■

मेंथा की खेती में भी बर्बादी

नकदी फसल के रूप में मेंथा की खेती में उत्तर प्रदेश का बाराबंकी और रुहेलखंड का दुनियाभर में नाम था, लेकिन मेंथा किसानों को भी बर्बाद करने की साजिश हो रही है. इस बार मेंथा किसानों को मेंथा का गलत बीज देकर उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया. किसानों को एक एकड़ में जहां 80 लीटर मेंथा का तेल हासिल हो पाता था, गलत बीज की सप्लाई के कारण मेंथा का उत्पादन एक एकड़ में 80 के बजाय मात्र 20 लीटर पर पहुंच गया. किसान बताते हैं कि उन्हें लाल प्रजाति के बजाय हरी प्रजाति के बीज दे दिए गए जिससे मेंथा के उत्पादन में भीषण ह्रास हो गया. एक एकड़ में मेंथा लगाने में किसान को न्यूनतम 40 हजार रुपये की लागत आती है. लेकिन उन्हें इसके एवज में क्या मिला? यह उनकी दुर्दशा देख कर खुद ब खुद पता चल जाता है. किसान इसे जर्मनी की सिंथेटिक मेंथा ऑयल का बाजार चलाने की साजिश का हिस्सा मानते हैं. उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में कॉमर्शियल खेती के रूप में मेंथा की खेती तेजी से विकसित हुई थी. मेंथा किसान दो फसलों के बीच में खेत खाली रहने की अवस्था में मेंथा पैदाकर आमदनी करते थे. मेंथा से पैदा हुए पिपरमेंट के तेल का खरीद रेट हजार से 12 सौ और 15 सौ रुपये प्रति लीटर है. इस बार बाराबंकी से लेकर रुहेलखंड तक किसानों को मेंथा उत्पादन में बड़े पैमाने पर घाटा हुआ है. दरअसल किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ. उन्हें कोसी प्रजाति का बीज जिसे लाल बीज भी कहते हैं, उसके नाम पर जो बीज दिया गया वह हरा बीज निकला, इसके परिणाम स्वरूप जहां एक एकड़ में किसान का 80 लीटर तेल उत्पादन होता वह महज 20 लीटर तेल ही उत्पादित हुआ. इसके कारण किसान की 40 हजार रुपये लागत भी नहीं निकल पाई. नतीजतन, किसान भीषण कर्ज में फंस गया. अखिलेश सरकार ने किसानों के साथ भद्दा मजाक करते हुए तीन लाख करोड़ के बजट में तिलहन विकास के लिए महज 3.55 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके बजाय सरकार किसानों को बेहतर बीज ही उपलब्ध करा देती, तो मेंथा के किसानों के मरने की नौबत नहीं आती. वे किसी तरह आजीविका चला लेते.

उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अजीब किस्म की साजिश चलती है और सरकार इसके प्रति आंखें मूंदे रहती है. जर्मनी में बना सिंथेटिक मिंट उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में मेंथा की खेती करने वालों के लिए नुकसान का कारण बन रहा है. सिंथेटिक मिंट ने पिछले कुछ वर्ष में बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है. इस वजह से देसी मेंथा मिंट की मांग घट गई है. मेंथा ऑयल की कीमत कभी आसमान पर होती थी. मेंथा की खेती में तकरीबन 30-35 फीसदी कमी आ गई है. यूपी के किसान परेशान हैं. कुछ साल पहले जर्मनी में बने सिंथेटिक मिंट ने भारत के बाजार में दखल दी थी. तब यूपी में मेंथा ऑयल 15 सौ से दो हजार रुपये किलो की दर पर बिकता था. वहीं, जर्मनी में बने सिंथेटिक मिंट की कीमत लगभग छह सौ रुपये किलो थी. ऐसे में किसानों को मेंथा ऑयल कम कीमत पर बेचने पर विवश होना पड़ा. अब उन्हें मेंथा ऑयल पांच-छह सौ रुपये किलो बेचना पड़ रहा है. ऐसे में लागत वसूल न हो पाने की वजह से मजबूर किसान मेंथा की खेती छोड़ रहे हैं. जितना पैसा लगाकर वो मेंथा की खेती करते हैं, वो भी बाजार में तेल बेचकर उन्हें नहीं मिल पाता है.

मेंथा-क्षेत्र बाराबंकी के एक किसान ने बताया कि वे हर साल तीन एकड़ में मेंथा की खेती करते थे. पिछले दो साल से बाजार में मेंथा ऑयल की कीमत लगातार गिर रही है. इस वजह से इस बार सिर्फ एक एकड़ खेत में उन्होंने मेंथा उगाई. वहीं खड़े एक अन्य किसान कहते हैं कि वे पहले दो हजार रुपये किलोग्राम तक मेंथा ऑयल बेचते थे. अब इसकी कीमत मुश्किल से छह सौ रुपये किलो मिल रही है. पहले कंपनियां मेंथा उगाने वाले किसानों को खोजती थीं, लेकिन अब उल्टे किसानों को ही कंपनियां खोजनी पड़ रही हैं. आइपीएफ के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर आशंका जाहिर करते हैं कि गन्ना किसानों के बाद उत्तर प्रदेश में आलू और मेंथा किसानों की आत्महत्याओं का दौर बढ़ेगा, इसे समय रहते रोकना सरकार का पहला और प्राथमिक कर्त्तव्य होना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नाम पर कहां जा रहे करोड़ों रुपये

न सड़क दुरुस्त, न डिवाइडर, फिर कैसे रुके हादसा

अखिलेश्वर पांडेय

सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन करता है, लेकिन इसके लिए परिवहन विभाग या सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को क्या करना है उस पर वे संजिदगी नहीं दिखाते हैं. सड़क सुरक्षा के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकारों के करोड़ों रुपये बजट पास करने के बावजूद सड़कों की हालत वैसी की वैसी ही है और न ही दुर्घटनाओं में कोई कमी आती दिख रही है. एक्सप्रेस-वे से लेकर शहीद पथ या अन्य-हाइवे पर रोज दुर्घटाएं हो रही हैं, जिनकी वजह सामने आई है कि कहीं गलत डिवाइटर बनाया गया है, तो कहीं एक्सप्रेस-वे को ही संकरा कर दिया गया है. जिसके कारण तेजी से आते वाहनों के आपस में टकराने से कई जिंदगियां समाप्त हो रही हैं. सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग के अधिकारी इससे भी बेखबर हैं. सड़क सुरक्षा के तहत पास हुए बजट को कैसे और कहां खर्च करना है, इस पर अभी तक किसी योजना को विस्तार नहीं दिया जा सका है.

प्रदेश सरकार ने अकेले सड़क सुरक्षा के लिए 2015-16 के लिए 25 करोड़ रुपये पास किए हैं, लेकिन इस बजट से अभी तक सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं किया गया है. बस पैसे की आपसी बंदरबांट हो रही है.

वहीं सड़क सुरक्षा की ब्रैंड एंबेसडर मुख्य सचिव की पत्नी सुरभि रंजन सड़क सुरक्षा के प्रति काफी जागरूकता दिखा रही हैं, लेकिन महज भाषणबाजी में. पिछले दिनों संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से गोमतीनगर स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में शिरकत करने के दौरान सुरभि रंजन ने यातायत नियमों को लेकर खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया. कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई. कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त के. रवींद्र नायक ने कहा कि हर साल केवल यूपी में ही विभिन्न कारणों के चलते होने वाले वाहन दुर्घटना में तकरीबन 16 हजार लोगों की असामयिक मृत्यु होती है. जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा प्रति वर्ष डेढ़ लाख तक है. वहीं घायलों की संख्या लाखों में है. हम सभी को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है. सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों का पालन कानून के डर से नहीं बल्कि स्वप्रेरित होते हुए इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए. कार्यक्रम के दौरान लघु फिल्मों द्वारा लोगों को यह दिखाने की कोशिश की गई कि वाहन चलाते समय नशे से दूर रहें, सीलट बेल्ट लगाएं, मोबाइल का प्रयोग न करें, तेज गति में वाहन न चलाएं व हमेशा हेल्मेट का प्रयोग करें. परिवहन विभाग समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नेट ऑन करने की जहमत नहीं उठाते अधिकारी

परिवहन निगम के अधिकारियों ने मोबाइल पर इंटरनेट न ऑन करने के पीछे तर्क दिया है कि परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से हर महीने इंटरनेट के खर्च के नाम पर 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन हर महीने मोबाइल का बिल 1200 से 1300 रुपये तक आ रहा है. ऐसे में 300 से ऊपर का बिल उन्हें खुद ही अपनी जेब से भरना पड़ता है. यही वजह है कि अब मोबाइल फोन पर नेट ऑन करने में हिचकिचाहट होती है. निगम के कई अधिकारियों ने बताया कि जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल न करने से कंट्रोल कमांड सेंटर पर अधिकारियों की लोकेशन ले पाना भी संभव नहीं है. ■

रोड सेफ्टी क्लब की होगी स्थापना

परिवहन आयुक्त के रवींद्र नायक ने बताया कि दुर्घटनाओं का आंकडा शून्य करने के के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं व अध्यापकों को यातायात नियमों की जानकारी देने व उनका पालन करने के प्रति जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना की जाएगी. इन स्कूलों में यातायात नियमों को बताया जाएगा साथ ही सड़क पर चलने के दौरान वाहन किस तरह से चलाएं, हेल्मेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जेब्रा क्रासिंग पार न करें जैसे नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना के बाद एक रोड सेफ्टी फेडरेशन स्थापित किया जाएगा. ■

एआरटीओ महानगर को न कार्यक्रम का आमंत्रण और न सूचना

संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से सड़क सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम कहां, कब और कितने से कितने बजे तक होना है इसकी जानकारी व आमंत्रण विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर बाबू और कर्मचारियों तक को दी गई लेकिन महानगर कार्यालय की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को इस बाबत आमंत्रण तो दूर कोई जानकारी भी उपलब्ध कराने की जहमत नहीं उठाई गई. इस मामले पर जब उप परिवहन आयुक्त अरविंद पांडेय से जानकारी ली गई, तो उन्होंने इसकी जानकारी न होने की बात कही. ■

कूड़ा हो रहा है करोड़ों रुपये का कंट्रोल कमांड सेंटर

बसों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, रोडवेज अधिकारी एसी कमरों को छोड़कर बसों की चेकिंग करने बाहर निकलें, वर्कशाप में किसी तरह का कोई घपला न हो, डिपो से डीजल चोरी न हो, समेत कई अन्य उद्देश्यों को लेकर करोड़ों रुपये खर्च कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंधन ने निगम मुख्यालय पर सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की थी. सेंटर से सभी अधिकारियों की लोकेशन लेने के लिए उनके मोबाइल फोन को जीपीएस सिस्टम के माध्यम से सेंटर से जोड़ा गया था, जीपीएस के जरिए ही अधिकारियों की लोकेशन ट्रैक की जाती थी. जो अधिकारी बसों की चेकिंग करने नहीं निकलता था उसे प्रबंधन की ओर से फटकार लगाई जाती थी, जिससे धीरे-धीरे अधिकारी तो सुधरने लगे ही यात्रियों को भी सुविधा मिलने लगी. लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका. एमडी का तबादला हुआ और सारी तकनीकी धरी रह गई. अधिकारियों ने खुद को कामचोरी में व्यस्त कर लिया. हकीकत यह है कि मुख्यालय पर तीन महीने पहले स्थापित किया गया सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अब तकनीकी के बजाय सिर्फ दिखावे के लिए ही रह गया है. ■

ऋतु भूषण संभालेंगी खंडूड़ी की राजनीतिक विरासत

चौथी दुनिया ब्यूरो

सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी की पुत्री ऋतु भूषण खंडूड़ी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगी, इस बात का साफ इशारा उनके समाज सेवा में बढ़ते कदम से लगाया जा रहा है. दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके खंडूड़ी एक ईमानदार जनसेवक के साथ चरित्र की पूर्ण परिभाषा से परिभाषित राजनेता हैं. इनकी भी दिली इच्छा है कि बेटी बढ़े. अभी ऋतु भूषण अपनी संस्था के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा की भावना से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. जनरल पिता के गोद में खेल कर बढ़ी आईएएस पति के साथ खुशहाल जीवन के साथ उन्होंने कहा कि केदारघाटी के आपदा पीड़ित बड़ासू गांव को गोद लेने की पहल की जा रही है. उनकी पवित्र मंशा है कि आपदा से तंग लोगों में खुशहाली लाई जाए, उनका सकल्प है कि गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयाय किया जाए. उनका ध्यान प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा सिर्फ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान पर है. वह कहती हैं कि यदि कभी मौका मिलेगा तो वह राजनीति में आने के बारे में विचार करेंगी. उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान अपनी संस्था के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर है. अभी लोगों को संस्था से जोड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि पौड़ी जिले के थलीसैण ब्लॉक के मझोली गांव को उनकी संस्था ने गोंद लिया है. गांव में मत्स्य विकास, फूल उत्पादन समेत अन्य कार्य किए जा रहे हैं. साथ ही गांव की शिक्षा व्यवस्था पर भी संस्था की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आपदा के बाद रुद्रप्रयाग जिले की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है. खासकर केदारघाटी में काफी नुकसान पहुंचा है. कई मां-बहनों का आसरा छिन गया है. उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ित देवली-भणिग्राम को उनके पिता ने गोद लिया है. इसी प्रकार वह भी आपदा पीड़ित बड़ासू गांव को गोद लेने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि गांव को गोद लेने का मुख्य उद्देश्य यहां की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है. ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि उनकी संस्था के मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक विकास, बाल एवं महिला स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, छात्र-छात्राओं को ऐसी शिक्षा से जोड़ना, जो रोजगार का भी जरिया बने. गरीब एवं समाज के उपेक्षित वर्ग को विभिन्न योजनाओं से जोड़ना एवं कृषि, उद्यान, डेरी विकास, शिक्षा, महिला शैक्षिक उत्थान व ग्रामीण विकास संस्था का अहम उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है. ऋतु भूषण राजनीति में अपने पिता को अपना आदर्श मानती हैं, इनकी मंशा है कि राजनीति की गंगा से भी प्रदूषण समाप्त करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

नेताजी से देहरादून का गहरा नाता

रेनू शर्मा

देहरादून से नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मौत के विवाद का पुराना और गहरा नाता है. नेताजी की मौत की जांच के लिए गठित जस्टिस मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देहरादून के स्वामी शारदानंद का जिक्र किया था. जस्टिस एम के मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में देहरादून के आयाम को जोड़ते हुए साफ तौर पर महान संत और तपस्वी स्वामी शारदानंद और नेताजी सुभाष में गहरा नाता बताया था. इनके शिष्य साफ तौर पर कहते हैं कि स्वामी जी सुभाष नहीं थे. यह जरूर है कि स्वामी शारदानंद भी इस मत के समर्थक थे कि नेताजी जी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई है. ध्यान योग्य है कि तपस्वी एवं संत स्वामी शारदानंद लंबे समय तक उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी व देहरादून में रहे. यहीं पर ही इन्होंने शरीर त्यागा और इनका अंतिम संस्कार भी मायाकुंड ऋषिकेश में किया गया. उत्तरप्रदेश की पुलिस ने इनको सम्मान के साथ विदाई दी थी. इनके पार्थिव शरीर को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में देहरादून से ऋषिकेश ले जाया गया था. 14 अप्रैल 1977 को स्वामी शारदानंद ने जब शरीर छोड़ा, इस समय इनके शिष्यों के दो ग्रुपों में आपसी विवाद हो गया था, जो लोग इन्हें नेताजी सुभाष मानते थे वे इनके पार्थिव शरीर का संस्कार करना चाहते थे. पार्थिव शरीर इन लोगों के पास था, जो इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्वामी शारदानंद मानकर चलते थे. नेताजी की आजाद हिंद फौज में रहे कर्नल प्रीतम सिंह ने इनके भक्तों का पक्ष लिया तब जाकर यह मामला शांत हुआ था. दून का राजपुर क्षेत्र हमेशा से संतों व तपस्वियों का तपोस्थल रहा है. यहां पर महान तपस्वी व अंतर्मुखी संत स्वामी शारदानंद ने भी अंतिम कुछ वर्ष बिताए थे. सरकार इन पर शक करती रही कि वे ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस हैं. आजाद हिंद फौज से जुड़े लोग भी इसी मत के समर्थक रहे. अब जबकि नेताजी के 1945 के बाद भी जीवित होने की बात सामने आई है, तो एकाएक स्वामी शारदानंद जी का जिक्र होना लाजिमी है. उत्तराखंड के लोग भी इस बात को लेकर हैरत में हैं कि दिवगंत संत सुभाष बाबू नहीं थे, फिर इनकी षव यात्रा में सरकार ने पुलिस लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों और किसके इशारे पर किया. ■

दुष्यंत कुमार का नया एल्बम यार सिंदूरी लॉन्च

चौथी दुनिया ब्यूरो

एमफॉरयू म्यूजिक एक बार फिर मेलोडियस गानों के साथ नई एल्बम लेकर आया है. यार सिंदूरी नाम की इस नए एल्बम को 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक संगीत समारोह में लॉन्च किया गया. यार सिंदूरी एल्बम के साथ अनुज गुप्ता ने संगीत जगत में कदम रखा है. एल्मब में संगीत दुष्यंत कुमार ने दिया है. दुष्यंत पहले ही भी कई म्यूजिक एल्बम और धारावाहिकों में संगीत दे चुके हैं. अपनी इस नए एल्बम के बारे में दुष्यंत का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस एल्बम को बनाया है. उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य संगीत से पैसा कमाना नहीं है. हम संगीत के लिए समर्पित हैं. हम चाहते हैं कि ऐसा संगीत बनाएं, जो लोगों को मीठा लगे, अच्छा लगे. इस एल्बम की रिकॉर्डिंग मुंबई के जानेमाने फैट बॉम्स स्टूडियो में हुई है. यह मीत ब्रदर्स का स्टूडियो है.

यार सिंदूरी से अनुज गुप्ता को लॉन्च करने पर दुष्यंत ने कहा कि वह बेहद प्रतिभाशाली गायक हैं वह संगीत जगत में बहुत तरक्की करेंगे. इस एल्बम में पांच गीत हैं सभी गीतों को अनुज ने अपनी आवाज दी है गीतों में उनका साथ फिल्म जगत की जानी मानी पार्श्वगायिका जसविंदर नरूला, सुगंधा मिश्रा, इंद्राणी भट्टाचार्य आदि ने दिया है. अनुज गुप्ता ने अपनी सधी हुई आवाज के साथ पार्श्वगायिकी के क्षेत्र में दस्तक दी है. उन्होंने अन्य दिग्गज गायकों के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए एक जादुई समन्वय प्रस्तुत किया है. एल्बम के गीत रितु सिंह ने लिखे हैं, जबकि एल्बम का वीडियो निर्देशन सिद्धान्त तिवारी ने किया है.

इस एल्बम के बारे में जसपिंदर नरूला का कहना है कि बड़े दिनों बाद मैंने कोई मैलोडियस गीत गाया है. मैं रिकॉर्डिंग के दौरान इतना खो गई थी केवल एक टेक में यह गीत रिकॉर्ड हो गया. बतौर एक्टर पहचानी जाने वाली सुगंधा मिश्रा ने भी एल्बम में अपनी आवाज दी है. सुगंधा का अपनी गायकी के बारे में कहना है कि वह फिल्म जगत में अपनी पहचान बतौर गायिका बनानी चाहती हैं, लेकिन उन्हें गाने के पर्याप्त मौके नहीं मिल पा रहे हैं. लेकिन यार सिंदूरी जैसे एल्बम से ही मैं गायकी और अपनी पहचान बना सकती हूं. इसमें गीत और संगीत दोनों ही बेहतरीन हैं. अनुज ने जसपिंदर नरूला के साथ गायन के अनुभव को अपने जीवन का बेहतरीन अनुभव बताते हुए कहा कि ऐसे मंझे हुए कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इस तरह के कलाकारों के साथ काम करने से विश्वास बढ़ता है. अनुज ने बताया कि जसपिंदर ने अपने अनुभव मुझसे बांटे और गायकी की कई बारीकियों से रूबरू करवाया. इसका सीधा फायदा मुझे भविष्य में मिलेगा. बहुत जल्द ही दुष्यन्त अपने एल्बम के गायकों के साथ एमफॉरयू इंटरटेनमेंट के संयोजन में इंडिया टूर पर निकल रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड क्रांति दल की एकता में सत्ता ही बाधक

राजकुमार शर्मा

दो धड़ों में बंटे उत्तराखंड क्रांति दल की एकता में सत्ता प्रतिष्ठान ही बाधक बना हुआ है. काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट व त्रिवेंद्र सिंह रावत की त्रिकोणीय राजनीति न तो समानांतर दिशा तय कर पा रही है और न इनमें लय ताल का मेल है. प्रत्यक्ष तौर पर वर्ष 2007 के बाद सत्ता से जुगलबंदी ने उत्तराखंड क्रांति दल के तेवर ढीले कर दिए. 2007 में चुनकर आई त्रिशंकु विधानसभा में उक्रांद की बैशाखी का सहारा लेकर भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई. सत्ता में सहयोगी के रूप में उक्रांद कोटे से शामिल किए गए दिवाकर भट्ट व संगठन के वरिष्ठ लोगों के संबंध कड़वे हो गए. सत्ता के लिए भाजपा का ऐसा प्रयोग तो सफल रहा किंतु उक्रांद की भावी राजनीति के लिए घातक. 2012 के विधानसभा चुनावों में उक्रांद के एक मात्र विधायक के चुनकर आने के पीछे राष्ट्रीय दल भाजपा से जुगलबंदी माना गया. कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की तरफ से की गई तत्कालीन टिप्पणियों से इस बात को बल मिलता है. वर्ष 2012 में फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बसपा व निर्दलीय विधायकों के साथ उक्रांद ने कांग्रेस की सत्ता की बैशाखी बनना पसंद किया. सत्ता में जुगलबंदी के बाद मौजूदा हालात 2007 की ही तरह हैं. विधायक के नाते प्रीतम सिंह पंवार सत्ता में सहयोगी बन गए, दल के भीतर अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर नेताओं के बीच संघर्ष छिड़ गया, जो अब भी जारी है. दल की राजनीति को प्रभावित करने वालों में काशी सिंह ऐरी, राज्य सरकार की नीति नियोजन समिति में दायित्वधारी हैं जबकि विधायक प्रीतम सिंह पंवार हरीश रावत सरकार में कैंबिवेट मंत्री हैं. पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट भी हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं. जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत दल की कमान थामे रखना चाहते हैं. मौजूदा समय में ऐरी व भट्ट दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी रजामंदी पर उक्रांद की एकता टिकी हुई है, सत्ता प्रतिष्ठान से दोनों की करीबी एकता की राह में बाधक बनी हुई है. दल को एक मंच पर आने में जितनी देरी होगी, आगामी विधानसभा चुनावों में उक्रांद के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती. उक्रांद नेताओं के स्वार्थ सिद्धी से राज्य की जनता की जो हानी हो रही है वह इन नेताओं के समझ से अब तक परे है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विश्लेषण करने से यह भी पता चल रहा है कि प्रदेश में हर 13 परिवारों में से एक सदस्य सचिवालय में चपरासी के रूप में काम करना चाहता है. जिन नौकरियों की योग्यता कक्षा पांच पास व साइकिल चलाने की अनिवार्यता हो वहां पर भी कम से कम दो लाख महिलाओं व लगभग चार सौ किन्नरों के आवेदनों ने रिकार्ड कायम कर दिया है. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करने से अब प्रशासन के समक्ष सिरदर्द पैदा हो गया है. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी समस्या 386 पदों के लिए जो आवेदन आए हैं, उनकी छंटाइ कैसे की जाए और सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कैसे लिए जाएं.

बेरोजगारी की महामारी से त्रस्त उत्तर प्रदेश

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक देश के अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं. वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही हैं और भाजपा के सर्वाधिक 71 सांसद भी उत्तर प्रदेश से ही जीतकर पहुंचे हैं. लगभग सभी दल गरीबी हटाओ व विकास का नारा बुलंद करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंच हैं, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज प्रदेश का बुरा हाल है.

मृत्युंजय दीक्षित

यह बात सभी दलों और विकास की बात करने वाले लोगों का पता है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक, समाजिक व आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है. साथ ही उनको यह भी पता है कि विकास की संभावनाओं की दृष्टि से भी यह कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक अधिकांश समय तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं. वह सब उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं. वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही हैं और सर्वाधिक 71 सांसद भी भाजपा के ही जीतकर संसद में पहुंचे हैं. लगभग सभी दल गरीबी हटाओ व विकास का नारा बुलंद करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंच हैं, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज प्रदेश का बुरा हाल है. 1990 के बाद से प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई हैं, उन सभी के कारण आज प्रदेश विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ता जा रहा है. वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश में युवाओं के सपने लगातार खाक होते जा रहे हैं. आज प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती तादाद महाविस्फोट का रूप लेती जा रही है. बेरोजगारों में कुंठा और निराशा का गहन अंधकार बढ़ता जा रहा है. विगत दिनों प्रदेश में आयोजित लेखपाल की परीक्षा में दो लाख से कुछ अधिक लोगों ने परीक्षा दी.

जबकि सचिवालय की परीक्षा में 386 चपरासी पद के लिए 23 लाख 80 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन करके इतिहास रच दिया है. सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चपरासी पद के लिए न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास है, लेकिन कुल आवेदकों में इनकी संख्या न्यूनतम है. इन आवेदकों में पाचवीं पास की संख्या मात्र 50 हजार है. वहीं कक्षा छह से आठ के बीच के अभ्यर्थी 1.60 लाख हैं. इसके बाद पीएचडी के 255, बीटेक, परास्नातक के 24969 और स्नातक के 152730 और शेष कक्षा आठ से ऊपर वाले हैं. जिसमें इंटर पास आवेदकों की संख्या सात लाख पचास हजार तीन सौ सतहत्तर है. जबकि 2681 लोगों ने अपनी योग्यता का उल्लेख तक नहीं किया है.

विश्लेषण करने से यह भी पता चल रहा है कि प्रदेश में हर 13 परिवारों में से एक सदस्य सचिवालय में चपरासी के रूप में काम करना चाहता है. जिन नौकरियों की योग्यता कक्षा पांच पास व साइकिल चलाने की अनिवार्यता हो वहां पर भी कम से कम दो लाख महिलाओं व लगभग चार सौ किन्नरों के आवेदनों ने रिकार्ड कायम कर दिया है. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करने से अब प्रशासन के समक्ष सिरदर्द पैदा हो गया है. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी समस्या 386 पदों के लिए जो आवेदन आए हैं, उनकी छंटाइ कैसे की जाए और सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कैसे लिए जाएं. चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा सरकार के लिए इस कदर चुनौती बनकर खड़ी हो गई है कि अब साक्षात्कार को रद्द करने व नियमावली बदलने पर भी विचार किया जा रहा है. अधिकारियों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि यदि इसी प्रारूप में साक्षात्कार लिया जाता है, तो कम से कम चार साल प्रक्रिया पूरी होने में लग जाएंगे.

आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो दंश महामारी के रूप में फैल रहा है उसका चिंतन सम्पूर्ण समाज को करना चाहिए. राजनीति करने वाले व निवेश करके नए उद्योग व कल-कारखाने लगाने वाले उद्योगपतियों व व्यापारियों को भी यह चिंतन अवश्य करना चाहिए कि आखिर प्रदेश में बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए.

आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं. प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट, बिगड़ती जा रही कानून-व्यवस्था और खासकर व्यपारियों के मन में सुरक्षा को लेकर व्याप्त चिंता के कारण प्रदेश में निवेशकों का भरोसा उठ गया है. एक ओर जहां पुराने उद्योग व कल कारखाने तेजी से बंद हो रहे हैं तथा उनको खोलने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में निवेशक व्यापार करने के लिए आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं. बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि प्रदेश के अधिकांश युवा सनातक, परास्नातक और पीएचडी की उपाधि तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश के पास पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण का अभाव होता है. अधिकांश लोग सरकारी नौकरियां पाने के चक्कर में फॉर्म पर फॉर्म भरते चलते जाते हैं. लेखपाल व अन्य सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में आवेदनों के पहुंचने से यह भी पता चल रहा है कि युवाओं में सरकारी नौकरियों के लिए अभी भी आकर्षण है, लेकिन इस आकर्षण के पीछे भी हिंदुस्तानी परिवारों में एक बड़ी बात यह घर कर गई है कि सरकारी कर्मचारी मोटी सैलरी लेते हैं. ऊपर से भ्रष्टाचार व दलाली की रकम भी पाते हैं. काम के प्रति लापरवाही रहती है. खूब अवकाश मिलता है तथा काम न करने का मन हो, तो बीमारी व अन्य किसी व्यक्तिगत कारणों से भी आप अवकाश लेकर खूब मजे कर सकते हैं. एक प्रकार से लोगों ने सरकारी नौकरी को आराम और कमाने का बेहतरीन जरिया बना लिया है. यही कारण है कि अब सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व आलसीपन कर्मचारियों की रगों में दौड़ रहा है. आज प्रदेश में युवाओं को लुभाने के लिए भारी तादाद में नौकरियां निकाली भी जा रही हैं, लेकिन सभी नौकरियों की भर्ती में भयंकर धांधली हो रही है तथा न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है.

जिस वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तथा शिक्षित व अशिक्षित बेरोंजगारों में भविष्य के प्रति चिंता के बादल उमड़ रहे हैं. सभी दल मिशन-2017 की तैयारी में लगे हैं, लेकिन प्रदेश का युवा बेरोजगार भी अगली बार सत्तारूढ़ दल को सबक सिखने की तैयारी में जुट गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो दंश महामारी के रूप में फैल रहा है उसका चिंतन सम्पूर्ण समाज को करना चाहिए. राजनीति करने वाले व निवेश करके नए उद्योग व कल-कारखाने लगाने वाले उद्योगपतियों व व्यापारियों को भी यह चिंतन अवश्य करना चाहिए कि आखिर प्रदेश में बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए. आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं.

चपरासी की नौकरी ने दिखाया आईना

प्रभाकर

यूपी को सरकारी विज्ञापनों में कभी देश का उत्तम प्रदेश होने का दावा किया जाता था, लेकिन यहां चपरासी के पद पर भर्ती के लिए निकले सरकारी विज्ञापन के जवाब में दाखिल हुए आवेदनों ने राज्य में सुशासन और बेरोजगारी की कलई खोल दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह 368 पदों पर चपरासियों की भर्ती के लिए विज्ञापन छपवाया था, लेकिन उसके जवाब में मिलने वाले आवेदनों ने सरकारी अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं. इन पदों के लिए 23 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं. लेकिन इससे भी हैरत वाली बात यह है कि इनमें ढाई सौ पीएचडी धारकों के अलावा भारी तादाद में इंजीनियिर व पोस्टग्रैजुएट की डिग्री वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं. यह कहना ज्यादा सही होगा कि चपरासी की यह नौकरी राज्य में बेरोजगारी की स्थिति का आईना बन गई है. यह तो पहले से ही साफ था कि शिक्षा के स्तर, रोजगार और विकास के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत भी पड़ोसी बिहार जैसी ही बदतर है. सत्ता में आने के बाद नेताओं का बैंक बैलेंस तो लगातार बढ़ता गया, लेकिन राज्य की हालत बद से बदतर होती गई. बीते विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी (सपा) की भारी जीत के बाद राज्य की कमान जब अखिलेश यादव जैसे युवा मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपी गई थी, तो खासकर युवा तबके में उम्मीद जगी थी. उसे लगा था कि एक युवा मुख्यमंत्री शायद बेरोजगारी का दर्द समझ कर उस दिशा में ठोस पहल करेगा. लेकिन हुआ उसका बिल्कुल ही उल्टा. अखिलेश सरकार के दौरान हालात बदतर ही हुए हैं. एक ओर जहां शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, वहीं दूसरी ओर यादव सिंह जैसे एक इंजीनियर के पास से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का बरामद होना और उसे सत्तारुढ़ पार्टी के नेताओं का संरक्षण हासिल होना विकास की अपनी कहानी खुद कहता है. कुछ महीने पहले बिहार में बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले अभिभावकों की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं. उत्तर प्रदेश की तस्वीर उससे अलग नहीं है. दरअसल, जातीय राजनीति ने इस राज्य का कबाड़ा कर दिया है. इन राज्यों में अब राजनीति ही रातों-रात करोड़पति बनने का शार्टकट है. नतीजतन छात्र पढ़ाई-लिखाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. राज्य में सत्ता में आई सपा हो या उसके पहले सत्तारूढ़ रही बसपा, सबने राज्य के विकास के बजाय निजी हितों को साधने पर ज्यादा ध्यान दिया. उत्तर प्रदेश के छात्रों की शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है कि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी नहीं मिलती. अस्सी के दशक तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रशासनिक परीक्षाओं की फैक्टरी कहा जाता था. हर साल वहां से दर्जनों लोग आईएएस बनते थे. लेकिन उस विश्वविद्यालय को भी राजनीति ने अपनी चपेट में ले लिया. यही वजह है कि राज्य से पीएचडी और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले छात्र अब चपरासी की नौकरी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं. चपरासी के जिस पद पर भर्ती होनी है उसकी योग्यता तो महज पांचवीं पास है, लेकिन वेतन सोलह हजार रुपये है. यही वजह है कि बेरोजगारी से जूझ रहे तमाम डिग्रीधारी मधुमक्खी की तरह उस पर टूट पड़े हैं. सरकारी अधिकारियों की मानें, तो महज इंटरव्यू के आधार पर होने वाली इस नियुक्ति में चार साल का समय लग सकता है. तब तक तो बेरोजगारों की एक नई जमात तैयार हो जाएगी. उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर एक भयावह संकेत है. येन-केन-प्रकारेण सत्ता हासिल करने और फिर उस पर पकड़ बनाए रखने की कोशिशों में जुटे राजनीतिक दलों के लिए भी यह खतरे की घंटी है. लेकिन इससे सबक लेकर तस्वीर का रुख बदलने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है. ■

भत्ते का धोखा, अब भर्ती की ठगी

सुशील कुमार सिंह

समाजवादी पार्टी जबसे सत्ता में आई है, उसने प्रदेश में बेरोजगारों (जिसकी यूपी में भारी तादाद है) के साथ केवल धोखा देने का काम किया. पहले तो उसके साथ बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखाधड़ी की गई, उसके बाद विभिन्न किस्म की नौकरियों का विज्ञापन निकाल कर उसे ठगा गया. कैसे? इसका दृश्य आप खुद ही देख लीजिए-

1- समाजवादी सरकार ने केवल धन उगाहने के लिए फर्जी भर्तियां निकालीं और जातीय आरक्षण के अनुसार शुल्क जमा करवाया जैसे सामान्य के लिए 500 रुपये तो ओबीसी के लिए 250 वगैरह, वगैरह.

2- प्रदेश के सभी जिलों से भर्तियां निकालीं और हर जिले से फॉर्म भरने की छूट दी गई, जिससे बेरोजगार युवाओं ने कर्जा ले लेकर कई-कई जिलों से फॉर्म भर डाले. इस लालच में कि कहीं से तो कॉल आ जाए. हर फॉर्म के साथ हर जिले में 500/- और 250/- रुपये जमा किए गए. इस चक्कर में एक-एक युवक ने 2000 से 4000 रुपये तक सरकार के खजाने में डाल दिए.

3-जितनी भी भर्तियां निकली, समाजवादी सरकार ने सुनियोजित तरीके से लगभग सभी में कुछ न कुछ कानूनी गड़बड़ियां कीं और खुद ही अपने एजेंटों से कोर्ट में मुकदमा दायर करवा के उसे अधर में लटकवा दिया. प्रदेश का बेरोजगार तो मारा गया.

4-सभी विभागों में इसी तरह से भर्तियां निकाली गईं कि उससे खूब पैसे इकट्ठे हुए, दो नम्बरी रास्ते से अलग से वसूले गए, न कोई भर्ती हुई, न भर्तियां निरस्त हुईं और न ही बेरोजगारों का पैसा वापस हुआ.

5-बेबस लाचार गरीब बेरोजगारों ने लोन, उधार, रेहन, गिरवी वगैरह के जरिए पैसे का इंतजाम करके फॉर्म भरे थे, लेकिन किसी भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और पैसा अलग से डूब गया.

6-कई नौकरियों की पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर से नए पद के लिए उसी विभाग में भर्ती निकाल दी गई. फिर दोबारा लूट हुई. उसका परिणाम मुकदमा कायम होने की वजह से निलंबित पड़ गया. यह काम सपा ने जान-बूझकर किया.

7- लाखों के कर्ज में डूबे इन बेरोजगारों की कोई मदद को तैयार नहीं है. इनकी पुकार आखिर कौन सुनेगा?

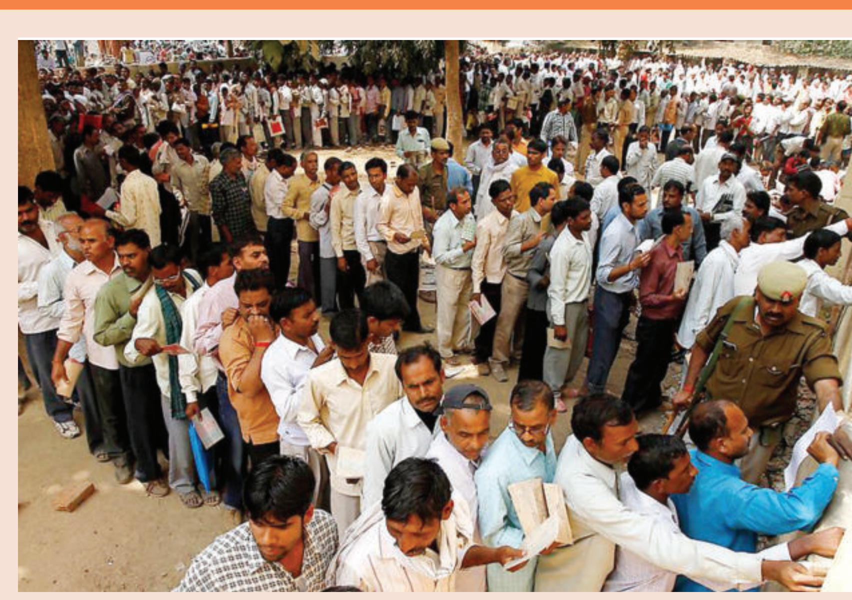

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

05 अक्टूबर-11 अक्टूबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

महागठबंधन की चुनौती

दुश्मनी छोड़ दोस्ती करनी होगी

फोटो-**प्रभात पाण्डेय**

जदयू की जीती हुई 27 सीटों पर इस बार राजद के उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस के 12 स्थानों पर. पिछले चुनाव में इन सीटों पर राजद और कांग्रेस का जदयू के साथ जोरदार मुकाबला हुआ था. राजद के 72 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे और कांग्रेस के 27. लेकिन इस बार दोस्त और दुश्मन बदल गए हैं. लोजपा एनडीए के साथ है तो जदयू राजद के साथ. मतलब चुनाव की पूरी केमेस्ट्री ही बदल गई है. चुनावी आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में जदयू के 34 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जीत का अंतर 20 हज़ार से ज्यादा था.

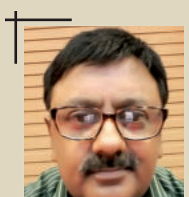

सरोज सिंह

पहले चरण के मतदान के लिए बिहार का चुनावी रणक्षेत्र सज-धज के तैयार है. रथियों और महारथियों की लंबी फौज एक-दूसरे का राजनीतिक वध करने के लिए गांडिव उठाए युद्धभूमि में तैयार बैठी है. इस महासमर में कौन पांडवों की सेना है और कौन कौरवों की, यह पहचानना मुश्किल हो रहा है. जीत का शंखनाद किस खेमे से होगा, इसका फैसला तो अगले एक महीने में बिहार की जनता कर देगी. लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात काबिलेग़ौर है कि बिहार विधानसभा की कई ऐसी सीटें हैं, जहां कई योद्धा उन्हीं के सीने में तीर भेदते हुए नज़र आ रहे हैं, जो 2010 के चुनाव में उनके साथ थे. इसके अलावा इससे भी बड़ी बात यह हो रही है कि पिछले चुनाव में जिन्होंने जिस महारथी को चुनावी अखाड़े में पछाड़ा था, बदले हुए राजनीतिक हालात में वे दोनों अब एक ही ख़ेमे में आ गए हैं. लिहाज़ा यह सवाल लाख टके का है कि क्या पिछली हार का जख्म भूलकर ये नेता अपने नए दोस्त को विजयश्री दिलाने के लिए रात-दिन एक कर देंगे और कहीं ऐसा नहीं हो पाया तो यकीन मानिए बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे. 2010 के चुनाव पर ग़ौर करें तो जदयू ने पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस बार उसने जीती हुईं 39 सीटें तालमेल में राजद और कांग्रेस को दे दी हैं.

जदयू की जीती हुई 27 सीटों पर इस बार राजद के उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस के 12 स्थानों पर. पिछले चुनाव में इन सीटों पर राजद और कांग्रेस का जदयू के साथ जोरदार मुकाबला हुआ था. राजद के 72 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे और कांग्रेस के 27. लेकिन इस बार दोस्त और दुश्मन बदल गए हैं. लोजपा एनडीए के साथ है तो जदयू राजद के साथ. मतलब चुनाव की पूरी केमेस्ट्री ही बदल गई है. चुनावी आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में जदयू के 34 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जीत का अंतर 20 हज़ार से ज्यादा था.
 दस हजार से अधिक और 20 हजार से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या 44 थी. जबकि पांच हजार से अधिक और दस हजार से कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या 17 थी. जदयू के ऐसे 15 उम्मीदवार थे, जो पांच हज़ार के कम अंतर से जीते.

पिछले चुनाव के यही आंकड़े जदयू और राजद के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं. इसके अलावा अभी हाल में ही संपन्न स्थानीय निकाय चुनाव में भी इसकी झलक मिली. पटना स्थानीय निकाय चुनाव में यादव प्रतिनिधियों ने जदयू के वाल्मीकि सिंह की बजाय स्वजातीय निर्दलीय प्रत्याशी रीतलाल यादव का साथ दिया. इसी तरह छपरा सीवान और गोपालगंज में भी जदयू और राजद के वोटर एक साथ दिल से नहीं हो पाए और तीनों की तीनों सीट भाजपा के खाते में चली गई. राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पटना में तो महागठबंधन हो गया पर सबसे जरूरी है कि जमीन पर तीनों दलों का महागठबंधन हो. ऐसा अगर नहीं हुआ तो पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है क्योंकि समय काफी कम बचा है और अभी ऊपर के स्तर पर भी तस्वीर बहुत साफ नहीं है इसलिए इस बात की गारंटी देना जल्दबाजी होगी कि राजद का बेस वोट बैंक जदयू को और जदयू का बेस वोट बैंक राजद को खुले दिल से मदद करेगा. जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो राजद की तुलना में जदयू को इसका ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है. राजद के वैसे प्रत्याशी जो पांच हजार से भी कम अंतर से हारे हैं वो दिल से जदयू को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में तो कुछ ने तीसरे मोर्चे का दामन थाम लिया है. इसलिए यह मान कर चला जा रहा है कि राजद और जदयू का पूरा का पूरा वोट एक-दूसरे के प्रत्याशियों को मिलना बहुत ही मुश्किल है. इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि महागठबंधन के नेताओं ने शुरू से ही एकजुटता का संदेश देने में झिझक दिखाई. पोस्टरों पर केवल और केवल नीतीश नज़र आए. राहुल गांधी की सभा में न लालू गए और न ही नीतीश. इस तरह के राजनीतिक प्रयोगों का महागठबंधन के वोटरों पर प्रतिकूल असर पड़ा.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

2010 में जदयू का जिनसे हुआ मुकाबला

पांच हजार से कम अंतर से जीत

क्षेत्र	दूसरे स्थान	दल	वोट अंतर
शिवहर	प्रतिमा देवी	बसपा	1631
सुरसंड	जयनन्दन यादव	राजद	1186
बाजपट्टी	अनवारुल हक	राजद	3420
मनिहारी	गीता किस्कू	एनसीपी	4165
बहादुरपुर	हरिनारायण शती	राजद	443
कुढ़नी	विजेंद्र चौधरी	लोजपा	1570
बरुराज	रामविचार राय	राजद	4916
परसा	चन्द्रिका राय	राजद	4689
हसनपुर	सुनील कुमार पुष्पम	राजद	3291
चेरिया बरियापुर	अनिल चौधरी	लोजपा	1061
सुल्तानगंज	रामऔतार मंडल	राजद	4845
नाथनगर	अबू कैसर	राजद	4727
बरबीघा	अशोक चौधरी	कांग्रेस	3047
मोहनिया	निरंजन राम	राजद	2525
चेनारी	ललन पासवान	राजद	2901
गोह	राम अयोध्या यादव	राजद	694
इमामगंज	रौशन कुमार	राजद	1211

पांच से आठ हजार के बीच जीत

क्षेत्र	दूसरे स्थान	दल	वोट अंतर
नरकटिया	साबिर अली	लोजपा	7688
हरलाखी	राम नरेश पाण्डेय	भाजपा	6659
मीनापुर	मुन्ना यादव	राजद	5402
मांझी	हेम नारायण सिंह	राजद	7904
मोरवा	अशोक सिंह	राजद	6850
बेलहर	रामदेव यादव	राजद	7616
शेखपुरा	सुनीला देवी	कांग्रेस	7342
मसौढ़ी	अनिल कुमार	लोजपा	5032
मखदुमपुर	धर्मराज पासवान	राजद	5085
शेरघाटी	सुषमा देवी	निर्दलीय	6503
नवादा	राजवल्लभ प्रसाद	राजद	6337
वारिसलीगंज	अरुणा देवी	कांग्रेस	5428

एक नज़र

चुनावी हलचल

राघोपुर और महुआ में होगी महागठबंधन की परीक्षा

वैशाली में एनडीए एवं महागठबंधन की असली चुनावी परीक्षा होगी. तीसरे मोर्चे के रूप में समाजवादी गठबंधन भी खेल बिगाड़ने को तैयार है. ज्ञात हो कि वैशाली चुनाव तीसरे चरण में होना तय हुआ है. हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन से कांग्रेस के खाते में है. इस सीट पर जहां भाकपा माले भी अपना उम्मदीवार उतार रही है. राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सतीश कुमार यादव, जिन्होंने पिछले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था, तेजस्वी यादव से मुकाबला करेंगे. वहीं भाकपा माले के रामबाबू भारती का भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. महुआ विधानसभा में मुख्य मुकाबला राजद के तेजप्रताप यादव एवं हम पार्टी के रविन्द्र राय के बीच है. यहां भाकपा के विश्वनाथ विप्लवी, गरीब आदमी पार्टी के डॉ. सुमन सिन्हा, बहुजन समजावादी पार्टी के अशोक क्रांति, एसडीपीआई के उम्मीदवार रियाज अहमद, एसयूसीआई के ललित कुमार घोष ने भी जनसम्पर्क अभियान शुरू कर दिया है. महनार से डॉ. अच्युतानन्द को कड़ी टक्कर भाकपा के रंजीत पंडित एवं राजापाकर विधानसभा से महागठबंधन के शिवचन्द्र राम को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं पातेपुर से भाजपा के महेन्द्र बैठा तथा माले के राजेश पासवान को उम्मीदवारी मिली है. बताया जाता है कि जिले में महुआ और राघोपुर सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है. जहां राघोपुर के कार्यकर्ताओं में सतीश को जदयू से टिकट नहीं मिलने से घोर असंतोष था. अंततः उन्हें भाजपा में शामिल होना पड़ा. बताते चलें कि जिले में राघोपुर, पातेपुर, एवं महनार सीट भाजपा को गयी है वहीं बाकी सीटों पर लोजपा, रालोसपा एवं हम के प्रत्याशी महागठबंधन से दो-दो हाथ करेंगे. *– नसीम रब्बानी*

पर्यावरण सह पुस्तक प्रदर्शनी

शिवम् क्लासेज एवं साई-शिवम् पब्लिक स्कूल, कुर्जी, दीघा, पटना के सौजन्य से बोरिंग रोड स्थित 'श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क के मेनगेट पास दो दिवसीय 'पर्यावरण सह पुस्तक प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर महंत हनुमान शरण कॉलेज, के प्रचार्य डॉ. विमलनारायण आर्य तथा कथाकार डॉ. लालजीप्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से किया. उक्त अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए प्रचार्य डॉ. विमल नारायण आर्य ने कहा कि इस 'पर्यावरण सह पुस्तक प्रदर्शनी' में एक ही लेखक डॉ. लालजी प्रसाद द्वारा लिखित 40शीर्षक की किताबें रखी गई हैं और इन्हीं द्वारा लगाए गए एलोवेरा, सिन्दूर, लौंग-तुलसी, अडेनियम, शमी-प्लांट, मनीप्लांट, रबर प्लांट, फुटबॉल लीली, करोटन, सुदर्शन, लेमनग्रास, रजनीगंधा, मेंहदी, ओड़हुल, आशोक, बेल, जामुन, इलाहाबादी अमरूद, आम इत्यादि सैकड़ों किस्म के फल-फूल एवं औषधीय पौधे यहां लाए गए हैं. डॉ. आर्य ने 'पुस्तकों एवं पौधों के ताल-मेल' पर तथ्य को स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि पौधे पर्यावरण को शुद्ध करते हुए हमारे स्वास्थ्य को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं और साहित्यिक पुस्तकें हमारे लिए 'मेंटलथेरेपी'का काम करती हैं. प्रदर्शनी में मुख्य रूप से प्रो. आरएस तिवारी, प्रो. बीके राय, प्रो. सीडी सिंह, प्रो. रंजना कुमारी, प्रो. संजय ठाकुर, प्रो. पंकज कुमार, मनोज कुमार, उपेन्द्र कुमार, प्रो. नवीन कुमार, प्रो. मीरा कुमारी, दीपक कुमार, रीना सिन्हा, चितरंजननारायण आर्य, छोटन राय, इत्यादि उपस्थित रहे.■ *–चौथी दुनिया ब्यूरो*

गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा है जरूरी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
Dr.NAHID FATIMA
DGO, Gynaecologist

Carbo-XT Drops Susp.
A Colic Drops
Siliplex Syp.
Oflogyl-OZ Susp.
Acobna Syp.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

मगध

एनडीए-महागठबंधन में सीधा मुकाबला

जीतन राम मांझी | प्रेम कुमार | सुरेंद्र यादव | कौशल यादव | उदय नारायण चौधरी

भाजपा ने मगध में आधी से अधिक सीटें अपने सहयोगी दलों को दी हैं. फिर भी वह फायदे में है. 26 में से 14 सीटें लोजपा, रालोसपा तथा हम के लिए दी हैं. जबकि 12 सीटों पर भाजपा लड़ रही है. जबकि 2010 तथा इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में जदयू-भाजपा का गठबंधन था तो भाजपा मात्र 10 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और जदयू 16 सीटों पर. इस हिसाब से बदले समीकरण में मगध में भाजपा को लाभ हुआ है तो जदयू को पांच सीटों का नुकसान. अब वह मात्र 11 सीटों पर लड़ने को मजबूर है. इस बार चुनाव में मगध में सबसे बड़ी परीक्षा पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा नेता जीतनराम मांझी को होगी.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

पूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव में मगध के 26 क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा. वर्तमान कई विधायकों का टिकट कटने तथा टिकट नहीं मिलने से बागी कई नेताओं द्वारा चुनाव मैदान में निर्दलीय खड़े होने या फिर भितरघात किये जाने दोनों ही गठबंधनों के प्रत्याशियों के परेशान होने की आशंका दिख रही है.

भाजपा ने मगध में आधी से अधिक सीटें अपने सहयोगी दलों को दी हैं. फिर भी वह फायदे में है. 26 में से 14 सीटें लोजपा, रालोसपा तथा हम के लिए दी हैं. जबकि 12 सीटों पर भाजपा लड़ रही हैं. जबकि 2010 तथा इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में जदयू-भाजपा का गठबंधन था तो भाजपा मात्र 10 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और जदयू 16 सीटों पर. इस हिसाब से बदले समीकरण में मगध में भाजपा को लाभ हुआ है तो जदयू को पांच सीटों का नुकसान. अब वह मात्र 11 सीटों पर लड़ने को मजबूर है. इस बार चुनाव में मगध में सबसे बड़ी परीक्षा पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा नेता जीतनराम मांझी की होगी. अचानक महादलितों के सबसे बड़े नेता के रूप उभरे मांझी दो क्षेत्रों, मखदुमपुर तथा इमामगंज, सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. इमामगंज से 2000 से जदयू से लगातार विधायक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से जीतनराम मांझी का मुकाबला है. लोगों की नजर इस सीट पर लगी हुई है. 2005 के फरवरी में चुनाव के दौरान यहां से लोजपा के टिकट पर लड़ रहे पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी. तबसे यह क्षेत्र से और चर्चित हो गया. जदयू के दो बागी विधायक चर्चित पूर्व सासंद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार घोसी तथा जहानाबाद के रालोसपा के सांसद डॉ. अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार टिकारी से हम से चुनाव लड़ रहे हैं. लोगों की नजर इन दोनों सीटों पर लगी है. यहां से जदयू ने गया जिला जदयू अध्यक्ष अभय कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है. नये समीकरण में जदयू ने अपने दो बागी विधायकों के अलावा पांच का टिकट काट दिया है जिसमें गया जिले के अतरी से कृष्ण नन्दन यादव, बाराचट्टी से ज्योति मांझी, जहानाबाद से अभिराम शर्मा, कुटुम्बा सुरक्षित से ललन राम तथा नवादा से पूर्णिमा देवी शामिल हैं. अतरी विधानसभा क्षेत्र से हत्या के मामले में सजा काट रहे बाहुबली पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव की पत्नी पूर्व विधायक कुन्ती देवी को राजद ने प्रत्याशी बनाया है. एनडीए ने यहां से लोजपा प्रत्याशी के रूप में अपने युवा नेता अरविन्द कुमार सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है. नवादा जिले के गोविन्दपुर के जदयू विधायक कौशल यादव को क्षेत्र बदल कर हिसुआ से जदयू प्रत्याशी बनाया है. वहीं उनकी पत्नी नवादा की जदयू विधायक पूर्णिमा देवी को गोविन्दपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है. भाजपा ने भी अपने दो वर्तमान विधायकों का भी टिकट काट दिया है. नवादा जिले के रजौली सुरक्षित क्षेत्र से वर्तमान विधायक कन्हैया कुमार का तथा गया जिले के गुरुआ से सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा का टिकट काट कर नये प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है. कांग्रेस मगध की पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वजीरगंज से कांग्रेस ने अपने पुराने नेता और पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह को पुनः चुनाव मैदान में उतारा है. यहां से भाजपा के विरेन्द्र कुमार सिंह से उनका मुकाबला है. 2010 की चुनाव में अवधेश सिंह दूसरे स्थान पर थे. मगध की चर्चित क्षेत्रों में गया जिले का बेलागंज भी हैं. 1990 से लगातार जीत रहे राजद के डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव का इस बार हम के प्रत्याशी शारिम अली से मुकाबला है. गया शहर से 1990 से लगातार जीत रहे भाजपा के पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार का कांग्रेस प्रत्याशी से तथा वाम मोर्चा के भाकपा के मसउद मंजर से है. औरंगाबाद से लगातार विधायक रहे भाजपा के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी से है. नवीनगर से चुनाव लड़ रहे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह पर भी लोगों की नजर है. यहां जदयू के वर्तमान विधायक वीरेन्द्र सिंह से मुकाबला है. बोधगया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से राजद के 2005 में चुनाव में इमामगंज में मारे गये लोजपा नेता और पूर्व सासंद स्व. राजेश कुमार के पुत्र पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत को प्रत्याशी बनाया है. ये हाल ही में लोजपा छोड़ राजद में शामिल हुए हैं. मगध मे सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा एनडीए के नेताओं की हैं. रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, पूर्व सासंद जगदीश शर्मा, सांसद सुशील कुमार सिंह, केन्द्रीय मंत्री नवादा के भाजपा सांसद गिरिराज सिंह सरीखे नेता, मगध क्षेत्र की आगवानी करने का दावा करते हैं. एनडीए से भाजपा 12, हम से 7, रालोसपा 4 तथा लोजपा के 3 प्रत्याशी मगध के क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. महागठबंधन से जदयू 11, राजद 10 तथा कांग्रेस 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खडा किया है. अब देखना है कि महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक तथा अगड़ी जातियों में मतदताओं को बांटने वाले नेता अपने-अपने दलों के प्रत्याशियों को अपनी जाति व जमात का कितना वोट दिला पाते हैं.■

कांग्रेस मगध की पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वजीरगंज से कांग्रेस ने अपने पुराने नेता और पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह को पुनः चुनाव मैदान में उतारा है. यहां से भाजपा के वीरेन्द्र कुमार सिंह से उनका मुकाबला है. 2010 के चुनाव में अवधेश सिंह दूसरे स्थान पर थे. मगध के चर्चित क्षेत्रों में गया जिले का बेलागंज भी है. 1990 से लगातार जीत रहे राजद के डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव का इस बार हम के प्रत्याशी शारिम अली से मुकाबला है. गया शहर से 1990 से लगातार जीत रहे भाजपा के पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार का कांग्रेस प्रत्याशी से तथा वाम मोर्चा के भाकपा के मसउद मंजर से है.

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

दुश्मनी बदले दोस्ती में तभी बनेगी बात

विधानसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और इसी हां और न वाली स्थिति ने भाजपा गठबंधन को आगे निकलने का मौका दे दिया है. जानकार बताते हैं कि जो हालात इलाके में बन रहे हैं, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की सलाह पार्टी के शीर्ष नेताओं को रोज दी जा रही है पर न जाने क्यूं इस पर कारगर पहल अब तक नहीं हो पाई है. पहले चरण के मतदान में अब काफी कम वक्त बचा है और महागठबंधन के लिए जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता की खुराक पिला दी जाए. जब तक राजद और जदयू के नेताओं की दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदलेगी तब तक भाजपा गठबंधन से मुकाबले में जमीन पर वह कमजोर नजर आएंगे. लेकिन अगर एक बार दिल से राजद और जदयू के कार्यकर्ता आपस में मिल गए तो यकीन मानिए बिहार भीषण राजनीतिक महासमर का गवाह बनेगा ही बनेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

तेघड़ा एवं मटिहानी में कांटे का संघर्ष

राजद ने लालू यादव की सरकार के महाधिवक्ता रहे रामबालक महतो के पुत्र वीरेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है. वीरेंद्र कुमार राजनीति का नया चेहरा हैं. राजनीति के क्षेत्र में वीरेंद्र कुमार की पहचान कम है, लेकिन महागठबंधन में शामिल जदयू एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेंगे. इस क्षेत्र के 144795 पुरुष एवं 123735 महिला मतदाता 12 अक्टूबर को 254 मतदान केन्द्रों पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

सुरेश चौहान
feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 12 अक्टूबर को होने वाले मतदान पर न सिर्फ बेगूसराय के अलावा सबकी नजर जिले के तेघड़ा एवं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र पर होगी. तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजग का वाममोर्चा एवं मटिहानी में महागठबंधन के साथ कड़ा मुकाबला होगा. तेघड़ा भाकपा का गढ़ रहा है, लगातार 48 वर्षो तक तेघड़ा सीट पर भाकपा का कब्जा रहा है. 2010 के चुनाव में पहली बार भाजपा-जदयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी. इस बार भी राजग ने भाजपा को यह सीट दिया है, भाजपा ने इस बार निवर्तमान विधायक ललन कुंवर की जगह पार्टी के चर्चित सिपहसालार राम लखन सिंह को टिकट दी है. रामलखन सिंह भाजपा के कर्मठ एवं वरिष्ठ नेता हैं. जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने भाजपा की पैठ काफी मजबूत बनाई. संघ की उपज राम लखन युवाओं के काफी चहेते हैं. इसी के साथ राम लखन को लोजपा एवं रालोसपा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. दूसरी ओर वाममोर्चा ने भाकपा के कर्मठ नेता राम रतन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है. राम रतन सिंह काफी लोकप्रिय वामपंथी नेता हैं. उन्हें सहयोगी दल माकपा एवं माले का समर्थन प्राप्त होगाय यह काफी रोचक मुकाबला होगा. जीत जिसकी भी हो, काफी वर्षो बाद बीहट को पुनः विधायक मिलेगा क्योंकि दोनों प्रत्याशी बीहट के ही निवासी हैं. महागठबंधन ने तेघड़ा विधानसभा सीट राजद को दिया है. राजद ने लालू यादव की सरकार के महाधिवक्ता रहे रामबालक महतों के पुत्र वीरेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है. वीरेंद्र कुमार राजनीति का नया चेहरा है. राजनीति के क्षेत्र में वीरेंद्र कुमार की पहचान कम है. लेकिन महागठबंधन में शामिल जदयू एवं कांग्रेस के कार्यकर्त्ता पूरा सहयोग करेंगे. इस क्षेत्र के 144795 पुरूष एवं 123735 महिला मतदाता 12 अक्टूबर को 254 मतदान केन्द्रो पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

बोगो सिंह | रामलखन सिंह | रामरतन सिंह | सर्वेश सिंह

बहुचर्चित मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है. इस सीट पर जदयू के नेता नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह का पिछले तीन चुनाव से कब्जा है. इस बार भी महागठबंधन ने बोगो सिंह को ही चुनाव मैदान में उतारा है. उन्हें कांग्रेस एवं राजद का समर्थन प्राप्त होगा, बोगो सिंह से मुकबले के लिए राजग ने भाजपा के सर्वेश कुमार को मैदान में उतारा है. सर्वेश कुमार काफी लोकप्रिय तथा भारत सरकार के लोक सेवक पद पर कार्यरत थे.

दूसरा बहुचर्चित मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है. इस सीट पर जदयू के नेता नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह का पिछले तीन चुनाव से कब्जा है. इस बार भी महागठबंधन ने बोगो सिंह को ही चुनाव मैदान में उतारा है. उन्हें कांग्रेस एवं राजद का समर्थन प्राप्त होगा, बोगो सिंह से मुकबला के लिए राजग ने भाजपा के सर्वेश कुमार को मैदान में उतारा है. सर्वेश कुमार काफी लोकप्रिय तथा भारत सरकार के लोक सेवक पद पर कार्यरत थे. अपने स्थानीय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं होने से व्यथित सर्वेश कुमार ने जनसेवा क्षेत्र में उतरने का निर्णय लिया और लोक सेवक पद से त्यागपत्र दे दिया. 2010 के चुनाव में मटिहानी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और (लगभग 17 हजार) मत प्राप्त किए, बाद में भाजपा की नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. भाजपा को एक कुशल जननेता एवं सर्वेश कुमार को मजबूत जनाधार मिला. सम्प्रति वे समग्र गंगा अभियान के संयोजक है. इन्हें लोजपा एवं रालोसपा का भी समर्थन प्राप्त होगा. मटिहानी विधानसभा सीट पर कभी भाकपा का लाल झंडा लहराता था. इस बार वाममोर्चा ने यह सीट भाकपा को दिया है. भाकपा ने एक तीर से दो शिकार करते हुए दलित वर्ग की महिला प्रत्याशी शोभा पासवान को चुनाव मैदान में उतारा है. सीट पर कब्जा जमाने के लिए भाकपा, माकपा कोई कसर नहीं छोड़ेगा. इस क्षेत्र के 163767 पुरूष एवं 140095 महिला मतदाता 12 अक्टूबर को क्षेत्र के 288 मतदान केन्द्रो पर मतदान करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी-शिवहर

बागी बिगाड़ देंगे चुनावी गणित

वाल्मीकि कुमार
feedback@chauthiduniya.com

आगामी चुनावों के मद्देनजर इसका आंकलन करना होगा कि सीतामढ़ी-शिवहर में दोनों प्रमुख गठबंधनों की स्थिति क्या होगी? पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में सीतामढ़ी और शिवहर जिले में किस गठबंधन को कितना फायदा और किसे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? अगर हम पिछले चुनाव पर गौर करें तो सीतामढ़ी की कुल 8 और शिवहर के 1 विधानसभा सीट यानि कि 9 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा क्रमशः बेलसंड, रुन्नीसैदपुर, बाजपट्टी, सुरसंड और शिवहर पर जदयू का कब्जा रहा. जहां से क्रमशः सुनीता सिंह चौहान, गुड्डी देवी, डॉ. रंजूगीता, शाहिद अली खान और मो. सरफुद्दीन बतौर विधायक निर्वाचित हुए. शेष 4 सीट सीतामढ़ी नगर से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू, रीगा से मोतिलाल प्रसाद, परिहार से राम नरेश प्रसाद यादव व बथनाहा से दिनकर राम बतौर भाजपा विधायक निर्वाचित हुए. 2015 के चुनाव में एनडीए का यह आंकडा महागठबंधन पर भारी पड़ता दिख रहा है. कारण कि अब तक गठबंधन के तहत टिकट का जो तालमेल सामने आ रहा है. उसमें एनडीए 7 सीट पर अपना प्रत्याशी देने जा रही है. इनमें भाजपा से सीतामढ़ी सीट पर सुनील कुमार पिंटू, रीगा से मोतिलाल प्रसाद, बथनाहा से दिनकर राम, परिहार से गायत्री देवी, रुन्नीसैदपुर से रालोसपा से पंकज मिश्रा, सुरसंड व शिवहर से 'हम' पार्टी से क्रमशः शाहिद अली खान व लवली आनंद के नाम की चर्चा है. जबकि बेलसंड सीट पर लोजपा व भाजपा के बीच खींचतान चल रही है. अगर यह सीट दोनों में से किसी को भी मिलता है तो यह संख्या बढकर 8 तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

गायत्री देवी | गुड्डी देवी | मंगीता देवी | मोतीलाल प्रसाद
राजेश चौधरी | शाहिद अली खान | सुनील कुमार पिंटू | पंकज कुमार मिश्र

अब इन सीटों को लेकर चल रही चुनावी चर्चा पर गौर करें तो पहली नजर में जाति और पार्टी के सामने व्यक्तित्व गौण नजर आ रहा है. सीतामढ़ी सीट से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू पांचवी बार अपना भाग्य आजमाने वाले हैं. इस सीट को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर गैर वैश्य प्रत्याशी को महागठबंधन चुनाव मैदान में लाती है तो भाजपा की बढ़त को रोकना मुश्किल साबित हो सकता है. कारण कि इस सीट पर वैश्य व सवर्ण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है. परिहार विधानसभा क्षेत्र से अबकी बार एनडीए ने बतौर भाजपा प्रत्याशी भाजपा के विधायक रहे राम नरेश प्रसाद यादव की पत्नी गायत्री देवी को उतारने की घोषणा की है. इस सीट पर यादव, वैश्य व अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच वोटों की छीना-झपटी होती रही है. प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे इस क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी हो सकते हैं. रीगा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण वैश्य व सवर्ण मतदाताओं पर टिका बताया जाता है. इस सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर अमित कुमार टुन्ना ने भाग्य आजमाया था. इस बार भी दावेदारी को लेकर प्रयासरत है. परंतु चर्चा है कि रीगा से अबकी बार पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में आने को आतुर हैं. बथनाहा सुरक्षित सीट से भाजपा विधायक दिनकर राम को टक्कर देने के लिए महागठबंधन तैयारी में हैं. सीट के लिए पार्टी का निर्णय की घोषणा बाकी है. चर्चा है कि सुरसंड से जदयू के विधायक रहे अल्पसंख्यक बिरादरी के शाहिद अली खान अब 'हम' पार्टी की टिकट पर भाग्य आजमाने वाले हैं. इनको चुनावी मात देने के लिए इनकी बिरादरी के प्रत्याशी की महागठबंधन तलाश में लगी है. यह चर्चा भी जोरों पर है कि इस बार सुरसंड से पूर्व सांसद नवल किशोर राय का पुत्र गुंजेश कुमार नवीन एवं पूर्व राजद विधायक जयनंदन प्रसाद यादव भी अपना भाग्य आजमाने वाले हैं. जबकि रुन्नीसैदपुर सीट से बेटिकट कर दी गयी जदयू विधायक गुड्डी देवी के पति राजेश चौधरी भी सुरसंड से अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में हैं.

वही दूसरी ओर रुन्नीसैदपुर से बतौर एनडीए प्रत्याशी रालोसपा के पंकज कुमार मिश्रा को चुनौती देने के लिए महागठबंधन से राजद की टिकट पर पूर्व राजद विधायक स्व. भोला राय की पुत्रवधु मंगीता देवी को उतारा जा रहा है. इस सीट से बेटिकट कर दी गयी जदयू विधायक गुड्डी देवी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच आने की ठानी है. वैसे तीसरा मोर्चा के किसी दल से टिकट मिलने की चर्चा भी जोरों पर है. बाजपट्टी सीट से जदयू विधायक डॉ. रंजूगीता को शिकस्त देने को लेकर एनडीए प्रत्याशी की तलाश में हैं. वैसे इस सीट से नानपुर प्रमुख रिंकू देवी का पति मुकेश कुमार यादव भी अपना भाग्य आजमाने को लेकर प्रयासरत हैं. शिवहर सीट से जदयू ने अपने विधायक मो. सरफुद्दीन को पुनः चुनावी समर में उतारने का मन बनाया है. अबकी बार उनको चुनौती देने के लिए एनडीए से 'हम' की टिकट पर पूर्व सांसद लवली आनंद को उतारने का फैसला लिया गया है.

अब अलग-अलग दलों के संभावित प्रत्याशियों का चुनावी बुखार का तापमान कैसा रहता है. इस पर नजर रखने की आवश्यकता है. कारण कि सीतामढ़ी व शिवहर सीट से कोई ऐसा दल नहीं जहां से एक दल के अनेक संभावित प्रत्याशी नहीं रहे हैं. परंतु गठबंधन की राजनीति के कारण फिलहाल इनका कोई चारा नहीं चल पा रहा है. अगर ऐसे बेटिकट कार्यकर्ता अपना भड़ास निकालने पर आतुर हुए तो दोनों ही गठबंधन के लिए टिकट की समस्या विकट रूप धारण कर सकता है. राजद के लालू प्रसाद के रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव का चुनावी चक्रव्यूह अगर सटीक बैठा तो महागठबंधन का सारा खेल खराब होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है. वैसे अभी टिकट वितरण का कार्य पूर्ण नही हुआ है. सीतामढी के कई सीट से महागठबंधन ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा से परहेज रखा है. सपा, बसपा, एनपीपी, राकांपा समेत कई दलों के प्रत्याशी का नाम अभी आना बाकी है. उम्मीद है सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक फाइनल चेहरा सामने होगा. ■

एक नज़र

चुनावी हलचल

महागठबंधन का मजबूत है इरादा : रमन

सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से राजद के संभावित प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि अबकी बार महागठबंधन मजबूत इरादे के साथ चुनाव मैदान में डटा है. उन्होंने कहा कि एनडीए की जुमलेबाजी से लोग तंग आ चुके है. इनका अब तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता है. जबकि राजद, जदयू व कांग्रेस के महागठबंधन के पक्ष में मतदाता गोलबंद है. चुनाव अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अगर चुनाव में तरजीह दी गयी तो अबकी बार का चुनाव नतीजा अविस्मरणीय होगा. *– विकास*

तीसरे विकल्प के रूप में एनएसए

आज की राजनीति पर चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के संयोजक सतीश प्रसाद ने कहा है कि बिहार को लालू- नीतीश ने जातियों के विकास की आड़ में अधर में धकेल दिया है. आज राज्य में घोर अराजकता फैली हुई है. अपहरण, हत्या, लूट का बोलबाला है ऐसे में तीसरे विकल्प की आवशकता बिहार के लिये अत्यावश्यक है. एनएसए बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आया है. उन्होंने आगे कहा कि एनएसए की सरकार बनती है तो हमारा अगला मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वर्ग का होगा. सतीश ने बताया कि राजग- जदयू गठबंधन बिहार की जनता का विकल्प नहीं बन सकते. यहां जनता ने एक-एक कर सबको देख लिया है. आजादी के 68 वर्षों में जहां पचासों साल तक कांग्रेस-राजद-जदयू और भाजपा ने विकास की बातें करके बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया. अब समय आ गया है कि जब उनके नेतृत्व वाली समानता दल और अशफाक रहमान के नेतृत्व वाली जनता दल राष्ट्रवादी की अगुवाई में कई राजनीतिक पार्टिया राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के बैनर तले बिहार की जनता को विकल्प दें. मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक ने अपने सम्बोधन में राजद कांग्रेस पर जंगलराज और दंगा नीति लाने का आरोप लगाया और अशफाक ने भाजपा के बारे में कहा कि बीजेपी ने इनका साथ दिया है. ■❖❖ *– चौथी दुनिया*

विकास के लिए शिक्षा-प्रणाली में बदलाव जरूरी

किसी देश के विकास का अंदाजा लगाना हो तो उस देश की प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था देखकर आप समझ सकते हैं कि इस देश की नींव, क्या है. भारत के कई राज्यों में शिक्षा व्यवस्था की हालत दयनीय है. भारत ज्यादा समतावादी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि उच्च स्तरीय शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया जाए. इसके लिए हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली की नीचे से ऊपर तक प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक स्थानीय से लेकर केंद्रीय संस्थानों और नीतियों तक की पूरी समीक्षा कर कायाकल्प करना होगा. बिहार चुनाव के बाद बनने वाली सरकार से शिक्षक क्या अपेक्षा करते हैं, जिसपर जाने-माने प्रोफसरों से चौथी दुनिया के संवाददाता रजनीकांत पाण्डेय ने बातचीत की पेश है कुछ अंश .

आने वाली सरकार से आपकी प्रमुख मांग क्या होगी? पटना विश्वविद्यालय केइतिहास विभाग के रिटायर हेड भारती एस कुमार का मानना है कि सरकार को सूबे में शांति व्यवस्था, मूलभूत सुविधा एवं शिक्षा को एक अच्छे नीति के तहत चलाना चाहिए. भारती ने बिहार के कॉलेजों और स्कूलों में हो रहें परीक्षा में नकल पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से ध्यान देने की अपील की. भारती ने महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा जोर देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की समानता और सम्मानपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता पर भी विचार करें. पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर उन्होंने कहा कि मिली जुली सरकार बनने की अधिक संभावना देखी जा रही है. वहीं पछले अठारह महीनों की नरेन्द्र मोदी के शासनकाल पर भारती बताती है कि मोदी की सरकार आने से एक उम्मीद देखी गई थी, कि अच्छे दिन आयेंगे लेकिन जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से संगठन की ओर से अभद्र बयान दिया जा रहे हैं, जिसपर मोदी जी चुपी साधे हुए हैं. युवाओं को रोजगार देने में भी कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ. भारती आगामी सरकार को सुझाव में बताती हैं कि सरकार किसी की बने लेकिन ईमानदारी से काम करे.

शशि शर्मा | भारती एस कुमार
सुनीता राय | अमरनाथ सिंह

पटना विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के पी.जी हेड शशि शर्मा आने वाली सरकार से मांगो पर उनका मानना है कि सरकार ने महिला कॉलेज के बगल में कन्वेंशन सेन्टर बना कर छात्राओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. सरकार की यह सबसे बड़ी भूल है. हिंदी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर की शिक्षा और बेरोजगारी केबारे में सरकार कोध्यान देना चाहिए. क्योंकि यह बेरोजगारी नक्सलवाद को बढ़ावा देता है. आगामी सरकार को सुझाव के सवाल पर शशी बताती है कि अच्छी शिक्षा देने पर विचार करना चाहिए जिस के लिए अच्छे शिक्षकों की बहाली होनी जरूरी है.

पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर अमरनाथ सिंह का मानना है कि सरकार को शिक्षा केलिए नए सिरे से सोचना चाहिए. अच्छे शिक्षकों की बहाली की जानी चाहिए. आरक्षण, भ्रष्टाचार पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए. बेहतर शासनकाल पर अमरनाथ का कहना है कि नीतीश की शुरूआती पांच साल अच्छा रहा है. पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की संभावना पर अमर ने एनडीए की सरकार बनने की ज्यादा उम्मीद बताई. केंद्र में मोदी की शासनकाल को उन्होंने अच्छा बताते हुए कहा प्रधानमंत्री को विदेशी मामलों से ज्यादा जरूरी है, अभी देश की समस्या पर ध्यान देना चाहिए. आने वाली सरकार को सुझाव केतौर पर अमरनाथ कहते हैं कि सरकार को बहाली प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए, गुणवक्ता वाले टीचर को बहाल करे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके पटना विश्वविद्यालय केअसिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पी.एम.आई.आर सुनीता राय ने अच्छे शिक्षकों की बहाली, विश्वविद्यालय की स्तर को बढ़ाने, फंडिंग व्यवस्था और विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता देने पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बात कहीं. सुनीता स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई, अच्छे पेमेंट देकर अच्छे टीचर नियुक्त करना, स्कूलों में मूलभूत सुविधा देने की मांग की ताकि छात्रों को गुणवक्ता वाली शिक्षा मिल सके वहीं मुख्यमंत्री की पहली पसंद को सुनीता ने नीतीश कुमार को बताया. उन्होंने कहा नीतीश केआने से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. स्पष्ट बहुमत के सवाल पर सुनीता बताती है कि अभी यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आखिर में में वोटर बदल सकते हैं. नरेन्द्र मोदी की शासनकाल पर उन्होंने बताया कि मोदी की नीतियां अच्छी है. वह अच्छा कर रहें हैं .■

-चौथी दुनिया ब्यूरो